रजिस्ट्री सं० डी (डी)-73

REGISTERED No. D(D)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 47] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 22, 1975/अग्रहायण 1, 1897
No. 47] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 22, 1975/AGRAHAYANA 1, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory orders and notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

NOTICE

The undermentioned Gazettes of India Extraordinary were Published upto the 31st July, 1975 :—

प्र०सं० Issue No.	संख्या व तिथि No. and Date	द्वारा प्रेषित Issued by	विषय Subject
225.	का०आ० 292 (अ), दिनांक 1 जुलाई, 1975	गृह मंत्रालय	का०आ० 524, तारीख 13 फरवरी, 1975 में संशोधन।
	S.O. 292 (E), dated the 1st July, 1975	Ministry of Home Affairs	Amendment in Notn. No. S.O. 524, dated the 13th February, 1967.
226.	एस० ओ० 293 (अ०), दिनांक 1 जुलाई, 1975	इस्पात और खान मंत्रालय	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के सभी राजपत्रित अधिकारियों को एल्यूमीनियम (नियंत्रण) आदेश, 1970 के अनुसरण में अधिकारों का प्रयोग।
	S.O. 293(E), dated the 1st July, 1975	Ministry of Steel and Mines	Authorises all the gazetted officers of Central Excise to use powers under clause 9 of the Aluminium (Control) Order, 1970.
227.	सा०आ० 294 (अ), दिनांक 1 जुलाई, 1975	नौवहन और परिवहन मंत्रालय	अधिसूचना सं० सा०आ० 255 तारीख 2 मई, 1975 में और संशोधन।
	S.O. 294(E), dated the 1st July, 1975	Ministry of Shipping and Transport	Further amendment in the Notn. No. S.O. 255(E), dated the 2nd May, 1975.
228.	का०आ० 295 (अ), दिनांक 1 जुलाई, 1975	केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड	इनकम टैक्स नियम, 1962 में और संशोधन करना।
	S.O. 295(E), dated the 1st July, 1975	Central Board of Direct Taxes	Rules further to amend the Income Tax Rules, 1962.

1	2	3	4
229.	का०आ० 296 (अ), दिनांक 1 जुलाई, 1975	उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय	अधिसूचना सं० का०आ० 147 (ई) दिनांक 20 मार्च, 1975 का शुद्धि पत्र।
	S. O. 296 (E), dated the 1st July, 1975	Ministry of Industry and Civil Supplies	Corrections to be made in Notn. No. S. O. 147 (E), dated the 20th March, 1975.
230.	का०आ० 297 (अ), दिनांक 3 जुलाई, 1975	गृह मंत्रालय	सुरक्षा बल अधिनियम 1968 की धारा 2 की उपधारा (i) के खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की हरियाणा राज्य में सक्रिय ड्यूटी।
	S. O. 297 (E) dated the 3rd July, 1975	Ministry of Home Affairs	The duty of every person serving in Haryana referred in clause (a) of sub-section (i) of section 2 of Border Security Force Act, 1968, is active duty.
	का०आ० 298 (अ), दिनांक 3 3 जुलाई, 1975	गृह मंत्रालय	सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 2 की उपधारा (i) के खंड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की राजस्थान राज्य में सक्रिय ड्यूटी।
	S.O. 298(E), dated the 3rd July, 1975	Do.	Duty of persons referred in clause (a) sub-section (i) of Section 2 of Border Security Force Act, 1968, serving in Rajasthan is active duty.
	का०आ० 299 (अ), दिनांक 3 जुलाई, 1975	तदैव	सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 2 की उपधारा (i) के खंड (क) में उल्लिखित व्यक्ति की वेस्ट बंगाल में सक्रिय ड्यूटी।
	S.O. 299(E), dated the 3rd July, 1975	Do.	Duty of persons, referred in clause (a) sub-section (i) of section 2 of Border Security Force Act, 1968, serving in West Bengal is active duty.
	का०आ० 300 (अ), दिनांक 3 जुलाई, 1975	तदैव	सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 2 की उपधारा (i) के खंड (क) में उल्लिखित व्यक्ति की बिहार में सक्रिय ड्यूटी।
	S.O. 300(E), dated the 3rd July, 1975	Do.	Duty of persons, referred in clause (a) sub-section (i) of section 2 of Border Security Force Act, 1968, serving in Bihar is active duty.
	का०आ० 301 (अ), दिनांक 1 जुलाई, 1975	तदैव	सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 2 की उपधारा (i) के खंड (क) में उल्लिखित व्यक्ति की दिल्ली में सक्रिय ड्यूटी।
	S.O. 301(E), dated the 3rd July, 1975	Do	The duty of persons, referred in clause (a) sub-section (i) of section 2 of B.S.F. Act, 1968 serving in Delhi is active duty.
	का०आ० 302 (अ), दिनांक 3 जुलाई, 1975	तदैव	सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 की धारा 2 की उपधारा (i) के खंड (क) में उल्लिखित व्यक्ति को केरल में सक्रिय ड्यूटी।
	S.O. 302(E), dated the 3rd July, 1975	Do.	The duty of persons referred to in clause (a) sub-section (i) of section 2 of B.S.F. Act, 1968, serving in Kerala is active duty.
	का०आ० 303 (अ), दिनांक 3 जुलाई, 1975	तदैव	सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 की धारा 2 की उपधारा (i) के खंड (क) में उल्लिखित व्यक्ति की मेघालय में सक्रिय ड्यूटी।
	S.O. 303(E), dated the 3rd July, 1975	Do.	The duty of per ons referred to in clause (a) of sub-section (i) of section 2 of B.S.F. Act, 1968, serving in Meghalaya is active duty.
231.	S.O. 304(E), dated the 3rd July, 1975	Do.	Application of the Defence and Internal Security of India Rules, 1971 to organisations as specified in the Schedule.
	S.O. 305(E), dated the 3rd July, 1975	Do.	Do.
	S.O. 306(E), dated the 3rd July, 1975	Do.	Application of the Defence and Internal Security of India Rules, 1971 to the Rashtriya Swayam Sevak Sangh.
	S.O. 307(E), dated the 3rd July, 1975	Do.	Application of the Defence and Internal Security of India Rules, 1971 to the Jamait-e-Islami-e-Hind.
232.	का०आ० 308 (अ), दिनांक 4 जुलाई, 1975	श्रम मंत्रालय	भारत खाद्य निगम में हड़ताल को प्रतिषिद्ध करना।
	S.O. 308(E), dated the 4th July, 1975	Ministry of Labour	Prohibition of strikes in the Food Corporation of India.

1	2	3	4
233.	का०आ० 309 (अ) दिनांक 4 जुलाई, 1975	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	अनुसूची में दी गई फिल्मों को स्वीकृति।
	S.O. 309(E), dated the 4th July, 1975.	Ministry of Information and Broadcasting.	Approval of films as specified in the schedule.
234.	S.O. 310(E), dated the 4th July, 1975.	Ministry of Home Affairs	Application of the Defence and Internal Security of India Rules, 1971 to Jamaat-e-Islami-e-Jammu and Kashmir.
235.	का०आ० 311 (अ), दिनांक 4 जुलाई, 1975	भारत निर्वाचन आयोग	सारणी में विनिर्दिष्ट आफिसरों को असम राज्य के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में पदाभिहित करना।
	S.O. 311(E), dated the 4th July, 1975.	Election Commission of India	Designation of officers as specified in the table to be District Election Officer in the State of Assam.
236.	का०आ० 312 (अ), दिनांक 4 जुलाई, 1975	वाणिज्य मंत्रालय	आदेश सं० 2/61 तारीख 28 फरवरी, 1961 का संशोधन।
	S.O. 312(E), dated the 4th July, 1975.	Ministry of Commerce	Amendment to Order No. 2/61 dated the 28th February, 1961
237.	का०आ० 313 (अ), दिनांक 5 जुलाई, 1975	उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय	अनुसूची में विनिर्दिष्ट उपक्रमों को अन्य विशिष्टियां दर्ज करने के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र को पेश करना।
	S.O. 313(E), dated the 5th July, 1975.	Ministry of Industry and Civil Supply	Production of Certificate of Registration of undertakings as specified in the Schedule for entering particulars etc.
238.	S.O. 314(E), dated the 5th July, 1975.	Ministry of Home Affairs	Appoints the Chief Censor to the Govt. of India to be a Consor
239.	S.O. 315(E), dated the 5th July, 1975.	Do.	No power will be exercised by the State Govt. under sub-rule (1) of rule 48 of the Defence and Security of India Rules 1971 without the approval of Central Govt.
240.	S.O. 316(E), dated the 6th July, 1975.	Do.	Amendments to the Order No. S.O. 275(E), dated the 26th June 1975.
241.	का०आ० 317 (अ), दिनांक 7 जुलाई, 1975	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	अनुसूची के कालम 2 में दी गई फिल्मों को स्वीकृति देना।
	S.O. 317(E), dated the 7th July, 1975.	Ministry of Information and Broadcasting	Approval of films as specified in column 2 of the Schedule annexed hereto.
	का०आ० 318 (अ), दिनांक 7 जुलाई, 1975	तदेव	द्वितीय अनुसूची के कालम 2 में विनिर्दिष्ट फिल्मों को स्वीकृति
	S.O. 318(E), dated the 7th July, 1975.	Do.	Approval of Films as specified in column 2 of the second schedule annexed hereto.
	का०आ० 319 (अ), दिनांक 7 जुलाई, 1975	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	द्वितीय अनुसूची के कालम 2 में विनिर्दिष्ट फिल्मों को स्वीकृति।
	S.O. 319(E), dated the 7th July, 1975.	Ministry of Information and Broadcasting	Approval of films as specified in column 2 of the Second Schedule annexed hereto.
	का०आ० 320 (अ), दिनांक 7 जुलाई, 1975	तदेव	अनुसूची के कालम 2 में विनिर्दिष्ट फिल्मो को स्वीकृति।
	S.O. 320(E), dated the 7th July, 1975.	Do.	Approval of films as specified in column 2 of the Schedule annexed hereto.
	का०आ० 321 (अ), दिनांक 7 जुलाई, 1975	तदेव	अनुसूची के कालम 2 में विनिर्दिष्ट फिल्मों को स्वीकृति।
	S.O. 321(E), dated the 7th July, 1975.	Do.	Approval of films as specified in column 2 of the Schedule annexed hereto.
	का०आ० 322 (अ), दिनांक 7 जुलाई, 1975	तदेव	अनुसूची के कालम 2 में विनिर्दिष्ट फिल्मों को स्वीकृति।
	S.O. 322(E), dated the 7th July, 1975.	Do.	Approval of films as specified in column 2 of the Schedule annexed hereto.

1	2	3	4
	का०आ० 323 (अ), दिनांक 7 जुलाई, 1975	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	द्वितीय अनुसूची के कालम 2 में विनिर्दिष्ट फिल्मों को स्वीकृति ।
	S.O. 323(E), dated the 7th July, 1975.	Ministry of Information and Broad casting	Approval of films as specified in column 2 of the Second Schedule annexed hereto.
	का०आ० 324 (अ), दिनांक 7 जुलाई, 1975	तदेव	अनुसूची के कालम 2 में विनिर्दिष्ट फिल्मो को स्वीकृति ।
	S.O. 324(E), dated the 7th July, 1975.	Do.	Approval of films as specified in column 2 of the Schedule annexed hereto.
	का०आ० 325 (अ), दिनांक 7 जुलाई, 1975	तदेव	अनुसूची के कालम 2 में विनिर्दिष्ट फिल्मों को स्वीकृति ।
	S.O. 325(E), dated the 7th July, 1975.	Do.	Approval of films as specified in column 2 of the Schedule annexed hereto.
	का०आ० 326 (अ), दिनांक 7 जुलाई, 1975	तदेव	द्वितीय अनुसूची के कालम 2 में विनिर्दिष्ट फिल्मों को स्वीकृति ।
	S.O. 326(E), dated the 7th July, 1975.	Do.	Approval of films as specified in column 2 of the Second Schedule annexed hereto.
	का०आ० 327 (अ), दिनांक 7 जुलाई, 1975	तदेव	अनुसूची के कालम 2 में विनिर्दिष्ट फिल्मों को स्वीकृति ।
	S.O. 327(E), dated the 7th July, 1975.	Do.	Approval of Films as specified in column 2 of the Schedule annexed hereto.
	का०आ० 228 (अ), दिनांक 7 जुलाई, 1975	तदेव	द्वितीय अनुसूची के कालम 2 में विनिर्दिष्ट फिल्मों को स्वीकृति ।
	S.O. 228(E), dated the 7th July, 1975.	Do.	Approval of films as specified in column 2 of the Second Schedule annexed hereto.
	का० आ० 229 (अ), दिनांक 7 जुलाई, 1975	तदेव	अनुसूची के कालम 2 में विनिर्दिष्ट फिल्मों को स्वीकृति ।
	S.O. 229(E), dated the 7th July, 1975.	Do.	Approval of films as specified in column 2 of the Schedule annexed hereto.
	आ०का० 330 (अ), दिनांक 7 जुलाई, 1975	तदेव	अनुसूची के कालम 2 में विनिर्दिष्ट फिल्मों को स्वीकृति ।
	S.O. 330(E), dated the 7th July, 1975.	Do.	Approval of films as specified in column 2 of the Schedule annexed hereto.
242.	का०आ० 331 (अ), दिनांक 7 जुलाई, 1975	कृषि और सिंचाई मंत्रालय	दिल्ली, मेरठ और बुलन्दशहर दूध और दुग्ध उत्पाद नियंत्रण आदेश, 1975
	S.O. 331(E), dated the 7th July, 1975.	Ministry of Agriculture and Irrigation	The Delhi, Meerut and Bulandshahr Milk and Milk Products (Export) Control Order, 1975.
243.	का०आ० 332 (ई), दिनांक 8 जुलाई, 1975	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	अनुसूची के कालम 2 में विनिर्दिष्ट फिल्मों को स्वीकृति ।
	S.O. 332(E), dated the 8th July, 1975.	Ministry of Information and Broadcasting	Approval of films as specified in column 2 of the Schedule annexed hereto.
	का०आ० 333 (अ), दिनांक 8 जुलाई, 1975	तदेव	द्वितीय अनुसूची के कालम 2 में विनिर्दिष्ट फिल्मों को स्वीकृति ।
	S.O. 333(E), dated the 8th July, 1975.	Do.	Approval of films as specified in column 2 of the Second Schedule annexed hereto.
	का०आ० 334 (अ), दिनांक 8 जुलाई, 1975	तदेव	अनुसूची के कालम 2 में विनिर्दिष्ट फिल्मों को स्वीकृति ।
	S.O. 334(E), dated the 8th July, 1975.	Do.	Approval of films as specified in column 2 of the Second Schedule annexed hereto.

1	2	3	4
	एस०ओ० 335 (अ), दिनांक 8 जुलाई, 1975	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	अनुसूची के कालम 2 में विनिर्दिष्ट फिल्मों को स्वीकृति।
	S.O. 335(E), dated the 8th July, 1975.	Ministry of Information and Broadcasting	Approval of films as specified in column 2 of the schedule annexed hereto.
	एस०ओ० 336 (अ), दिनांक 8 जुलाई, 1975	तदैव	अनुसूची के कालम 2 में विनिर्दिष्ट फिल्मों को स्वीकृति।
	S.O. 336(E), dated the 8th July, 1975.	Do.	Approval of films as specified in column 2 of the Schedule annexed hereto.
	एस०ओ० 337 (अ), दिनांक 8 जुलाई, 1975	तदैव	द्वितीय अनुसूची के कालम 2 में विनिर्दिष्ट फिल्मों को स्वीकृति।
	S.O. 337(E), dated the 8th July, 1975.	Do.	Approval of films as specified in column 2 of the Second Schedule annexed hereto.
	एस०ओ० 338 (अ), दिनांक 8 जुलाई, 1975	तदैव	द्वितीय अनुसूची के कालम 2 में विनिर्दिष्ट फिल्मों को स्वीकृति।
	S.O. 338(E), dated the 8th July, 1975.	Do.	Approval of films as specified in column 2 of the second schedule annexed hereto.
244.	का०आ० 339 (अ), दिनांक 8 जुलाई, 1975	भारत निर्वाचन आयोग	दिल्ली के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर के रूप में पदाभिहित करना।
	S.O. 339(E), dated the 8th July 1975.	Election Commission of India	Designation of Eleectoral Registration Officers of Parliamentary Constituency of Delhi.
	का०आ० 340 (अ), दिनांक 8 जुलाई, 1975	तदैव	संघ राज्य क्षेत्र में सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर की नियुक्ति।
	S.O. 340(E), dated the 8th July 1975.	Do.	Appointment of Assistant Electoral Officer for Union Territory of Delhi.
	S.O. 341(E), dated the 9th July, 1975.	Ministry of Home Affairs	Specifies rule 33 of the Defence and Internal Security of India Rules, 1971.
246.	का०आ० 342 (अ), दिनांक 9 जुलाई, 1975	विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय	पश्चिम बंगाल विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन।
	S.O. 342(E), dated the 9th July, 1975.	Ministry of Law, Justice and Company Affairs	Biennial Election to the Council of States by the elected members of the Legislative Assembly of West Bengal.
247.	का०आ० 343 (अ), दिनांक 10 जुलाई, 1975	विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय	पश्चिम बंगाल विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचित सदस्यों के नाम।
	S.O. 343(E), dated the 10th July 1975.	Ministry of Law, Justice and Company Affairs	Names of Members elected by the elected members of the Legislative Assembly of West Bengal.
248.	का०आ० 344 (अ), दिनांक 10 जुलाई, 1975	संचार मंत्रालय	भारतीय बेतार तार यांत्रिकी (कब्जा) नियम 1965 का सिक्किम राज्य को विस्तारित।
	S.O.344(E), dated the 10th July, 1975.	Ministry of Communications	Indian Wireless Telegraphy (Possession) Rules, 1965 extended to Sikkim.
249.	का०आ० 345 (अ), दिनांक 10 जुलाई, 1975	श्रम मंत्रालय	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अध्याय 4, 5, 6, के उपबन्ध आन्ध्र प्रदेश के क्षेत्रों पर लागू।
	S.O. 345(E), dated the 10th July, 1975.	Ministry of Labour	Provision of Chapters, IV, V and VI of the Employees State Insurance Act, 1948 come into force in the areas of Andhra Pradesh as specified.
250.	का०आ० 346 (अ), दिनांक 10 जुलाई, 1975	वित्त मंत्रालय	श्री चम्पालाल पंजाजी शाह को पुलिस आयुक्त, बृहत्तर मुम्बई के समक्ष हाजिर होना।
	S.O. 346(E) dated the 10th July, 1975.	Ministry of Finance	Directs Shri Champalal Punjaji Shah to appear before the Commissioner of Police, Greater Bombay.
251.	का०आ० 347 (अ), दिनांक 10 जुलाई, 1975	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	"आंधी" नामक फिल्म का प्रदर्शन दो माह तक स्थगित।
	S.O. 347(E), dated the 10th July, 1975.	Ministry of Information and Broadcasting.	Exhibition of the films entitled "ANDHI" be suspended for two months.

1	2	3	4
252.	का०आ० 348 (अ), दिनांक 10 जुलाई, 1975	उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय	आदेश सं० का०आ० 230 (अ), तारीख 26 मई 1975 में संशोधन।
	S.O. 348(E), dated the 10th July, 1975.	Ministry of Industry and Civil Supplies	Amendment to Order No. S.O. 230(E), dated the 26th May, 1975.
253.	का०आ० 349 (अ), दिनांक 11 जुलाई, 1975	ऊर्जा मंत्रालय	सरकारी स्थान (आप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम 1971, के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सम्पदा अधिकारी की नियुक्ति।
	S.O. 349(E), dated the 11th July, 1975.	Ministry of Energy	Appointment of officers as Estate Officer to exercise the powers under Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971.
254.	का०आ० 350 (अ), दिनांक 11 जुलाई, 1975	श्रम मंत्रालय	मध्य प्रदेश की कपड़ा मिलों में हड़ताल को प्रतिषिद्ध करना।
	S.O. 350(E), dated the 11th July, 1975.	Ministry of Labour	Prohibition of strikes in textile mills in Madhya Pradesh.
	का०आ० 351 (अ), दिनांक 11 जुलाई, 1975	श्रम मंत्रालय	नियेली लिगनाइट कारपोरेशन, नियेली में हड़ताल को प्रतिषिद्ध करना।
	S.O. 351(E), dated the 11th July, 1975.	Do.	Prohibition of strike in Neyveli Lignite Corporation Ltd., Neyveli.
255.	का०आ० 352 (अ), दिनांक 15 जुलाई, 1975	विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय	कम्पनी (लाभांशों पर अस्थायी निर्बन्धन) अधिपत्र नियम, 1975।
	S.O. 352(E), dated the 15th July, 1975.	Ministry of Law, Justice and Company Affairs	Companies (Temporary Restrictions on Dividends) Warrant Rules, 1975.
256.	का०आ० 353 (अ), दिनांक 15 जुलाई, 1975	इस्पात और खान मंत्रालय	एल्यूमीनियम (नियंत्रण) द्वितीय संशोधन आदेश 1975
	S.O. 353(E), dated the 15th July, 1975.	Ministry of Steel and Mines	Aluminium (Control) Second Amendment order, 1975.
	का०आ० 354 (अ), दिनांक 15 जुलाई, 1975	इस्पात और खान मंत्रालय	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के सभी राजपत्रित अधिकारियों को एल्यूमिनियम (नियंत्रण) आदेश, 1975 के अधीन अधिकारों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करना।
	S.O. 354(E), dated the 15th July, 1975.	Ministry of Steel and Mines	Appoints all the gazetted officers of Central Excise to exercise all the powers under the Aluminium (Control) Order, 1975.
	का०आ० 355 (अ), दिनांक 15 जुलाई, 1975	तदैव	एल्यूमीनियम (नियंत्रण) तृतीय संशोधन आदेश 1975।
	S.O. 355(E), dated the 15th July, 1975.	Do.	Aluminium (Control) Third Amendment Order, 1975.
	का०आ० 356 (अ), दिनांक 11 जुलाई, 1975	तदैव	एल्यूमीनियम का हर एक उत्पादक ई०सी० ग्रेड, एल्यूमीनियम जरूर पैदा करेगा जितनी मात्रा का औद्योगिक लाइसेंस दिया गया है।
	S.O. 356(E), dated the 15th July, 1975.	Do.	Each producer shall produce required quantity of Electrical conductor grade Aluminium in terms of Industrial licence granted.
	का०आ० 357 (अ), दिनांक 15 जुलाई, 1975	इस्पात और खान मंत्रालय	प्रत्येक उत्पादक अपने मासिक उत्पादन का 55 प्रतिशत उत्पाद उपभोक्ताओं को सप्लाई करेगा जिसका उल्लेख एल्यूमीनियम (नियंत्रण) आदेश, 1971 की धारा 4सी में किया गया है।
	S.O. 357(E) dated the 15 th July 1975.	Ministry of Steel and Mines	Each producer shall supply 55% of monthly production to the consumer referred to in clause 4C of the Aluminium (Control) Order, 1970.
	का०आ० 358 (अ), दिनांक 15 जुलाई, 1975	तदैव	अनुसूची में उल्लिखित लेवी एल्यूमीनियम का मूल्य नियत करना।
	S.O. 358(E), dated the 15th July, 1975.	Do.	Fixation of sale price of levy Aluminium as specified in the Schedule.

1	2	3	4
257.	का० आ० 359 (अ), दिनांक 16 जुलाई, 1975	वाणिज्य मंत्रालय	निर्यात (नियंत्रण) चौदहवां संशोधन आदेश, 1975।
	S.O. 359 dated the 16th July, 1975.	Ministry of Commerce	Export (Control) Fourteenth) Amendment Order, 1975.
258.	का० आ० 360(अ)/18 ए/आई डी आर ए/75, दिनांक 16 जुलाई, 1975	उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय	आदेश सं० 608(अ)/18 ए/आई डी आर ए/72, तारीख 18 सितम्बर, 1972 में संशोधन।
	S.O. 360(E)/18 A/IDRA/75, dated the 16th July, 1975.	Ministry of Industry and Civil Supplies.	Amendment in Order No. S.O. 608(E)/18A/IDRA/72, dated the 18th September, 1972.
259.	का० आ० 361(अ), दिनांक 18 जुलाई, 1975	भारत निर्वाचन आयोग	जम्मू और काश्मीर राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से राज्य सभा के लिये एक व्यक्ति को निर्वाचित करने की अपेक्षा करना।
	S.O. 361(E) dated the 18th July, 1975.	Election Commission of India	Calls upon the elected members of the Legislative Assembly of Jammu and Kashmir to fill a vacancy in Council of States.
	का० आ० 362(अ) दिनांक 18 जुलाई, 1975	भारत निर्वाचन आयोग	अधिसूचना सं० 100/रा० सं० ज क/1/75(1) ता० 18 जुलाई, 1975 के अनुसरण में नाकनिर्देशन, वापस लेने और चुनाव आदि के लिये तारीख नियत करना।
	S.O. 362(E) dated the 18th July, 1975.	Election Commission of India	In pursuance of Notn. No. 100/CS-J & K/1/75(1), dated, the 18th July, 1975 appoints the dates for nomination, Scrutiny of nomination and election etc.
	का० आ० 363(अ), दिनांक 18 जुलाई, 1975	भारत निर्वाचन आयोग	अधिसूचना सं० 100/रा० सं०-ज क/1/75(1), तारीख 18 जुलाई, 1975 के अनुसरण में निर्वाचन के लिये समय नियत करना।
	S.O. 363(E) dated the 18th July, 1975.	Election Commission of India	Fixation of hours for election in pursuance of Notn. No 100/CS-J & K/I/75(1), dated the 18th July, 1975.
	का० आ० 364(अ), दिनांक 18 जुलाई, 1975	भारत निर्वाचन आयोग	अधिसूचना सं० 100/रा० सं०-जाक/1/75(1), तारीख 18 जुलाई, 1975 के अनुसरण में सचिव, विधान सभा को रिटर्निंग आफिसर पदाभिहित करना।
	S.O. 364(E) dated the 18th July, 1975.	Election Commission of India	In pursuance of Notn. No. 100/CS-J & K/1/75 (1) dated the 18th July, 1975 appoints Secretary, Legislative Assembly as Returning officer.
	का० आ० 365(अ), दिनांक 18 जुलाई, 1975	भारत निर्वाचन आयोग	रिटर्निंग आफिसर की सहायता के लिये श्री रोशन लाल, उपसचिव, जम्मू और काश्मीर विधान सभा, को नियुक्त करना।
	S.O. 365(E) dated the 18th July, 1975.	Election Commission of India	Appointment of Shri Roshan Din, Dy. Secy., Legislative Assembly of Jammu and Kashmir to assist the Returning Officer.
260.	का० आ० 366(अ), दिनांक 18 जुलाई, 1975	वाणिज्य मंत्रालय	जुलाई 1975—जून 1976 मौसम के लिये कच्चे जूट की न्यूनतम कीमतें।
	S.O. 366(E) dated the 18th July, 1975.	Ministry of Commerce	Fixation of minimum prices of Raw Jute during the season July 1975 to June 1976.
261.	का० आ० 367(अ) दिनांक 19 जुलाई, 1975	भारत निर्वाचन आयोग	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिये ट्रेजरी आफिसर को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर के रूप में पदाभिहित करना।
	S.O. 367(E) dated the 19th July, 1975.	Election Commission of India	Appointment of Treasury Officer as Electoral Registration Officer for the Andaman and Nicobar Islands Parliamentary Constituency.
262.	का० आ० 368(अ)/आई डी आर ए/29 ख/75/4, दिनांक 21 जुलाई, 1975	उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय	अधिसूचना सं० 98(अ)/आई डी आर ए/29 ख/73/1, तारीख 16 फरवरी, 1973 में और संशोधन।
	S.O. 368(E)/IDRA/29B/75/4 dated the 21st July, 1975.	Ministry of Industry and Civil Supplies.	Further amendment to Notn. No. S.O.98(E)/IDRA/29B/73/1, dated the 16th February, 1973.
263.	का० आ० 369(अ), दिनांक 22 जुलाई, 1975	भारत निर्वाचन आयोग	गुजरात राज्य विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिये 3 सदस्यों के निर्वाचन हेतु तारीखें नियत करना।
	S.O. 369(E) dated the 22nd July, 1975.	Election Commission of India	Fixation of dates for the election of three members to the Council of States by the elected members of the Gujarat Legislative Assembly.

1	2	3	4
	का० आ० 370(अ) दिनांक, 22 जुलाई, 1975	भारत निर्वाचन आयोग	गुजरात राज्य में राज्य सभा के लिये होने वाले द्विवार्षिक निर्वाचन के लिये समय नियत करना ।
	S.O. 370(E) dated the 22nd July, 1975	Election Commission of India	Fixation of time for the biennial Elections to the Council of States in the State of Gujarat.
	का० आ० 371(अ), दिनांक 22 जुलाई, 1975	भारत निर्वाचन आयोग	राज्य सभा के लिये होने वाले द्विवार्षिक निर्वाचन के लिये सचिव, गुजरात विधान मंडल सचिवालय को रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित करना ।
	S.O. 371(E) dated the 22nd July, 1975.	Election Commission of India	Designates Secretary, Gujarat Legislative Secre'ariat as a Returning Officer for the biennial elections to the Council of States.
	का० आ० 372(अ), दिनांक 22 जुलाई 1975	भारत निर्वाचन आयोग	उप सचिव, गुजरात विधान मंडल सचिवालय, को रिटर्निंग आफिसर की सहायता के लिये नियुक्त करना ।
	S.O. 372(E) dated the 22nd July, 1975.	Election Commission of India	Appoints Dy. Secy., Gujarat Legislative Secretariat to assist the Returning Officer.
264.	का० आ० 373(अ), दिनांक 22 जुलाई, 1975	वाणिज्य मंत्रालय	अधिसूचना सं० एस० ओ० 1317, दिनांक 9 जून, 1956 में और आगे संशोधन ।
	S.O. 373(E) dated the 22nd July, 1975.	Ministry of Commerce	Further amendment to Notn. No. S.O. 1317, dated the 9th June 1956.
265.	का० आ० 374(अ), दिनांक 22 जुलाई, 1975	विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय	गुजरात राज्य विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों को राज्य सभा के लिये 3 सदस्यों को निर्वाचित करने के लिये आहूत करना ।
	S.O. 374(E) dated the 22nd July, 1975.	Ministry of Law, Justice and Company Affairs.	To call upon the elected members of the Legislative Assembly of Gujarat to elect three members for Council of States.
266.	का० आ० 375(अ), दिनांक 22 जुलाई, 1975	उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय	मैसर्स ग्लूकोनेट लिमिटेड, कलकत्ता का प्रबन्ध ग्रहण करना ।
	S.O. 375(E) dated the 22nd July, 1975.	Ministry of Industry and Civil Supplies.	Taking over the management of Messrs. Gluconate Limited, Calcutta.
267.	का० आ० 376(अ), दिनांक 23 जुलाई, 1975	श्रम मंत्रालय	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अध्याय 4, 5 और 6 के उपबन्ध इस तारीख से बीकानेर जिले के बेछवाल ग्राम पर लागू होना।
	S.O. 376(E) dated the 23rd July 1975.	Ministry of Labour	The date on which the provisions of Chapter IV, V and VI of Employees' Estate Insurance Act, 1948, come into force in village Bechhwal in Bikaner Distt.
268.	S.O. 377 (E) dated the 23rd July, 1975.	Ministry of Home Affairs	Powers under sub-rule (2) of rule 48 of the Defence and Internal Security of India Rules 1971, shall be exercised by all State Governments and the Chief Censor to the Government of India.
269.	का० आ० 378(अ)/18 का/आई डी आर ए/75, दिनांक, 24 जुलाई, 1975	उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय	आदेश सं० का० आ० 725(अ)/18 क/आई डी आर ए/72, तारीख 25 नवम्बर, 1925 में संशोधन ।
	S.O. 378(E)/18A/IDRA/75 dated the 24th July, 1975.	Ministry of Industry and Civil Supplies.	Amendment in Order No. S.O. 725(E)/18A/IDRA/72, dated the 25th November, 1972.
270.	का० आ० 379(अ), दिनांक 25 जुलाई, 1975	नौवहन और परिवहन मंत्रालय	राष्ट्रीय राज मार्ग अधिनियम, 1956 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट राज्य मार्ग 2 को अनुसूची से हटाना ।
	S.O. 379(E) dated the 25th July, 1975.	Ministry of Shipping and Transport.	Omission of National Highway No. 2 as specified in Schedule to National Highways Act, 1956.
	का० आ० 380(अ), दिनांक 25 जुलाई, 1975	नौवहन और परिवहन मंत्रालय	सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करना ।
	S.O. 380(E) dated the 25th July, 1975.	Ministry of Shipping and Transport.	Declaration of the highway as specified in Column (3) of the table to be a National Highway.
271.	का० आ० 381(अ), दिनांक 26 जुलाई, 1975	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	अनुसूची के कालम 2 में विनिर्दिष्ट फिल्मों को स्वीकृति ।
	S.O. 381(E) dated the 26th July, 1975.	Ministry of Information and Broadcasting.	Approval of films specified in the column 2 of the Schedule annexed.

1	2	3	4
271.	का० आ० 382(अ) दिनांक 26 जुलाई 1975	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	अनुसूची के कालम 2 में विनिर्दिष्ट फिल्मों को स्वीकृति ।
	S.O. 382(E) dated the 26th July, 1975.	Ministry of Information and Broadcasting.	Approval of films specified in Column 2 of the Schedule annexed.
	का० आ० 383(अ) दिनांक 26 जुलाई 1975	तदेव	अनुसूची के कालम 2 में विनिर्दिष्ट फिल्मों की स्वीकृति ।
	S.O. 383(E) dated the 26th July 1975.	Do.	Approval of films specified in column 2 of the Schedule annexed.
	का० आ० 384(अ) दिनांक 26 जुलाई 1975	तदेव	अनुसूची के कालम 2 में विनिर्दिष्ट फिल्मों की स्वीकृति ।
	S.O. 384(E) dated the 26th July 1975.	Do.	Approval of film specified in Column 2 of the Schedule annexed.
	का० आ० 385(अ) दिनांक 26 जुलाई 1975	तदेव	अनुसूची के कालम 2 में विनिर्दिष्ट फिल्मों की स्वीकृति ।
	S.O. 385(E) dated the 26th July 1975.	Do	Approval of films specified in Column 2 of the Schedule annexed.
	का० आ० 386(अ) दिनांक 26 जुलाई 1975	तदेव	अनुसूची के कालम 2 में विनिर्दिष्ट फिल्म को स्वीकृति ।
	S.O. 386(E) dated the 26th July 1975.	Do.	Approval of film specified in Column 2 of the Schedule annexed.
272.	का० आ० 387(अ) दिनांक 26 जुलाई 1975	वाणिज्य मंत्रालय	निर्यात (नियंत्रण) पन्द्रहवां संशोधन आदेश 1975 ।
	S.O. 387(E) dated the 26th July 1975.	Ministry of Commerce	The Exports (Control) fifteenth Amendment Order 1975.
273.	का० आ० 388(अ) दिनांक 26 जुलाई 1975	इस्पात और खान मंत्रालय	श्री वी० पंचापगेशन की एल्यूमिनियम नियंत्रक के रूप में नियुक्ति ।
	S.O. 388(E) dated the 26th July 1975.	Ministry of Steel and Mines	Appoints Shri V. Panchapagesan to be Controller of Allumi-nium.
274.	का० आ० 389(अ) दिनांक 28 जुलाई 1975	उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय	भारत रक्षा (पैकेज वस्तु) आदेश, 1975
	S.O. 389(E) dated the 28th July 1975.	Ministry of Industry and Civil Supplies	The Defence of India (packaged Commodities) Order, 1975.
275.	का० आ० 390(अ) दिनांक 28 जुलाई 1975	दिल्ली विकास प्राधिकरण	दिल्ली मुख्य योजना में लागू किये जाने वाले क्षेत्रीय नियमों में संशोधन ।
	S.O. 390(E) dated the 28th July 1975.	Delhi Development Authority	Proposal to the modifications to be made to the zoning regu-lation in the Master Plan.
276.	का० आ० 391(अ) दिनांक 28 जुलाई 1975	गृह मंत्रालय	सं० सा० आ० 88(ई) तारीख 10 फरवरी 1975 के द्वारा नियुक्त जांच आयोग की कार्याविधि को और बढ़ाना ।
	S.O. 391(E) dated the 28th July 1975.	Minstry of Home Affairs	Further extended the period of the Commission of Inquiry appointed by Notn. No. S.O. 88(E), dated the 10th Febru-ary, 1975.
277.	का० आ० 392(अ) दिनांक 28 जुलाई 1975	कृषि और सिंचाई मंत्रालय	उर्वरक (संचलन नियंत्रण) तृतीय संशोधन आदेश 1975 ।
	S.O. 392(E) dated the 28th July 1975.	Ministry of Agriculture and Irrigation	The Fertiliser (Movement Control) (Third Amendment) Order, 1975.
278.	का० आ० 393(अ) दिनांक 29 जुलाई 1975	विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय	जम्मू-कश्मीर विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिये उपनिर्वाचन ।
	S.O. 393(E) dated the 29th July 1975.	Ministry of Law, Jastice and Company Affairs	Declaration re. Election to the Council of States by the elected members of the Legislative Assembly of Jammu and Kashmir.

1	2	3	4
279.	का० आ० 394(अ) दिनांक 30 जुलाई 1975	उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय	स्कूटर (वितरण और विक्रय) नियंत्रण (द्वितीय संशोधन) आदेश, 1975।
	S.O. 394(E) dated the 30th July 1975.	Ministry of Industry and Civil Supplies	The Scooters (Distribution and Sale) Control (Second Amendment) Order, 1975.
280.	का० आ० 395(अ) दिनांक 30 जुलाई 1975	वाणिज्य मंत्रालय	अधिसूचना सं० का० आ० 162, दिनांक 13 जनवरी 1961 का अतिक्रमण करते हुये तारीख निर्धारित करना है जिससे 40 पैसे प्रतिकिलो ग्राम रबड़ की दर पर उत्पादन शुल्क लगाया जायेगा।
	S.O. 395(E) dated the 30th July 1975.	Ministry of Commerce	In Supersession of Notn. No. S.O. 162 dated the 13th January 1961 appoints the date on which the cess of 40 paise per Kg. of Rubber will take effect.
281.	का० आ० 396(अ) दिनांक 30 जुलाई 1975	पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय	आदेश सं० 1873, तारीख 18 मई 1970 में और संशोधन।
	S.O. 396(E) dated the 30th July 1975.	Ministry of Petroleum and Chemicals	Further amendments o Order No. S.O. 1873 dated the 18th May 1970.
282.	का० आ० 397(अ) दिनांक 30 जुलाई 1975	पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय	आदेश सं० का० आ० 1873 तारीख 18 मई 1970 में और संशोधन।
	S.O. 397(E) dated the 30th July 1975.	Ministry of Petroleum and Chemicals	Further amendment to Order No. S.O. 1873 dated the 18th May 1970.
283.	का० आ० 398(अ) दिनांक 31 जुलाई 1975	गृह मंत्रालय	15 अगस्त 1975 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको संघ राज्य क्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम 1975 प्रवृत्त होगा।
	S.O. 398(E) dated the 31st July 1975.	Ministry of Home Affairs	Appoints the 15th August 1975 as the date on which the Government of Union Territories (Amendment) Act, 1975 will come into force.
284.	का० आ० 401(अ) दिनांक 1 अगस्त 1975	शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय	महाराष्ट्र सरकार के सचिव श्री ए० ए० जिनवाला की कापीराइट बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्ति।
	S.O. 401(E) dated the 1st August, 1975.	Ministry of Education and Social Welfare	Appointment of Shri A.A. Ginwala, Secretary to Govt. of Maharashtra as a member of Copy right Board.
285.	सा० नि० 402(अ) दिनांक 1 अगस्त 1975	गृह मंत्रालय	प्रत्येक व्यक्ति की जो कि सुरक्षा बल अधिनियम 1968 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (क) के अनुसरण में मणीपुर से सेवारत है सक्रिय ड्यूटी होगी।
	S.O. 402(E) dated the 1st August, 1975.	Ministry of Home Affairs	Duty of every person referred to in clause (a), sub-section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968. Serving in Manipur is an active duty.
	सा० नि० 403(अ) दिनांक 1 अगस्त, 1975	तदैव	प्रत्येक व्यक्ति की जो कि सुरक्षा दल अधिनियम 1968 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (क) के अनुसरण में महाराष्ट्र से सेवारत है सक्रिय ड्यूटी होगी।
	S.O. 403(E) dated 1st August, 1975.	Do.	Duty of every person referred to in Clause (a), sub-section (i of section 2 of the Border Security Force Act, 1968, Serving in Maharashtra is an active duty.
	सा० नि० 404(अ) दिनांक 1 अगस्त 1975	तदैव	प्रत्येक व्यक्ति की जो कि सुरक्षा बल अधिनियम 1968 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (क) के अनुसरण में मध्य प्रदेश से सेवारत है सक्रिय ड्यूटी होगी।
	S.O. 404(E) dated the 1st August, 1975.	Do.	Duty of every person, referred to in clause (a) sub-section (i) of Section 2 of the Border Security Force Act, 1968 Serving in Madhya Pradesh, is an active duty.
	सा० नि० 405(अ) दिनांक 1 अगस्त 1975	तदैव	प्रत्येक व्यक्ति की जो कि सुरक्षा दल अधिनियम 1968 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (क) के अनुसरण में मैसूर से सेवारत है सक्रिय ड्यूटी होगी।
	S.O. 405(E) dated the 1st August, 1975.	Do.	Duty of every person referred to in clause (a), sub-section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968, Serving in Mysore is an active duty.

1	2	3	4
	सा० नि० 406(अ) दिनांक 1 अगस्त, 1975	गृह मंत्रालय	प्रत्येक व्यक्ति जो कि सुरक्षा दल अधिनियम 1968 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (क) के अनुसरण में आंध्र प्रदेश से सेवारत है, सक्रिय ड्यूटी होगी ।
	S.O. 406(E) dated the 1st August, 1975.	Ministry of Home Affairs	Duty of every person referred to in clause (a) sub-section (i) of section 2 of the Border Security Force Act 1968, Serving in Andhra Pradesh, is an active duty.
	सा० नि० 407(अ) दिनांक 1 अगस्त, 1975	तदेव	प्रत्येक व्यक्ति जो कि सुरक्षा दल अधिनियम 1968 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (क) के अनुसरण में उत्तर प्रदेश से सेवारत है, सक्रिय ड्यूटी होगी ।
	S.O. 407(E) dated the 1st August, 1975.	Do.	Duty of every person referred to in clause (a) subsection (i) of section 2 of the Border Security Act 1968, serving in Uttar Pradesh is an active duty.
286.	सा० आ० 408(अ) दिनांक 1 अगस्त, 1975	ऊर्जा मंत्रालय	कोयला खान मालिकों द्वारा कोयला अथवा कोक की बिक्री के लिये खान मुहाना मूल्य निर्धारित करना ।
	S.O. 408(E) dated the 1st August, 1975.	Ministry of Energy	Fixcation of pit head prices at which coal or Coke may be sold by Colliery owners.
287.	का० आ० 409(अ) दिनांक 2 अगस्त, 1975	वित्त मंत्रालय	फीस उद्ग्रहण (सीमाशुल्क दस्तावेज) संशोधन विनियम 1975 ।
	S.O. 409(E) dated the 2nd August, 1975.	Ministry of Finance	Levy of Fees (Customs Documents) Amendment Regulations 1975.
	का० आ० 410(अ) दिनांक 2 अगस्त, 1975	विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय	का० आ० 243(अ) दिनांक 10 जुलाई, 1975 की अधिसूचना में संशोधन ।
	का० आ० 411(अ) दिनांक 2 अगस्त 1975	तदेव	अधिसूचना सं० का० आ० 242(अ) दिनांक 9 जुलाई, 1975 में संशोधन ।
289.	का० आ० 412(अ) दिनांक 2 अगस्त, 1975	मंत्रिमंडल सचिवालय	भारत सरकार (कार्य आवंटन) (एकसौग्यारवां संशोधन) नियम 1975 ।
	S.O. 412(E) dated the 2nd August, 1975.	Cabinet Secretariat	Government of India (Allocation of Business) (One Hundred and eleventh Amendment) Rules, 1975.
290.	का० आ० 413(अ) दिनांक 2 अगस्त, 1975	श्रम मंत्रालय	कृषि में नियोजित कर्मचारियों की न्यूनतम मजदूरी को पुनरीक्षित करने की प्रस्थापनाएं ।
	S.O. 413(E) dated the 2nd August, 1975.	Ministry of Labour	Proposals to revise the minimum wages of the employees employed in agriculture.
	S.O. 414(E) dated the 4th August, 1975.	Central Board of Direct Taxes.	Corrigendum to Notn. No. S.O. 615(E) dated the 17th October, 1974.
291.	का० आ० 415(अ) दिनांक 4 अगस्त, 1975	वित्त मंत्रालय	अधिसूचना सं० का० आ० 615(अ) दिनांक 17 अक्तूबर, 1974 में संशोधन ।
292	का० आ० 416 (अ), दिनांक 4 अगस्त, 1975	संचार मंत्रालय	तार यंत्र सम्बन्धी तारों के विधिविरुद्ध कब्जे के निवारण के लिये नियम, तथा तार यंत्र सम्बन्धी तार (क्रय और विक्रय) हेतु अनुज्ञा नियम, 1954 का सिक्किम राज्य में विस्तार ।
	S.O. 416 (E), dated the 4th August, 1975.	Ministry of Communications	The Rules for the prevention of Unlawful Possession of Telegraph wires, and the Telegraph wires (Permission for sale and Purchase) Rules, 1954 come into force in the State of Sikkim.
293	का०आ० 417 (अ), ई०सी०ए०/2/62, दिनांक 4 अगस्त, 1975	उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय	सीमेंट (क्वालिटी नियंत्रण) संशोधन आदेश 1975 ।
	S.O. 417 (E)/ECA/2/62, dated the 4th August, 1975.	Ministry of Industry and Civil Supplies.	The Cement (Quality Control) Amendment Order 1974.
294	का०आ० 418 (अ), दिनांक 4 अगस्त, 1975	भारत निर्वाचन आयोग	प्राउटिस्ट ब्लाक का नाम रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की सूची से निकालना ।
	S.O. 418 (E), dated the 4th August, 1975.	Election Commission of India	Deletion of the name of the Proutist Block of India from the list of registered unrecognised political party.

1	2	3	4
295.	का०आ० 419 (अ), दिनांक 5 अगस्त, 1975 S.O. 419 (E), dated the 5th August, 1975.	गृह मंत्रालय Ministry of Home Affairs	"मिजो नेशनल फ्रंट और उसके द्वारा स्थापित अन्य निकायों" का विधि विरुद्ध संगम घोषित करना । Declares the "Mizo National Front and other bodies set up by it" to be an unlawful association.
296.	का०आ० 420 (अ), दिनांक 5 अगस्त, 1975 S.O. 420 (E), dated the 5th August, 1975.	भारत निर्वाचन आयोग Election Commission of India	गुजरात राज्य से राज्य सभा के लिये निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची । List of Contesting candidates for the election to the Council of States from Gujarat State.
297.	का०आ० 421 (अ), दिनांक 5 अगस्त, 1975 S.O. 421 (E), dated the 5th August, 1975.	उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय Ministry of Industry and Civil Supplies.	सीमेंट नियंत्रण (द्वितीय संशोधन) आदेश, 1975 । The Cement Control (Second Amendment) Order, 1975.
298.	का०आ० 422 (अ) दिनांक 5 अगस्त, 1975 S.O. 422 (E), dated the 5th August, 1975.	उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय Ministry of Industry and Civil Supplies.	मैसर्स एंजिल इंडिया मशीन्स एंड टूल्स लिमिटेड, कलकत्ता का प्रबन्ध ग्रहण करने के लिये निकाय की स्थापना । Appointing a body of persons to take over the management of M/s Engel India Machines and Tools Limited, Calcutta.
299.	का०आ० 423 (अ), दिनांक 6 अगस्त, 1975 S.O. 423 (E), dated the 6th August, 1975.	वाणिज्य मंत्रालय Ministry of Commerce	निर्यात (नियंत्रण) सोलहवां संशोधन आदेश, 1975 । The Export (Control) Sixteenth Amendment Order, 1975.
300.	का० आ० 424 (अ), दिनांक 6 अगस्त, 1975 S.O. 424 (E), dated the 6th August, 1975.	वाणिज्य मंत्रालय Ministry of Commerce	निर्यात (नियंत्रण) सत्रहवां संशोधन आदेश 1975 । Export (Control) Seventeenth Amendment Order, 1975.
301.	का०आ० 425 (अ), दिनांक 8 अगस्त, 1975 S.O. 425 (E), dated the 8th August, 1975.	गृह मंत्रालय Ministry of Home Affairs	भारत रक्षा और आंतरिक सुरक्षा नियम, 1971 के प्रयोजन के लिये सेंसर की नियुक्ति । Appointment of a Censor for the purposes of the Defence and Internal Security of India Rules, 1971.
302.	का०आ० 426 (अ) दिनांक 8 अगस्त, 1975 S.O. 426 (E), dated the 8th August, 1975.	श्रम मंत्रालय Ministry of Labour	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अध्याय 4, 5, और 6 का उड़ीसा राज्य के उल्लिखित क्षेत्र पर लागू होना । The provisions of Chapters IV, V and VI of the Employees State Insurance Act, 1948 come into force in areas in the State of Orissa, as specified.
303.	का०आ० 427 (अ), दिनांक 8 अगस्त, 1975 S.O. 427 (E), dated the 8th August, 1975.	वाणिज्य मंत्रालय Ministry of Commerce	आयात (नियंत्रण) चौथा संशोधन आदेश, 1955 । The Imports (Control) Fourth Amendment Order, 1955.
304.	का०आ० 428 (अ), दिनांक 12 अगस्त, 1975 S.O. 428 (E), dated the 12th August, 1975.	दिल्ली विकास प्राधिकरण Delhi Development Authority	दिल्ली मुख्य योजना में आवासीय भूखंडों पर लागू किये जाने वाले क्षेत्रीय नियमों में संशोधन करने का प्रस्ताव । Modifications to be made to the zoning regulations applicable to residential plots in the Master Plan for Delhi.
305.	का०आ० 429 (अ), दिनांक 12 अगस्त, 1975 S.O. 429 (E), dated the 12th August, 1975.	ऊर्जा मंत्रालय Ministry of Energy	मध्य प्रदेश के सरगूजा जिले के क्षेत्र जोकि सारणी में उल्लिखित है, कोयले का पूर्वेक्षण करने के आशय की सूचना । Notice of intention to prospect for coal in area of Surguja Distt. of Madhya Pradesh, as Specified in the Schedule.
306.	का०आ० 430 (अ), दिनांक 12 अगस्त, 1975	केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड	अधिसूचना संख्या का०आ० 599 (अ) दिनांक 8 अक्तूबर, 1974 में संशोधन ।
307.	का०आ० 431 (अ), दिनांक 12 अगस्त, 1975 S.O. 431 (E), dated the 12th August, 1975.	गृह मंत्रालय Ministry of Home Affairs	आदेश सं०का०आ० 275 (ई) तारीख 26 जून, 1975 में और संशोधन । Further amendment in the Order No. S.O. 275 (E) dated the 26th June, 1975.

1	2	3	4
308	का०आ० 432 (अ), दिनांक 13 अगस्त, 1975	कृषि और सिंचाई मंत्रालय	अधिसूचना सं० का० आ० 269 (अ), दिनांक 21 जून, 1975 में अशुद्धियों का सुधार ।
309	का०आ० 433 (अ), दिनांक 13 अगस्त 1975, S.O. 433 (E), dated the 13th August, 1975.	तदेव Ministry of Agriculture and Irrigation.	अधिसूचना संख्या का०आ० 273 (अ) तारीख 23 जून, 1975 में मुद्रण अशुद्धियां ठीक करना । In Notn. No. S.O. 273 (E), dated the 23rd June, 1975 printing mistakes may be rectified.
310	का०आ० 434 (अ), दिनाक 14 अगस्त, 1975 S.O. 434 (E), dated the 14th August, 1975.	उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय Ministry of Industry and Civil Supplies.	अधिसूचना संख्या का०आ० 436 (अ), तारीख 10 अगस्त, 1973 और 490 (अ) तारीख 9 अगस्त, 1974 के साथ पठित आदेश सं० 555 (अ) तारीख 14 अगस्त, 1972 की अस्तित्वावधि को और बढ़ाना । Duration of the Notn. No. 555 (E), dated the 14th August, 1972 read with S.O. Nos 436 (E), dated the 10th August, 1973 and 490 (E), dated the 9th August, 1974 should be further extended.
311	का०आ० 435 (अ), दिनांक 14 अगस्त, 1975 S.O. 435 (E), dated the 14th August, 1975.	गृह मंत्रालय Ministry of Home Affairs	मुख्यायुक्त द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियों को अरुणाचल प्रदेश के उपराज्यपाल द्वारा प्रयोग किया जाना । Powers of the Chief Commissioner will be exercised by the Lt. Governor of Arunachal.
312	का०आ० 436 (अ), दिनांक 14 अगस्त, 1975 S.O. 436 (E), dated the 14th August, 1975.	विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय Ministry of Law, Justice and Company Affairs.	गुजरात विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिये निर्वाचन । Election to the Council of States by the elected members of the Legislative Assembly of Gujarat.
313	का०आ० 437 (अ), दिनांक 14 अगस्त, 1975 S.O. 437 (E), dated the 14th August, 1975.	विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय Ministry of Law, Justice and Company Affairs.	गुजरात राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए निर्वाचित सदस्यों के नाम । Names of the members elected by the elected members of the Legislative Assembly of Gujarat.
314	का०आ० 438 (अ), दिनांक 19 अगस्त, 1975 S.O. 438 (E), dated the 19th August, 1975.	मंत्रिमण्डल सचिवालय Cabinet Secretariat	भारत सरकार (कार्य आबंटन) (एक सौ बारहवां संशोधन) नियम, 1975 । The Government of India (Allocation of Business) (One hundred and twelfth Amendment) Rules, 1975.
315	का०आ० 439 (अ), दिनांक 20 अगस्त, 1975 S.O. 439 (E), dated the 20th August, 1975.	वित्त मंत्रालय Ministry of Finance	श्री आर० बी० प्रधान की भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति । Appointment of Shri R.B. Pradhan as Chairman of the Life Insurance Corporation of India.
316	का०आ० 440 (अ), दिनांक 21 अगस्त, 1975 S.O. 440 (E), dated the 21st August, 1975.	कृषि और सिंचाई मंत्रालय Ministry of Agriculture and Irrigation.	सारणी में विनिर्दिष्ट किस्मों के बीजों को अधिसूचित किस्में घोषित करना । Declaration of kinds of seeds to be the notified kinds of seed as specified in the table.
317	का०आ० 441 (अ), दिनांक 21 अगस्त, 1975 S.O. 441 (E), dated the 21st August, 1975.	कृषि और सिंचाई मंत्रालय Ministry of Agriculture and Irrigation	सारणी में विनिर्दिष्ट किस्मों के बीजों को अधिसूचित किस्में घोषित करना। Declaration of kinds of seeds to be the notified kinds of seed as specified in the table.
318	का०आ० 442 (अ), दिनांक 22 अगस्त, 1975 S.O. 442 (E), dated the 22nd August, 1975.	ऊर्जा मंत्रालय Ministry of Energy	अधिसूचना सं० का० आ० 408 (अ), दिनांक 1 अगस्त, 1975 में संशोधन । Amendment in Notn. No. S.O. 408 (E), dated the 1st August, 1975.
319	का०आ० 443 (अ), दिनांक 22 अगस्त, 1975 S.O. 443 (E), dated the 22nd August 1975.	उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय Ministry of Industry and Civil Supplies.	पैकेज में रखी गई वस्तु (विनियमन) आदेश 1975 । The Packaged Commodities (Regulation) Order, 1975.

1	2	3	4
320	का०आ० 444 (अ), दिनांक 23 अगस्त, 1975	वाणिज्य मंत्रालय	अधिसूचना में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को चाय बोर्ड के सदस्यों के रूप में नियुक्ति ।
	S.O. 444 (E), dated the 23rd August, 1975.	Ministry of Commerce	Appointment of persons as specified in the Notn. to be members of the Tea Board.
321	का०आ० 445 (अ), दिनांक 23 अगस्त, 1975	वित्त मंत्रालय	प्रोफेसर नितीश आर० दे को जीवन बीमा निगम के सदस्य के रूप में नियुक्ति ।
	S.O. 445 (E), dated the 23rd August, 1975.	Ministry of Finance	Appointment of Prof. Nitish R. De, as a member of Life Insurance Corporation of India.
322	का०आ० 446 (अ), दिनांक 25 अगस्त, 1975	इस्पात और खान मंत्रालय	एल्यूमिनियम (नियंत्रण) चौथा संशोधन आदेश, 1975 ।
	S.O. 446 (E), dated the 25th August, 1975.	Ministry of Steel and Mines.	The Aluminium (Control) Fourth Amendment Order, 1975.
323	का०आ० 447 (अ), दिनांक 26 अगस्त, 1975	उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय	श्री अम्बीका जूट मिल्स कलकत्ता में उत्पादन की गिरावट की जांच के लिये व्यक्तियों का निकाय नियत करना ।
	S.O. 447 (E), dated the 26th August, 1975.	Ministry of Industry and Civil Supplies.	Appointed a body of persons to investigate into circumstances of falling of Production of Shree Ambica Jute Mills, Calcutta.
324	का०आ० 448 (अ), दिनांक 26 अगस्त, 1975	वाणिज्य मंत्रालय	सारणी में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को इलायची बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्ति ।
	S.O. 448 (E), dated the 26th August, 1975.	Ministry of Commerce	Appoints the persons specified in the table to be members of Cardamom Board.
325	का०आ० 449 (अ), दिनांक 26 अगस्त, 1975	वाणिज्य मंत्रालय	निर्यात (नियंत्रण) 18वां संशोधन आदेश, 1975 ।
	S.O. 449 (E), dated the 26th August, 1975.	Ministry of Commerce	The Export (Control) Eighteenth Amendment Order, 1975.
326	का०आ० 450 (अ), दिनांक 27 अगस्त, 1975	पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय	अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण (संशोधन) नियम, 1975 ।
	S.O. 450 (E), dated the 27th August, 1975.	Ministry of Tourism and Civil Aviation.	The International Airport Authority (Amendment) Rules, 1975.
327	का०आ० 451 (अ), दिनांक 27 अगस्त, 1975	वाणिज्य मंत्रालय	निर्यात (नियंत्रण) 19वां संशोधन, 1975 ।
	S.O. 451 (E), dated the 27th August, 1975.	Ministry of Commerce	The Export (Control) Ninteenth Amendment Order, 1975.
328	का०आ० 452 (अ), दिनांक 28 अगस्त, 1975	गृह मंत्रालय	अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों का सिक्किम राज्य पर विस्तार ।
	S.O. 452 (E), dated the 28th August, 1975.	Ministry of Home Affairs	Extention to the State of Sikkim the enactments specified in the Schedule.
329	का०आ० 453 (अ), दिनांक 28 अगस्त, 1975	वाणिज्य मंत्रालय	निर्यात (नियंत्रण) इकिसवां संशोधन आदेश, 1975 ।
	S.O. 453 (E), dated the 28th August, 1975.	Ministry of Commerce	The Exports (Control) Twenty-first Amendment Order, 1975.
330	का०आ० 454 (अ), दिनांक 28 अगस्त, 1975	वाणिज्य मंत्रालय	निर्यात (नियंत्रण) बीसवां संशोधन आदेश, 1975 ।
	S.O. 454 (E), dated the 28th August, 1975.	Ministry of Commerce	The Exports (Control) Twentieth Amendment Order, 1975.
331	का०आ० 455 (अ), दिनांक 28 अगस्त, 1975	उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय	मैसर्स ब्रिटेनिया इंजीनियरिंग कम्पनी, कलकत्ता नामक उपक्रम के पुनः आरम्भ करने की संभाव्यता की जांच के प्रयोजनार्थ एक निकाय की नियुक्ति ।
	S.O. 455 (E), dated the 28th August, 1975.	Ministry of Industry and Civil Supplies.	Appoints a body to investigate the possibility of restarting the undertaking known as M/s. Britannia Engineering Company, Calcutta.

1	2	3	4
333	का०आ० 457 (अ), दिनांक 29 अगस्त 1975	गृह मंत्रालय	"विधि विरुद्ध क्रिया कलाप (निवारण) अधिकरण" गठित करना ।
	S.O. 457 (E), dated the 29th August 1975	Ministry of Home Affairs	Constitute the "Unlawful Activities (Prevention) Tribunal".
334	का० आ० 458 (अ), दिनांक 29 अगस्त 1975	उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय	कागज (संरक्षण तथा प्रयोग का विनियमन) संशोधन आदेश, 1975 ।
	S.O. 458 (E), dated the 29th August 1975	Ministry of Industry and Civil Supplies.	The Paper (Conservation and Regulation of Use) Amendment Order, 1975.
335	का०आ० 459 (अ), दिनांक 29 अगस्त 1975	श्रम मंत्रालय	कर्मचारी राज्य बीमा (संशोधन) अधिनियम, 1975 की धारा 3 से 7 तथा 9 के उपबन्ध 1 सितम्बर 1975 से लागू होना ।
	S.O. 459 (E), dated the 29th August 1975	Ministry of Labour	The provisions of Sections 3 to 7 and section 9 of the Employees State Insurance (Amendment) Act, 1975 come into force from 1st September, 1975.

मंत्रिमंडल सचिवालय

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

नई दिल्ली 30 अक्तूबर, 1975

का० आ० 4874.—केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियम, 1965 के नियम 5 के उपनियम (2) के खंड (क) के उपबन्धों के अनुसरण में तथा भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं० 59/13/65-स्थापना(क) तारीख 22 जुलाई, 1965 को जहां तक उसका सम्बन्ध मुख्य नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री से है, अधिक्रांत करते हुए केन्द्रीय सरकार नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में वर्णित प्राधिकारियों को ऐसे प्राधिकारियों के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिनके द्वारा उक्त खंड द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में ऐसे प्रत्येक प्राधिकारी के सामने उपदर्शित सीमा तक, प्रयोग किया जा सकेगा ।

सारणी

प्राधिकारी का नाम	शक्तियों की सीमा
1. निदेशक, मुद्रण	मुद्रण निदेशालय के, उन कर्मचारियों से भिन्न, जिनके नियुक्ति प्राधिकारी राष्ट्रपति हैं, कर्मचारियों के विरुद्ध नियम 5(1) के अधीन पारित आदेशों के सम्बन्ध में।
2. नियंत्रक, लेखन सामग्री	नियंत्रक लेखन सामग्री के कार्यालय के, उन कर्मचारियों से भिन्न जिनके नियुक्ति प्राधिकारी राष्ट्रपति है, कर्मचारियों के विरुद्ध नियम 5(1) के अधीन पारित आदेशों के संबंध में ।
3. नियंत्रक, प्रकाशन	नियंत्रक, प्रकाशन के कार्यालय के, उन कर्मचारियों के भिन्न, जिनके नियुक्ति प्राधिकारी राष्ट्रपति हैं, कर्मचारियों के विरुद्ध नियम 5 (1) के अधीन पारित आदेशों के संबंध में ।

[सं० 12011/2/75-स्थापना (ग)]
जे० एस० अहलुवालिया, अवर सचिव

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel & Admn. Reforms)

New Delhi, 30 October, 1975.

S.O. 4874. In pursuance of the provisions of clause (a) of sub-rule (2) of rule 5 of the Central Civil Services (Temporary Service) Rules 1965, and in supersession of notification of the Government of India, Ministry of Home Affairs No. 59/13/65-Ests (A), dated the 22nd July, 1965, in so far as it relates to Chief Controller of Printing and Stationery, the Central Government hereby specifies the authorities mentioned in column (1) of the Table below as the authorities by which the power conferred by the said clause may be exercised to the extent indicated against each such authority in column (2) of the said Table.

TABLE

Name of the Authority	Extent of powers
1. Director of Printing	In respect of orders passed under rule 5(1) against the employees of the Directorate of Printing, other than those whose appointing authority is the President.
2. Controller of Stationery	In respect of orders passed under rule 5(1) against the employees of the Office of Controller of Stationery, other than those whose appointing authority is the President.
3. Controller of Publication	In respect of orders passed under rule 5(1) against the employees of the Office of the Controller of Publication other than those whose appointing authority is the President.

[No. 12011/2/75-Ests (C)]

J. S. AHLUWALIA, Under Secy.

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 1975

शुद्धि पत्र

का० आ० 4875.—भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) पृष्ठ 3181 में 6 सितम्बर, 1975 को प्रकाशित, भारत सरकार मंत्रिमंडल सचिवालय (कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग) की अधिसूचना संख्या का०आ० 2864 तारीख 19 अगस्त, 1975 के कालम 1 पंक्ति 12 में "(संख्या 228/13/74-एवीडी-II)" के स्थान पर "(संख्या 228/13/75)" पढ़ें ।

[संख्या 228/13/75-एवीडी II]

बी०सी० वन्जानी, अवर सचिव

New Delhi, the 6th November, 1975

ERRATUM

S.O. 4875.—In the notification of the Government of India in the Cabinet Secretariat (Department of Personnel and Administrative Reforms) No. S.O. 2864 dated the 19th August, 1975, published at page 3181 of the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 6th September, 1975, in column 2, line 11, for [No. 228/13/74-AVD.II] read [No. 228/13/75-AVD.II]".

[No. 228/13/75-AVD. II]

B. C. VANJANI, Under Secy.

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 1975

का० आ० 4876.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 102-लखनऊ पश्चिम निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री चन्द्र भान सिंह, एम-1, पेपर मिल कालोनी, निशात गंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाये गये नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ।

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री चन्द्र भान सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ०प्र०-वि०स०/102/74(241)]

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 8th October, 1975

S.O. 4876.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Chandra Bhan Singh, M-1, Paper Mill Colony, Nishatganj Lucknow, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 102-Lucknow West, assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Chandra Bhan Singh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/102/74 (241)]

आदेश

का० आ० 4877.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 113-सलोन (अ०जा०) निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री राम प्यारे, ग्राम व पोस्ट ममुनी, जिला राय बरेली, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाये गये नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री राम प्यारे को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ०प्र०-वि०स०/113/74(242)]

ORDER

S.O. 4877.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ram Piyare, Village & Post Office Mamuni, District—Rae Bareli, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 113-Salon (SC) Assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

Now therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ram Piyare to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/113/74 (242)]

आदेश

का० आ० 4878.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 207-नत्थू पुर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री कामला, ग्राम बर्री सिंह पांव, पोस्ट रामपुर, जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाये गये नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री कामता को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ०प्र०-वि०स०/207/74(243)]

ORDER

S.O. 4878.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Kamta, Village Basti Bason Nidhiyawan, Post Office Rampur, District Azamgarh, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 207-Nathupur assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Kamta to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/207/74 (243)]

आदेश

का० आ० 4879.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 312-फर्रुखाबाद निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री इंगलिश भान, मुहल्ला सधवाड़ा, जिला फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाये गये नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री इंगलिश भान को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ०प्र०-वि०स०/312/74(244)]

ORDER

S.O. 4879.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri English Bhan, Mohalla Sadhwara, Farrukhabad, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 312-Farrukhabad assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri English Bhan to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/312/74 (244)]

आदेश

का० आ० 4880.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश प्रदेश विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 312-फर्रुखाबाद निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री मुनेश्वर सिंह, ग्राम व पोस्ट सबलपुर कंचनपुर, जिला फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाये गये नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने उसे सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री मुनेश्वर सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ०प्र०-वि०स०/312/74(245)]

ORDER

S.O. 4880.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Muneshwar Singh, Village and Post Office Sabalpur-Kanchanpur, District—Farrukhabhad, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 312-Farrukhabad, assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Muneshwar Singh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/312/74 (245)]

आदेश

का० आ० 4881.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 319-बांदा निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री परमात्मा दीन, ग्राम और पोस्ट गोखिया, जिला बांदा, उत्तर प्रदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाये गये नियमों द्वारा

अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री परमात्मा दीन को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ०प्र०-वि०स०/319/74(246)]

ORDER

S.O. 4881.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Parmatma Din, Village & Post Office, Gokhia, District—Banda, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 319-Banda assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Parmatma Din to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/319/74 (246)]

आदेश

का०आ० 4882.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 319-बांदा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री सुरेन्द्र नाथ, पीलीकोठी, बांदा, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाये गये नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री सुरेन्द्र नाथ को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ०प्र०-वि०स०/319/74(247)]

ORDER

S.O. 4882.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Surendra Nath, Pilikothi, Bandra, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 319-Banda assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Surendra Nath, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/319/74 (247)]

आदेश

का० आ० 4883.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 324-चरखारी (अ०जा०) निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री कलुआ, ग्राम व पोस्ट कल्पहार, जिला हमीरपुर, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा तद्धीन बनाये गये नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री कलुआ को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ०प्र०-वि०स०/324/74(248)]

ORDER

S.O. 4883.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Kalua, Village Post Kalpahar, District—Hamirpur, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 324-Charkhari (SC) assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Kalua to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/324/74 (248)]

आदेश

का०आ० 4884.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 324-चरखारी (अ०जा०) निर्वाचन -क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री राम नाथ ग्राम व पोस्ट काशीपुर, जिला हमीरपुर, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाये गये नियमों द्वारा अपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्ययोचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री राम नाथ को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ० प्र०-वि०स०/324/74(249)]

ORDER

S.O. 4884.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ram Nath, Village Post Kashipur, District—Hamirpur, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 324-Charkhari (SC) assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ram Nath, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/324/74 (249)]

आदेश

का०आ० 4885.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 325-महोबा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्रीमती ज्योतिर्मयी, हुसैनगंज वार्ड नं० 5, लखनऊ उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, तथा तद्धीन बनाये गये नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्ययोचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्रीमती ज्योतिर्मयी को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ०प्र०-वि०स०/325/74(250)]

ORDER

S.O. 4885.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shrimati Jyotirmayi, Hussainganj, Ward No. 5, Lucknow, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 325-Mahoba assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shrimati Jyotirmayi to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/325/74 (250)]

आदेश

का०आ० 4886.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिय 325-महोबा निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री शम्भू दयाल, छजमनपुरा मोहल्ला महोबा, जिला हमीरपुर, उत्तर प्रदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाये गये गये नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिय जाने र पर भी, अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिय कोई पर्याप्त कारण या न्ययोचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री शम्भु दयाल को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ० प्र०-वि०स०/325/74(251)]

ORDER

S.O. 4886.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Shambhu Dayal, Chhajmanpura, Mahoba, District—Hamirpur, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 325-Mahoba, assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Shambhu Dayal to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/325/74 (251)]

आदेश

का०आ० 4887.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 328-झांसी निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री नूर बक्स, निवासी 35/36 सिलवर्ट गंज, झांसी, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाये गये नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री नूर बक्स को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद्, के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ०प्र०-वि०स०/328/74(252)]

ORDER

S.O. 4887.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Noor Bux, Resident of 35/36, Silvartganj jhansi, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 328-Jhansi, assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Noor Bux to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/328/74 (252)]

आदेश

का०आ० 4888.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 195-राम कोला निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री सुशील कुमार, ग्राम व पोस्ट राम कोला, जिला देवरिया, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाये गये नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री सुशील कुमार को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद्, के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ०प्र०-वि०स०/195/74(253)]

ORDER

S.O. 4888.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Sushil Kumar, Village & Post Office Ramkola, District Deoria, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 195-Ramkola assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Sushil Kumar to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/195/74 (253)]

आदेश

का० आ० 4889.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिये साधारण निर्वाचन के लिये 195-राम कोला निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री हरि वंश, पो० राजाबाजार खड्डा, जिला देवरिया, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाये गये नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों को कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री हरि वंश को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद्, के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ०प्र०-वि०स०/195/74(254)]

ORDER

S.O. 4889.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Haribans, Post Raja Bazar Khadda, District Deoria, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 195-Ramkola, assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Haribans to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/195/74 (254)]

का०आ० 4890.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग, महाराष्ट्र सरकार के परामर्श से अवकाश प्राप्त श्री के० ए० गफूर के स्थान पर श्री एच० नंजुंदिया, महाराष्ट्र सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से महाराष्ट्र राज्य के लिये मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में एतद्द्वारा नाम निर्देशित करता है।

[सं० 154/महाराष्ट्र/75]

S.O. 4890.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 10A of the Representation of the People Act, 1950 (48 of 1950), the Election Commission of India, in consultation with the Government of Maharashtra, hereby nominates Shri H. Nanjundiah, Additional Chief Secretary to the Government of Maharashtra, as the Chief Electoral Officer for the State of Maharashtra with effect from the date he takes over charge vice Shri K. A. Gafoor retired.

[No. 154/MT/75]

आदेश

नई दिल्ली, 10 अक्तूबर, 1975

का० आ० 4891.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 43-बिल्सी (अ० जा०) निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री रघुनाथ ग्राम पडउआ, जिला बदायूं उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री रघुनाथ को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ०प्र०-वि०स०/43/74(257)]

ORDER

New Delhi, the 10th October, 1975

S.O. 4891.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Raghunath, Village Paruya, District—Budaun, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 43-Bilsi (SC) assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Raghunath to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/43/74 (257)]

आदेश

का० आ० 4892.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 176-मेहुंदावल निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री मजहर अली, डा० मेहुंदावल, टोला बरगदही, जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री मजहर अली को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ०प्र०-वि०स०/176/74(260)]

ORDER

S.O. 4892.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Mazhar Ali, Post office Mendhawal, Tola Bargadhi, District Basti, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 176-Mendhawal, assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Mazhar Ali to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/176/74 (260)]

आदेश

का० आ० 4893:—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 183-मुंडेरा बाजार (अ० जा०) निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री रामपति, ग्राम रामपुरा, पोस्ट ब्रह्मपुर, जिला गोरखपुर उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री रामपति को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ० प्र०-वि० स०/183/74(261)]

ORDER

S.O. 4893.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Rampati, Village Rampur, Post Office Brahmpur, District Gorakhpur, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 183-Mundera Bazar (SC) assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Rampati to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of their order.

[No. UP-LA/183/74 (261)]

आदेश

का० आ० 4894 :—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 183-मुंडेरा बाजार (अ० जा०) निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री शिव शरन प्रसाद, ग्राम भोपाबाजार, पो० चौरी, जिला गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तदधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री शिव शरन प्रसाद को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ० प्र०-वि० स०/183/74(262)]

ORDER

S.O. 4894.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Sheo Sharan Prasad, Village Bhopa Bazar, Post Office Chauri Chaura District Gorakhpur, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 183-Mundera Bazar (SC) assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Sheo Sharan Prasad to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/183/74 (262)]

आदेश

का० आ० 4895 :—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 186-मानी राम निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री सतई, ग्राम व पोस्ट बशारतपुर, जिला गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों को कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10 के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री सतई को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[स०उ०प्र०-वि०सा०/186/74(263)]

ORDER

S.O. 4895.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Satai, Village and Post Office Basharatpur, District—Gorakhpur, Uttar Pradesh, a contesting candidate for

election to the U.P. Legislative Assembly from 196-Maniram assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Satai to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/186/74 (263)]

आदेश

का० आ० 4896.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 333-उरई निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री रघुबीर शरन, ग्राम पोस्ट खरी, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों को कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है; और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री रघुबीर शरन को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ०प्र० वि०स०/333/74(264)]

ORDER

S.O. 4896.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Raghuvir Saran, Village Post Kharra, District Jalaun, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 333-Orai assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Raghuvir Saran to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/333/74 (264)]

आदेश

का० आ० 4897. यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 334-कालपी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री बद्री प्रसाद, ग्राम हरीपुरा, पो० जाम्मनपुर, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों को कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री बद्री प्रसाद को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ०प्र०-वि०स०/334/74(265)]

ORDER

S.O. 4897.—Whreas the Election Commission is satisfied that Shri Badri Prasad, Village Haripura, Post Jagammanpur, District Jalaun, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 334-Kalpi assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Badri Prasad, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/334/74(265)]

आदेश

का० आ० 4898.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 336-भोंगाव निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री जबर सिंह यादव, नगला सुखू डाकघर भोंगाव, जिला मैनपुरी, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों को कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री जबर सिंह यादव को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ०प्र० वि०स०/336/74(266)]

ORDER

S.O. 4898.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Jaber Singh Yadav, Nagla Sukhoo, Post Office Bhongaon, District—Mainpuri, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 336-Bhongaon, assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Jaber Singh Yadav to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/336/74 (226)]

आदेश

का० आ० 4899:—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 336-भोंगांव निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री राधे श्याम, ग्राम परतापपुर, डाकघर भोंगांव, जिला मैनपुरी, उत्तर प्रदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों को कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री राधे श्याम को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ० प्र०-वि० स०/336/74/(267)]

ORDER

S.O. 4899.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Radhey Shyam, Village Partappur, Post Bhongaon, District—Mainpuri, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 336-Bhongaon assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Radhey Shyam, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/336/74 (267)]

आदेश

का० आ० 4900:—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 336-भोंगांव निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री राम भरोसे सिंह, ग्राम श्यामपुर भटपुरा, डाकघर मैनपुरी, जिला मैनपुरी, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों को कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री राम भरोसे सिंह को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ० प्र०-वि० सं०/336/74/(268)]

ORDER

S.O. 4900.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ram Bharosey Singh, Village Shyampur Bhatpura, Post Office Mainpuri, District, Mainpuri, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 336-Bhongaon, assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ram Bharosey Singh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/336/74 (268)]

आदेश

का० आ० 4901:—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 337-किशनी (अ० जा०) निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री नेकसू, ग्राम हेरा, डाकघर अजीत गंज, जिला मैनपुरी, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री नेकसू को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ० प्र०-वि० स०/337/74/(269)]

ORDER

S.O. 4901.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Naksoo, Village Hira, Post Office Ajeetganj, District, Manipur, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 337-Kishni (SC) assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Naksoo to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/337/74 (269)]

आदेश

का० आ० 4902 :—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 337-किशनी (अ० जा०) निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री वीरेन्द्र, ग्राम बैधेरुआ, डाकघर सुगांव, जिला मैनपुरी, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री वीरेन्द्र को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ० प्र०-वि० स०/337/74(270)]

ORDER

S.O. 4902.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Virendra, Village Baghirua, Post Office Sugaon, District, Manipuri, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 337-Kishni (SC) assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

An whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Virendra to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/337/74 (270)]

आदेश

का० आ० 4903:—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 337-किशनी (अ० जा०) निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार, श्री हरी बक्स, ग्राम व पोस्ट कैथोली, जिला मैनपुरी, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री हरी बक्स को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ० प्र०-वि० स०/337/74(271)]

ORDER

S.O. 4903.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Hari Bux, Village and Post Office Kaithauli, District, Mainpuri, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 337-Kishni (SC) assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Hari Bux to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/337/74 (271)]

आदेश

का० आ० 4904 :—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि फरवरी, 1974 में हुए उड़ीसा विधान सभा के निर्वाचन के लिए कटक सदर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री नरेन्द्र कुमार साहू, ग्राम सिंघालो, पत्रालय खलारदा, कटक (उड़ीसा), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यत, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री नरेन्द्र कुमार साहू को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उड़ीसा वि० स०/43/74]

ORDER

S.O. 4904.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Narendra Kumar Sahoo, Village Singhalo, P.O. Khalarda, Cuttack (Orissa), a contesting candidate for election to the Orissa Legislative Assembly from Cuttack Sadar constituency, held in February, 1974 has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after the due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Narendra Kumar Sahoo to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. OR-LA/43/74]

आदेश

नई दिल्ली, 15 अक्तूबर, 1975

का० आ० 4905.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 16-काशीपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री असलम खाँ, असलम भवन, रामपुर, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री असलम खाँ को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ० प्र०-वि० सं/16/74(272)]

ORDER

New Delhi, the 15th October, 1975

S.O. 4905.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Aslam Khan, Aslam Bhawan, Rampur, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. legislative Assembly from 16-Kashipur, Assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

Now therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Aslam Khan to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/16/74 (272)]

आदेश

का० आ० 4906.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के साधारण निर्वाचन के लिए 29-बहजोई निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री सतेन्द्र सिंह, ग्राम व पोस्ट पंबासा, सम्भल, जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री सतेन्द्र सिंह को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ० प्र०-वि० स०/29/74/(273)]

ORDER

S.O. 4906.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Satendra Singh, Village & Post Office Panbasa, Sambhal, District, Moradabad, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U. P. Legislative Assembly from 29-Bahjoi, assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

Now therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Satendra Singh to be disqualified for being, chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/29/74 (273)

आदेश

का० आ० 4907.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 49-बिसौली निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री सुलतान अली पो० ग्राम एचौली, जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री सुलतान अली को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ० प्र०-वि० स०/40/74(274)]

ORDER

S.O. 4907.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Sultan Ali, Village & Post Office, Aincholi, District Moradabad, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 40-Bisauli, assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

Now therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Sultan Ali, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/40/74(274)]

आदेश

का० आ० 4908.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 42-सहसवान निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री अशर्फी लाल, ग्राम व डाकखाना दहगवां, जिला बदायूं उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री अशर्फी लाल को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ० प्र०-वि० स०/42/74(275)]

ORDER

S.O. 4908.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Asharfi Lal, Village & Post Office Dahgawan, Dist. Budaun, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U. P. Legislative Assembly from 42-Sahaswan, assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

Now therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Asharfi Lal to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/42(275)]

आदेश

का० आ० 4909.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 38-बिलासपुर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री नाजर सिंह, ग्राम नगरी, तहसील बिलासपुर, जिला रामपुर, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा रीति से दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः उक्त उम्मीदवार के अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री नाजर सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ० प्र०-वि० स०/38/74(276)]

ORDER

S.O. 4909.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Nazar Singh, Village Gokul Nagri, Tahsil Bilaspur, District—Rampur, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U. P. Legislative Assembly from 38-Bilaspur, assembly constituency, has failed to lodge his account of election expenses in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas after considering the representation of the said candidate the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

Now therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Nazar Singh, to be disqualified for being chosen

as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/38/74(276)]

आदेश

का० आ० 4910.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 338-करहल निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री राम सनेही लाल, ग्राम तरोलिया, पो० आ० कुर्रा, जिला मैनपुरी, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री राम सनेही लाल को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ० प्र०-वि० स०/338/74(277)]

ORDER

S.O. 4910.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ram Sanehi Lal, Village Tarolia, P.O. Kurra, District—Mainpuri, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U. P. Legislative Assembly from 338-Karhal, assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ram Sanehi Lal to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/338/74 (277)]

आदेश

का० आ० 4911.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 338-करहल निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री राधे लाल, ग्राम पशुपुर, पोस्ट आफिस मोहब्बतपुर, जिला मैनपुर, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाये गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री राधे लाल को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ० प्र०-वि० स०/338/74(278)]

ORDER

S.O. 4911.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Radhey Lal, Village Pashupur, P.O. Mohabbatpur, District—Mainpuri, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 338-Karhal, assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

Now therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Radhey Lal to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/338/74(278)]

आदेश

का० आ० 4912.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 338-करहल निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री मुन्ना लाल, ग्राम व पोस्ट बरनाहल, जिला मैनपुरी, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री मुन्ना लाल को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ० प्र०-वि० स०/338/74(279)]

ORDER

S.O. 4912.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Munna Lal, Village and Post Office Bernahal, District—Mainpuri, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U. P. Legislative Assembly from 338-Karhal, assembly constituency, has failed to lodge an account of his

election expenses in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

Now therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Munna Lal to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/338/74(279)]

आदेश

नई दिल्ली, 15 अक्तूबर, 1975

का० आ० 4913.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 36-स्वार टान्डा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री राम पाल सिंह, ग्राम चन्दुपरी, डा० लाम्बा खेड़ा, तहसील स्वार जिला रामपुर, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा रीति से दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री राम पाल सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ० प्र०-वि० स०/36/74(280)]

ORDER

New Delhi, the 16th October, 1975

S.O. 4913.—Whereas the Election Commission is satisfied Shri Ram Pal Singh, Village Chandupuri, P.O. Lamba Khera, Tahsil Suar, District-Rampur, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 36-Suar Tanda, assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

Now therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ram Pal Singh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/36/74(280)]

का० आ० 4914.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 36-स्वार टान्डा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री अब्दुल अजीज खां, मोहल्ला सराय सआदत यार खां, रामपुर, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री अब्दुल अजीज खां को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ० प्र०-वि० स०/36/74(281)]

ORDER

S.O. 4914.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Abdul Aziz Khan, Mohalla Sarai Sadat Yar Khan Ram pur, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 36-Suar Tanda, assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

Now therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Abdul Aziz Khan, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/36/74(281)]

आदेश

का० आ० 4915.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 36-स्वार टान्डा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री रिसालत खां, मुहल्ला काशीपुर, तहसील स्वार, जिला रामपुर, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री रिसालत खां को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य

चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ प्र०-वि० स०/36/74 (282)]

ORDER

S.O. 4915.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Risalat Khan, Mohalla Kashipur, Tahsil Suar, District—Rampur, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 36-Suar Tanda, assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after dute notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Risalat Khan to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/36/74 (282)]

आदेश

नई दिल्ली, 17 अक्तूबर, 1975

का० आ० 4916.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 340-जसराना निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री महेन्द्र मुदगल, ग्राम व पोस्ट आफिस, पाढम, जिला मैनपुरी, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री महेन्द्र मुदगल को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ० प्र०-वि० स०/340/74 (283)]

ORDER

New Delhi, the 17th October, 1975

S.O. 4916.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Mahendra Mudgal, Village and Post Office Padham, District Mainpuri, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 340-Jasrana, assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

3. Now therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Mahendra Mudgal, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/340/74 (283)]

आदेश

का० आ० 4917.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 340-जसराना निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्रीमती विमलेश यादव, ग्राम व पोस्ट पेंढत, तहसील जसराना, जिला मैनपुरी, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्रीमती विमलेश यादव को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ० प्र०-वि० स०/340/74 (284)]

ORDER

S.O. 4917.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shrimati Vimlesh Yadav, village and Post Office Pendhat, District Mainpuri, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U. P. Legislative Assembly from 340-Jasrana, assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said mati Vimlesh Yadav to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislaive Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/340/74(284)]

आदेश

का० आ० 4918.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 341-घिरोर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री राम सिंह, ग्राम श्यामनगर मौजा पटसुई, पो० आ० अमोर, मगला, औछन, जिला मैनपुरी, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951

तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री राम सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ० प्र०-वि० स०/341/74 (285)]

S.O. 4918.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ram Singh, Village Shyam Nagar, Mauja Patsui, P.O. Amor, Nagla Jeewan District-Mainpuri, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 341-Ghiror, Assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ram Singh, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/341/74 (285)]

आदेश

का० आ० 4919—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 342-मैनपुरी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री पुहुप सिंह, ग्राम पीरपुर, पो० आ० सिकन्दरापुर, जिला मैनपुरी, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री पुहुप सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ० प्र०-वि० स०/342/74 (286)]

ORDER

S.O. 4919.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Puhup Singh, Village Pirpur, P.O. Sikandrapur, District Mainpuri, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 342-Mainpuri, assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Puhup Singh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/342/74 (286)]

आदेश

का० आ० 4920.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 44-पटियाली निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री राम स्वरूप पुत्र श्री बेनी राम, मोहल्ला जटवन टाऊन एरिया, सहावर, जिला ऐटा, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री राम स्वरूप को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ० प्र०-वि० सं०/344/74 (287)]

ORDER

S.O. 4920.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ram Swaroop, S/o Shri Beni Ram, Mohalla Jatavan Town Area Sahawar, Distt. Etah, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 344-Patiali, Assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ram Swaroop S/o Shri Beni Ram to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/344/74 (287)]

आदेश

का० आ० 4921.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 344-पटियाली निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री राम स्वरूप पुत्र श्री भवानी, मोहल्ला जटवन, टाऊन एरिया, सहावर जिला एटा, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री राम स्वरूप पुत्र श्री भवानी को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ० प्र०-वि० स०/344/74(288)]

ORDER

S.O. 4921.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ram Swaroop Son of Shri Bhawani, Mohalla Jatwan, Town Area Sahawar, District Etah, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U. P. Legislative Assembly from 344-Patiali assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ram Swaroop S/o Shri Bhawani to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/344/74 (288)]

आदेश

का० आ० 4922.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 345-सकीट निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री गिरिन्द, ग्राम मुजफ्फर नगर गिरौन्दी डाकघर कंगरोल जिला एटा उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री गिरन्द को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ० प्र०-वि० स०/345/74 (289)]

ORDER

S.O. 4922.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Girand, Village Muzaffarpur, Hirodi, Post Kangrol, District Etah, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 345-Sakit, assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Girand to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/345/74 (289)]

आदेश

का० आ० 4923.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 347-कासगंज निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री तेज सिंह, ग्राम नसरतपुर, पो० नदरई, जिला एटा, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री तेज सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ० प्र०-वि० स०/347/74 (290)]

ORDER

S.O. 4923.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Tej Singh, Village Nasaratpur, Post Office Nadrai, District Etah, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 347-Kasganj, assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Tej Singh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[NO. UP-LA/347/74 (290)]

आदेश

का० आ० 4924.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 347-कासगंज निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री मानपाल, ग्राम क्यामपुर, बेहटिया, पो० आ० खास, जिला एटा, उत्तर देश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल हैं ;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री मानपाल को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ० प्र०-वि० स०/347/74 (291)]

ORDER

S.O. 4924.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Man Pal, Village Kyampur Bahedia, Post Office Khas, District-Etah, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 347-Kasganj, assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

2. And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

3. Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Man Pal to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/347/74 (291)]

आदेश

नई दिल्ली, 18 अक्तूबर, 1975

का० आ० 4925.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 17-सेवहारा निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री चन्द्रपाल सिंह, ग्राम अजुपुराजट, पो० हीमपुर दीपा, जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यत : उक्त उम्मीदवार ने उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस फलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री चन्द्र पाल सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ० प्र०-वि० स०/17/74 (298)]

ORDER

New Delhi, the 18th October, 1975

S.O. 4925.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Chandra Pal Singh, Village Ajupura Jat, Post Office Heempur Deepa, District-Bijnor, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 17-Seohara, assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Chandra Pal Singh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/17/74 (298)]

आदेश

का० आ० 4926.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 355 एत्मादपुर (अ० जा०) निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री पंचमसिंह, ग्राम समोगर, पो० आ० नगला सिवाला, आगरा, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययो का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नही है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री पंचमसिंह को संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० उ० प्र०-वि० सं०/355/74 (300)]

ORDER

S.O. 4926.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Pancham Singh, Village Samogar, Post Office Nagla Siwala, Agra,Uttar Pradesh, a contesting candidate for electtion to the U.P. Legislative Assembly from 355-Etmadpur(SC) assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Pancham Singh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/355/74 (300)]

आदेश

का०आ० 4927.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए निर्वाचन के लिए 353-फतेहाबाद निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री कृष्ण चन्द्र पुत्र श्री कासी प्रसाद, कस्बा व डाकघर फतेहाबाद, आगरा, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण अथवा न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री कृष्ण चन्द्र को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ० प्र०-वि० स०/353/74 (303)]

ORDER

S.O. 4927.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Kishan Chandra, S/o Shri Kali Prasad, Town and Post Office Fatehabad, Agra, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 353-Fatehabad assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Kishan Chandra S/o Shri Kali Prasad to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/353/74 (303)]

आदेश

का० आ० 4928.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 353-फतेहाबाद निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री देवी राम पुत्र श्री विद्या राम, कस्बा व डाकघर फतेहाबाद, आगरा, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री देवी राम पुत्र श्री विद्याराम को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ० प्र०-वि० स०/353/74 (304)]

ORDER

S.O. 4928.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Devi Ram, S/o Shri Vidya Ram, Town and Post Office Fatehabad, Agra, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 353-Fatehabad, assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Devi Ram to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/353/74 (304)]

आदेश

का० आ० 4929.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1971 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 353-फतेहाबाद निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री नत्थी लाल, पुत्र श्री ग्यानी राम, ग्राम मुरावल, डा० भलोखरा, तहसील फतेहाबाद, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री नत्थी लाल को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ० प्र०-वि० स०/353/74 (305)]

ए० एन० सैन, सचिव

ORDER

S.O. 4929.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Nathi Lal, S/o Shri Gyani Ram, Village Murawal, P. O. Bhalokhra, Tahsil Fatehabad, Distt. Agra, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 353-Fatehabad assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Nathi Lal to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/353/74 (305)]

A. N. SEN, Secy.

नई दिल्ली, 17 अक्तूबर, 1975

का० आ० 4930.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग यह निदेश देता है कि उसकी अधिसूचना सं० 434/केरल/74(4), तारीख 18 नवम्बर, 1974 में निम्नलिखित संशोधन और किए जाएंगे, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से सारणी के स्तम्भ 2 में मद सं० 5 के सामने, क्रम सं० 4 पर विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर "4 अपर उप-कलक्टर (भूमि सुधार I), मालापुरम" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी।

[सं० 434/केरल/75 (4)]

वी० नारसुब्रमण्यन, सचिव

New Delhi, the 17th October, 1975

S.O. 4930.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby directs that the following further amendment shall be made in its notification No. 434/KL/74(4), dated 18 November, 1974 namely:—

In column 2 of the Table appended to the said notification, for the existing entry at Serial No. 4 against item No. 5, the entry "4 Additional Deputy Collector (Land Reforms-I), Malappuram", shall be substituted.

[No. 434/KL/75(4)]

New Delhi, the 20th October, 1975

S.O. 4931.—In pursuance of clause (b) of sub-section (2) of section 116C of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby publishes the order of the Supreme Court of India dated 19th September, 1975, on an appeal from the Judgment and order dated 10 April, 1973 of the High Court of Punjab and Haryana in Election Petition No. 1 of 1971.

IN THE SUPREME COURT OF INDIA

CIVIL APPELLATE JURISDICTION

Civil appeal No. 1172 of 1973

S. Iqbal Singh — Appellant

Versus

S. Gurdas Singh & Ors. — Respondents

JUDGMENT

ALAGIRISWAMI. J.

This appeal relates to the election to the Parliament from the Fazilka constituency in Punjab held on 5th March, 1971. The Parliamentary constituency consisted of eight assembly constituencies of Malout, Muktsar, Gidderbha, Fazilka, Jalalabad, Abohar, Lambi and Faridkot. The voters were counted on 10th and 11th of March at five different places. The counting of the votes of the Malout Assembly Constituency was held on 10th March by Mr. Aggarwal, Assistant Returning Officer, of Muktsar and Gidderbha on 10th and 11th by Mr. Sayal ,of Fazilka and Jalalabad on the 10th and 11th by Mr. Mahajan, of Lambi and Abohar on the 10th and 11th by Mr. Ram Lal and of Faridkot on the 11th by Mr. Garg. 6,409 votes were declared invalid and the 1st respondent was declared elected having secured 1,52,677 votes. The appellant obtained 1,47,354 votes. There were six other candidates about whom it is not necessary to refer.

A number of allegations were made in the election petition about many irregularities that took place on the date of the polling. It is not necessary to refer to them as the issues concerned with them were not pressed even before the High Court. Only two issues, issue 1 and 4 were considered by the High Court and those are the issues urged before us also. They are:

"1. Whether the respondent No. 1 is guilty of corrupt practices specified in paras 19, 20, 22 and 23 and 26 to 29 of the election petition as amended? If so, what is the effect?

2. Whether 15000 ballot papers were invalid and were wrongly polled and counted? If so, with what effect?"

It is also necessary to refer to issues 3 and 6 for they have some relevance in discussing issues 1 and 4 :

"3. Whether the petitioner is entitled to the scrutiny of the ballot papers alleged to have been illegally rejected and those of the respondent alleged to have been illegally accepted and on that account is entitled to a recount?

6. Whether the allegations made in para 7 of the petition are correct, and if so, what is the effect ?"

As issue 6 was not pressed the various allegations of irregularities at the time of polling including collusion by Polling Officers and consequent false voting and stuffing of ballot boxes could not be considered. As issue 3 was not pressed recount cannot be asked for on the allegation of wrong counting of votes that is that the appellant's votes were wrongly rejected and the 1st respondent's votes were wrongly accepted.

With regard to issue 1 the allegation as that corrupt practice of bribery was committed in the interest of the 1st respondent by his brother Shri Parkash Singh Badal, who was at that time the Chief Minister of Punjab. One of the items of bribery alleged was that large sums of

money were distributed to Harijans in the form of contributions towards construction of Dharamshalas for the purpose of inducing them to vote in favour of the 1st respondent. The second allegation was that Shri Parkash Singh Badal directed Mr. Sayal, one of the Assistant Returning Officer, to issue 3,304 gun licences for furthering the prospects of the 1st respondent's election and that this was a gratification for inducing the electors to vote for the 1st respondent. Similarly Mr. O. P. Garg, another Assistant Returning Officer was alleged to have issued 485 gun licences in the months of February and March, 1971. Shri Parkash Singh Badal was alleged to have arranged and addressed a number of meetings in various villages promising to help the voters in many ways if they would vote for his brother. There were certain other allegations of corrupt practices but the only ones canvassed before us were those relating to gun licences and grants in respect of construction of dharamshalas to Harijans.

The allegations which relate to issue 4, as found in the petition, were that at least 15,000 invalid and void votes had been included and counted in favour of the returned candidate, which should have been rejected and not counted at all and that in addition at least 3,000 invalid ballot papers which should have been rejected under rule 56 had been wrongly counted as valid votes in favour of the returned candidate. The distinction between 15,000 and 3,000 votes was this: The 15,000 ballot papers were said to consist of (i) spurious ballot papers, (ii) ballot papers not bearing serial number or design authorised for use at the particular polling stations, and (iii) ballot papers not bearing both marks and the full signatures of the Presiding Officer. The 3,000 ballot papers were said to have been so marked as to render it doubtful to which candidate the vote is given, or the ballot papers bore marks with instrument other than the one supplied for the purpose, or ballot papers marked in favour of more than one candidate had been wrongly counted in favour of the returned candidate. No evidence in fact was let in in respect of the 3,000 votes. The attack was concentrated on the 15,000 invalid and void votes. In view of issues 3 and 6 having been given up, the effect of which we have earlier referred to, the only question that arises is whether these 15,000 votes should not have been counted at all, whether for the appellant or for the 1st respondent on the basis that they bore neither the stamp nor the signature of the Polling Officer.

The whole of the evidence let in was of a uniform type that a number of ballot papers did not bear the signature of the Polling Officer or the stamp of the booth. Indeed the allegation in the petition on this point is "ballot papers not bearing booth marks and full signatures of the Presiding Officer were wrongly counted as valid votes". It is not said that the ballot papers bore neither the mark nor the signature of the Presiding Officer. The rule in question, rule No. 56, was amended in 1971 providing that only a ballot paper which did not contain both the mark and signature would be deemed invalid but even then it is not as though it automatically became invalid. The Returning Officer had to scrutinise it in order to see whether the ballot paper was a genuine ballot paper. This provision was apparently put in because under pressure of work the Polling Officer might have failed either to affix the stamp or his signature. If the Returning Officer was satisfied that the failure to affix the stamp or the signature was due to the fault of the Polling Officer but the ballot paper was itself genuine he could include it among the valid ballot papers. Therefore, merely by giving evidence that the ballot papers did not contain both the signature and the stamp it would not be established that the ballot paper concerned was not a valid ballot paper. But that is the only type of evidence which has been let in.

Apart from this the number 15,000 seems to be a case of wild guess. The appellant's voting agents were alleged to have kept a note of the number of invalid ballot papers that they had noticed but none was produced. Some of the counting agents gave evidence that they brought it to the notice of the chief counting agent who sat on the dais along with the Assistant Returning Officer at the time of the counting. Neither the counting agents nor the chief counting agent had complained in writing to the Assistant Returning Officer. It is impossible to believe that if there were as many as 15,000 invalid ballot papers, which amount to about two thousand from every assembly constituency they would have kept quiet without raising hell. On both the days of counting an observer deputed by the Election Commissioner had gone round all the places where the votes were counted. No serious infirmities were pointed out to him. One or two ballot papers which did not bear either the signature of the Polling Officer or the stamp were shown to him only in the Lambi constituency and he scrutinised them and found that the serial numbers tallied and he was satisfied about their genuiness. He as well as the various Assistant Returning Officers had offered that if there were any complaints the candidate could ask for a recheck. No such recheck was asked for. It was argued on behalf of the appellant that the recheck offer meant only a check on whether the number of votes had been correctly added. We find it impossible to accept this suggestion. The reference to the checking in the observer's report shows that the checking meant also scrutiny as to whether the ballot paper was signed by the Presiding Officer. The Returning Officer has also mentioned in his order on the application made by the appellant for a recount that he was asked to specify as to whether in any assembly segment he or any of his agents had asked for the recheck or pointed out any discrepancy in the figures and that the appellant had failed to cite any such specific instance, and that he was also asked as to whether he wanted the recounting of any specific assembly segment but he relterated that he wanted a total recount.

Four of the Assistant Returning Officers, Mr. Sayal, Mr. Ram Lal, Mr. Garg and Mr. Aggarwal have been examined and they did not support the appellant's case that there were such a large number of invalid ballot papers or that it was brought to their notice even orally. Mr. Ram Lal said that at the most there might be 200 such votes which were objected to; that is in respect of the two constituencies in which he was the Assistant Returning Officer. This would mean that there might have been about one thousand invalid ballot papers at the most and we have already mentioned that 6,409 had been declared invalid. We do not know how many of them were ballot papers which did not contain either the signature or the stamp.

The way the appellant's case has been developed is also very interesting. We have pointed out that votes of four constituencies were counted on the 10th and of four other constituencies on the 11th. The first move of the appellant was to send a telegram on the 11th. By that time half the number of votes had been counted and probably more than half because we do not know at what time on the 11th telegram, Ex. B-2 was sent. Even assuming that nearly half the number of votes had been counted the appellant probably had an inking of the possibility of his being defeated. In this telegram he referred to about fifteen thousand ballot papers which did not contain either the signature of the Presiding Officer or the Polling Officer of the polling station and booth numbers. He also mentioned that about six thousand three hundred votes had been wrongly rejected. Apparently he wanted to imply that they would otherwise have gone in his favour. But his case of six thousand votes which ought to have gone to him, but had been wrongly rejected, had been completely given up later. another telegram sent on the 13th March, 1971 was similar to the telegram sent on the 11th. A similar telegram was sent by the appellant to the General Secretary of the Congress Party as also the Prime Minister. But in the petition given to the Returning Officer asking for a recount on the same day the complaint was that some of the ballot papers did not bear the official stamp on their back as provided by rules and they seem to have been smuggled illegally and the number given is "thousand". Another complaint was some of the ballot papers did not bear the signatures of the Presiding Officers on the back, which were also "in thousands" and even more than five thousand. So here we do not find the allegation that the ballot papers contained neither the signature nor the stamp. In this petition before the Election Commission asking for recount he mentioned

fifteen thousand ballot papers as having been found which bore no distinction mark or signature of the Presiding Officer. He also mentioned the rejection of more than 6,000 votes. As we have already pointed out, there is absolutely nothing on record to show how the figure 15,000 was arrived at. We are, therefore, satisfied that the mention about 15,000 votes, 3,000 votes and 6,000 votes are only steps in the attempt to secure a recount at any cost and to fish for evidence. As we have already pointed out, the allegation in the petition was that 15,000 invalid votes were counted in favour of the returned candidate but in the evidence as well as the arguments it was only claimed that there were 15,000 invalid ballot papers which were counted. There is nothing to show how many of these 15,000 went to the appellant and how many to the 1st respondent. Indeed as we have earlier explained that was asked for was elimination of the 15,000 votes altogether from the counting. The whole thing is there kite flying. We are, therefore, in agreement with the learned Judge of the High Court that the appellant has not succeeded in establishing the allegations covered by issue No. 4.

There are a large number of decision of this Court on the question regarding the circumstances under which recount can be ordered. It has been recognised in all those decisions that there can never be any hard and fast rule as to the circumstances when an order of recount would be permissible and should always be dependent upon the circumstances of the case. We do not therefore consider it necessary to refer to any of those decisions. Suffice it to say that the facts of this case do not leave even the slightest justification for ordering a recount.

Now we come to the question of corrupt practice. We shall first of all deal with the grant for construction of dharamshalas for Harijans. The Punjab Government appears to have set apart a sum of Rs. 50,00,000 for this very purpose. All that is established is that a sum of Rs. 3,00,000 was spent towards the end of the official financial year 1970-71 in the district in which this Fazilka Parliamentary Constituency is situate. Punjab has 11 districts and it cannot therefore be said that this sum is disproportionately large. The anxiety to spend the money towards the end of the financial year is also natural. If the end of the financial year also happens to be the period when an election is going on parties in power naturally bestir this to show that they are active in helping the people to get what they want. The election time is the time when people in power as well as ordinary politicians are active in trying to show that they are out to help the people. They address meetings and hold out all sorts of promises. Where a large section of the people are concerned, who only get an amenity which they ought in any case to get and which they get probably a little more easily because it happens to be election time, it cannot be said that the person in authority making that promise and holding out that he would carry out many remedial measures to benefit the people was resorting to bribery or bargaining for votes. It may not amount to setting up a very high standard and it may be very desirable that whatever is done for the people should be done by persons in authority throughout the period of their office. But they naturally are more active at election time than other times. That cannot be said to amount to corruption.

We then come to the question of gun licences. It has been pointed out that during the months of January, February and March, 1971, Mr. Sayal had issued 3,304 gun licences and Mr. Garg 485 gun licences, the usual number in an ordinary year being about 300. When every explanation offered on behalf of the official is taken into consideration the fact remains that an unusually large number of gun licences had been issued during that period. We are satisfied that to some extent at least this amounts to improper use of power. We do not say that this is an abuse or misuse. In fact there is evidence that the proper procedure has been followed in these cases. In one case, for instance, a man who had applied for a gun licence long time back approached the Chief Minister when he had come to the village and he at once told the District Magistrate and the man got his licence. We can see nothing improper in that instance. But the gun licences themselves are issued by the officials and not by the Chief Minister. It also appears that a large number of relatives of the Chief Minister as well as his Mukhtiar-e-Aam, his maternal uncle, and even the returned candidate had taken interest in the issue of gun licences. It was sought to be proved that the Chief Minister had addressed a number of meetings promising to issue gun licences if they would vote for his brother. But there was no allegation in the election petition relating to the meetings he addressed or his having held out the promise in those meetings that he would issue gun licences if the people voted for his brother. The 1st respondent himself not having had notice of the specific allegation of meetings at which such promises were held out we have left out of consideration the evidence regarding the meetings and the promises held out by the Chief Minister in those meetings as inadmissible.

Assuming that it was the returned candidate or his agent that had held out an inducement to get gun licences issued for people who vote for the returned candidate, does it amount to bribery under s. 123(1) of the Representation of the People Act ? Bribery is defined thus :

"123(1) 'Bribery', that is to say,—

(A) any gift, offer or promise by a candidate or his agent or by any other person with the consent of a candidate or his election agent of any gratification to any person whomsoever, with the object directly or indirectly of inducing—

(a) .....

(b) an elector to vote or refrain from voting at an election, or as a reward to—

(i) .....

(ii) an elector for having voted or refrained from voting ;

(B) the receipt of, or agreement to receive, any gratification, whether as a motive or a reward—

(a) .....

(b) by any person whomsoever for himself or any other person for voting or refraining from voting or inducing or attempting to induce any elector to vote or refrain from voting, or any candidate to withdraw or not to withdraw his candidate.

Explanation.—For the purposes of this clause the term 'gratification' is not restricted to pecuniary gratifications or gratifications estimable in money and it includes all forms of entertainment and all forms of employment for reward but it does not include the payment of any expenses bonafide incurred at, or for the purpose of any election and duly entered in the account of election expenses referred to in section 78."

In order to understand the exact implication of the word 'gratification' it may be useful to refer to another statute which has been in force for over a century, that is, the Indian penal Code as most legislations tend to follow established precedents. In section 161 of the Code, which deals with bribery, one of the explanation is as follows :

"'Gratification.' The word "gratification" is not restricted to pecuniary gratification, or to gratification estimate in money."

Illustration (a) to the section is as follows:

"(a) A, a munsif, obtains from Z, a banker, a situation in Z's bank, for A's brother, as a reward to A for deciding a cause in favour of Z. A has committed the offence defined in this section".

We may also quote s. 171-B of the Code and s. 171-E which find a place in the Chapter of Offences Relating to Elections, which was inserted in the Code in the year 1920.

"171-B(1) whoever—

(i) gives a gratification to any person with the object of inducing him or any other person to exercise any electoral right or of rewarding any person for having exercised any such right; or

(ii) accepts either for himself or for any other person any gratification as a reward to exercising any such right or for inducing or attempting to induce any other person to exercise any such right,

commits the offence of bribery:

Provided that a declaration of public policy or a promise of public action shall not be an offence under this section.

(2) A person who offers, or agrees to give or offers, or attempts to procure, a gratification shall be deemed to give a gratification.

(3) A person who obtains or agrees to accept or attempts to obtain a gratification shal be deemed to accept a gratification, and a person who accepts a gratification as a motive for doing what he does not intend to do, or as a reward for doing what he has not done, shall be deemed to have accepted the gratification as a reward."

"171-E. Whoever commits the offence of bribery shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to one year, or with fine, or with both :

Provided that bribery by treating shall be punished with fine only.

Explanation.—" 'Treating' means that form of bribery where the gratification consists in food, drink, entertainment, or provision".

It would be noticed that the Explanation to Section 123 (1) of the Representation of the People Act and Explanation to section 161 of the Indian Penal Code relating to gratification are similar. In addition, the Representation of the People Act refers to all forms of entertainment and all forms of employment for reward. The employment for reward is covered by illustration (a) to s. 161 of the Indian Penal Code. The words "all forms of entertainment" in the Explanation to section 123(1) of the Representation of the People Act apparently refer to offence of treating found in s. 171-E of the Indian Penal Code. When Parliament enacted the provision regarding bribery in the Representation of the People Act it should have had before it the comparable provisions in the Penal Code. It is to be noticed that the giving of any gratification with the object of inducing the receiver of any other person to vote is an offence while acceptance of gratification by a person either for himself or for any other person or for inducing any other person to vote is an offence. In other words giving is an offence if paid to the voter or such giving induces another persons to vote. It is not giving a gratification in order that he may induce another person to vote that is an offence whereas receipt of a gratification in order to induce another person to vote is an offence. The reason for the distinction between the provision in s. 123(1) (A) and 123(1)(B) seems to be this : In the former case a person standing for election has necessarily to have a number of people to work for him and he may have to bear their expenses. That by itself should not be deemed to be bribery. In the latter case when a person takes money offering to induce other people, of course, induce by wrong means, to vote for the person who pays him the money he is realy poking his nose into something which is no business of his and that practice should be discouraged. See Kalya Singh's case(1) and our judgment in Harisingh Pratapsingh Chawda v. Popatlal Mulshanker Joshi & Ors.(2) So far as we are aware it has never been held that the issue of a gun licence amounts to bribery under s. 171-B. We are of opinion that the word 'gratification' should be deemed to refer only to cases where a gift is made of something which gives a material advantage to the recipient. There is hardly any need to say that giving whose value is estimable in money is bribery. A gun licence gives no material advantage to its recipient. It might gratify his sense of importance if he has a gun licence in a village where nobody else has a gun licence. So might the conferment of an honour like Padma Bhushan. A praise from a high quarter might gratify the sense of vanity of a person. But the world 'gratification' as used in s. 123(1) does not refer to such gratifications any more than in s. 171-B of the Indian Penal Code. Taking the case of licences : Possibly the grant of a licence which enables a man to do some business and thus make money may confer a material advantage to him. We are not here speaking of licences which are insisted upon merely for regulatory purposes like municipal licences. But a licence given to a person to deal in fertilizers might confer a financial advantage to that person; so might an import licence or an export licence. Such licences differ from licences for regulatory purposes. Arms licence is licence for regulatory purposes. Its possession gives no material advantage to its possessor. A licence in a prohibition area to deal in liquor might confer a material advantage to the licensee. But a licence enabling a person to imbibe liquor in such area gives the licensee no material advantage. Such a licence is only regulatory. We must therefore distinguish between various kinds of licences and hold that where a licence gives a material advantage to the licensee the grant of such licences amounts to a gratification. In that sense the grant of gun licences to voters is the Fazilka Constituency would not amount to bribery. We have discussed this question on the basis that the authority to grant a licence is the returned candidate or his brother the Chief Minister.

We have already pointed out that there is no evidence regarding bargaining for votes by promise of gun licences. A bargain for the purpose of this section does not mean that the candidate or his agent makes an offer and the voter accepts it in the sense that he promises to vote. It is enough if the candidate or his agent makes the gift or promise on that condition. If a candidate or his agent pays money to a voter saying that he wants him to vote it is a bargain for the purposes of this section. It is not necessary that the voter should say that he would vote and thereafter the candidate or his agent should pay the money. Even in such a case the voter after receiving the money might or might not vote.

The law regarding bribery in elections in our country has been discussed in various decisions of this Court. In Magan-lal Bagdi v. Hari Vishnu Kamath (15 ELR 205) the candidate offered to construct a well in a village if the voters voted for him and not for the rival candidate and money was actually deposited for this purpose and was to await the result of the election. It was held that there was a clear bargain for votes. In Khader Sheriff. v. Munnuswami Gounder & Ors. (AIR 1955 SC 775) it was observed by this Court that it may be meritorious to make a donation for a charitable purpose but on the eve of an election such a gift may be open to construction that it was made with the intention of buying votes. In Ghasi Ram v. Dal Singh (1963 (3) SCR 102) it was held that the gift must be proved to have a direct or indirect connection with votes and this must admit of no other reasonable excluse. In Radha Krishna Shukla v. Tara Chand Maheshwar (12ELR 376) general promises by Ministers to redress certain public grievances or to erect certain public amenities like hospitals, if elected, were held not to amount to corrupt practice. They were treated as promises of general public action. In Amirchand v. Surendra Lal Jha (10 ELR 57) it was laid down that if a Minister redresses the grievances of a class of the public or people of a locality or renders them any help,

(1) C.A. No. 16 of 1973 decided on 28-2-1975.

(2) C.A. No. 90 of 1973 decided on 19-9-1975.

on the eve of an election, it was not corrupt practice unless he had obtained promises from the voters in return, as a condition for their help. The promise to grant gun licences would really amount to a redressal of the grievances of a class of the public or rendering them any help. There is no evidence here of obtaining a promise from the voters in return. The observations made in Ghasi Ram's case (supra) regarding the action taken by a Minister which helps a calss of the public may be noticed in this connection :

> "The postition of a Minister is difficult. It is obvious that he cannot cease to function when his election is due. He must of necessity attend to the grievances, otherwise he must fail. He must improve the image of his administration before the public. If everyone of his official acts done bona-fide is to be construed against him and an ulterior motive is spelled out of them, the administration must necessarily come to a stand-still. The State of Haryana came into existence on November 1, 1966. When an election in the near future, the political party had to do acts of a public nature. The grant of discretionary grants were part of the general scheme to better community development projects and to remove the immediate grievances of the public. The money was required to be spent in about 3 months' time. The action of the Minister had often the concurrence and recommendation of his subordinate staff. It is for this reason that the orders about the improvement of the supply of waters were not pressed. They were incapable of being construed against the first respondent. Therefore, emphasis was placed upon the distribution of money. The money was not distributed among the voters directly but was given to Panchayats and the public at large. It was to be used for the good of those for and those against the candidate. No doubt they had the effect of pushing forward his claims but that was inevitable even if no money was spent, but good administration changed the people's condition. We cannot therefore, hold that there was any corrupt practice. If there was good evidence that the Minister bargained directly or indirectly for votes the result might have been different but there was no such evidence."

The issue for decision in Om Prabha Jain v. Abnash Chand & Anr. (1968) (3) SCR 111) was similar to the case here in respect of the grants for dharamshalas for Harijans. It was held that the action of the Minister could not be construed against her and that it was done in the ordinary course of her duties as Minister and there was no evidence that it was, directly or indirectly, part of a bargain with the voters. In Bhanu Kumar v. Mohan Lal (1971(3) SCR 522) it was alleged that the Chief Minister by ordering the covering of a nallah, the construction of a road, the installation of water taps and the grant of pattas to the inhabitants of a colony for construction of houses had made a bargain with the people for votes and thus committed corrupt practice as defined in s. 123(1) of the Representation of the People Act. This Court pointed out that ordinarily amelioration of grievances of the public in innocuous and cannot be construed against a candidate who is a Minister but that if there is evidence to indicate that any candidate at the election abused his power and position as a Minister in the Government by utilising public revenues for conferring advantage or benefit on a particular group of people for the purpose of obtaining their votes, different considerations will arise and it may be held to be a corrupt practice within the meaning of s. 123(1). In that case it was held that in all the instances relied upon by the appellant the evidence showed that there were long standing public grievances and the Government had from time to time made suggestions and recommendations for redress of the grievances and amelioration of the condition of the people and that it could not be said that on the eve of election there was any sudden spontaneous outburst of public activity in the shape of diverting money to win electors to the side of the Chief Minister by throwing baits or giving them any particular and specially favoured treatment. These observations apply to the case of grants for Harijan dharamshalas.

We are therefore satisfied that in the case of both the allegations of corrupt practice there was no gratification offered, that there was no bargaining for votes in the sense we have explained earlier and these issues must also be found against the appellant.

The appeal is, therefore, dismissed with costs.

Sd/- (A. Alagiriswami) J.
Sd/- (P. K. GOSWAMI) J.
Sd/- (N. L. Untwalia) J.

New Delhi,
September 19, 1975.

[No. 82/PB/1/71]

V. NAGASUBRAMANIAN, Secy.

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधि विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 1975

का० आ० 4932.—राष्ट्रपति, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 81) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :-

1. (1) इस आदेश का नाम गौहाटी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (वेतन और भत्तों का आबंटन) आदेश, 1975 है ।

(2) यह 21 जनवरी को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

2. इस आदेश में, "गौहाटी उच्च न्यायालय", से गौहाटी उच्च न्यायालय (असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा) अभिप्रेत है ।

3. गौहाटी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतनों और भत्तों की बाबत, किसी वर्ष या उसके किसी भाग में खर्च को असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा और संघ के मध्य, निम्नलिखित आधार पर आबंटित किया जाएगा, अर्थात्

(क) सभी न्यायाधीशों के वेतनों और भत्तों के योग को अपवर्त्य "एक्स" द्वारा गुणा करके जो खर्चा आता है उसे, उस विशेष वर्ष या उसके भाग में, प्रत्येक राज्य या अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के संघ राज्य क्षेत्रों से संस्थित मामलों के अनुसार आनुपातिक आधार पर बांटा जाएगा ।

(ख) न्यायाधीशों के कुल वेतन और भत्तों को परिवर्ती अपवर्त्य "वाई" से गुणा करके, वेतन और भत्तों पर खर्चे का जो अतिशेष आता है उसे, जिस जिस राज्य में न्यायपीठ आस्थित है उसको अतिरिक्त रूप में विकलित किया जाएगा ;

(ग) अपवर्त्य 'एक्स' = $\frac{\text{टी}1 + \text{टी}2 + \text{टी}3 + \text{और उसी प्रकार के}}{\text{टी}1}$

टी = एक वर्ष या उसके भाग में, गौहाटी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के कार्य दिवसों की कुल संख्या ;

टी 1, टी 2, टी 3 और उसी प्रकार के वे दिन हैं जो न्यायाधीशों द्वारा न्यायपीठों का कार्य देखने के लिए विभिन्न न्यायपीठों की ओर से, यात्रा में बिताए गए हैं ।

(घ) अपवर्त्य 'वाई' = $\frac{\text{टी 1}}{\text{टी}}$ या $\frac{\text{टी 2}}{\text{टी}}$ या $\frac{\text{टी 3}}{\text{टी}}$ और उसी प्रकार के और जिस राज्य में न्यायपीठ आस्थित है उसके साथ साथ यह परिवर्तित होगा। टी 1, टी 2, टी 3 और टी का वही अर्थ है जो उपयुक्त (ग) में है।

[संख्या 4/2/72 न्याय]

पी० पी० नय्यर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(Department of Justice)

ORDER

New Delhi, the 27th October, 1975

S.O. 4932.—In exercise of the powers conferred by section 33 of the North-Eastern Areas (Re-organisation) Act 1971 (81 of 1971), the President hereby makes the following Order, namely:—

1. (1) This Order may be called the Judges of the Gauhati High Court (Allocation of Salaries and Allowances) Order, 1975.

(2) It shall be deemed to have come into force on the 21st day of January, 1972.

2. In this Order, "Gauhati High Court" means the Gauhati High Court (the High Court of Assam, Nagaland, Meghalaya, Manipur and Tripura).

3. The expenditure in respect of the salaries and allowances of the Judges of the Gauhati High Court in any year or part thereof shall be allocated amongst the States of Assam, Manipur, Meghalaya, Nagaland and Tripura and the Union on the following basis, namely:—

(a) The expenditure as arrived at by multiplying the total of salaries and allowances of all the judges with the multiple 'X' will be shared on **pro rata** basis according to the cases instituted from each of the States and the Union Territories of Arunachal Pradesh and Mizoram in the particular, year or part thereof.

(b) The balance of the expenditure on salaries and allowances of the Judges shall be additionally debited to the respective States in which the Benches are located, as arrived at by multiplying the total of salaries and allowance by variable multiple 'Y';

(c) Multiple 'X'— $\frac{t1+t2+t3+\text{and so on}}{T}$

T = total number of Judge's working days in the Gauhati High Court in a year or part thereof;

t1, t2, t3, and so on are days spent in journey to and from the seat of the different Benches by the Judges to attend to the work of the Benches.

(d) Multiple 'Y' = $\frac{t1}{T}$ or $\frac{t2}{T}$ or $\frac{t3}{T}$ and so on

and will vary with the State in which the Bench is located. t1, t2, t3 and T have the same meaning as in (c) above.

[No. 4/2/72-Jus]

P. P. NAYYAR, Jt. Secy.

(कम्पनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 28 अक्तूबर, 1975

का० आ० 4933.—एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 26 की उपधारा (3) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा मैं० सायाद्री डाइस्टफस एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड के कथित अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण (पंजीकरण प्रमाण-पत्र संख्या 237/70 दिनांक 24-10-70) के निरस्तीकरण को अधिसूचित करती है।

[फा० संख्या 2/9/75-एम 2]

एस० बलरामण, अवर सचिव

(Department of Company Affairs)

New Delhi, the 28th October, 1975

S.O. 4933.—In pursuance of sub-section (3) of section 26 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969) the Central Government hereby notifies the cancellation of registration of M/s. Sahyadri Dyestuffs and Chemicals Limited under the said Act (Certificate of Registration No. 237/70 dated the 24th October, 1970).

[F.No. 2/9/75-M.II]

S. BALARAMAN, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 1975

आयकर

का० आ० 4934.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित संस्था को विहित प्राधिकारी भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (iii) के प्रयोजनों के लिए अनुमोदित किया गया है। संस्था इस छूट के अधीन प्राप्त आय का, उसके संवितरण के ब्यौरों सहित, एक वार्षिक विवरण भेजेगी।

संस्था

इण्डियन सोसायटी आफ इण्डस्ट्रियल एण्ड फिस्कल एकोनामिक्स मद्रास।
यह अधिसूचना 1-4-75 से प्रभावी होगी।

[सं० 1094 (फा० सं० 203/66/75 आईटीए II)]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue & Insurance)

New Delhi, the 25th September, 1976

INCOME TAX

S.O. 4934.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Indian Council of Social Science Research, the prescribed authority for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961. The society would send an annual statement of income received under this exemption together with the details of its disbursal.

INSTITUTION

Indian Society of Industrial & Fiscal Economics, Madras.
This notification will be effective from 1-4-75.

[No. 1094 (F. No. 203/66/75-ITA. II)]

का० आ० 4935.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित संस्था को विहित प्राधिकरण, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उप-धारा (1) के खण्ड (iii) के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमोदित किया गया है, अर्थात् :—

(1) संस्था इस छूट के अधीन प्राप्त निधियों का पृथक लेखा रखेगी, और

(2) संस्था प्राप्त निधियों और उनके उपयोग की राशि के बारे में भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ।

संस्था

प्रबंध विकास संस्थान, उत्तर प्रदेश लखनऊ

यह अधिसूचना 1-4-75 से 31-3-1978 तक प्रभावी रहेगी ।

[सं० 1095 (फा० सं० 203/42/75 आई टी ए II)]

S.O. 4935.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Indian Council of Social Science Research, the prescribed authority for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961, subject to the following conditions:—

(1) The institute maintains separate accounts for the funds received under this exemption, and

(2) The institute submits an annual report to the Indian Council of Social Science Research regarding the funds received & manner in which they were utilised.

INSTITUTION

The Institute of Management Development, U.P., Lucknow.

The notification will be effective from 1-4-75 to 31-3-78.

[No. 1095 (F. No. 203/42/75-ITA. II)]

का० आ० 4936.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित संस्था को विहित प्राधिकारी, सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली, द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के प्रयोजनों के लिए अनुमोदित किया गया है ।

संस्था

दी इंस्टीट्यूशन आफ सर्वेयर्स, नई दिल्ली ।

यह अधिसूचना 1-4-1975 से 31-3-1978 तक प्रभावी रहेगी ।

[सं 1096 (फा० सं० 203/73/75-आई टी ए II)]

S.O. 4936.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by the Secretary, Department of Science & Technology, New Delhi, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961.

INSTITUTION

The Institution of Surveyors, New Delhi.

The notification will be effective from 1-4-75 to 31-3-1978.

[1096 (F. No. 203/73/75-ITA. II)]

का० आ० 4937.—अधिसूचना सं० 853 (फा० सं० 203/6/75-आई टी० ए II) तारीख, 7 मार्च, 75 के अनुक्रम में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा नीचे वर्णित संस्था को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उप-धारा (1) के खण्ड (ii) के प्रयोजनों के लिए, 1 अप्रैल, 1976 से 31 मार्च, 1977 तक एक वर्ष की और अवधि के लिए अनुमोदित किया गया है ।

संस्था

कर्नाटक एग्रीकल्चर फाउण्डेशन, हुबली, जिला धारवाड़

[सं० 1097(फा०सं० 203/6/75-आईटीए-II)]

S.O. 4937.—In continuation of notification No. 853 (F. No. 203/6/75-ITA. II) dated 7th March, 75 it is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Indian Council of Agricultural Research, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 for a further period of one year with effect from 1st April, 1976 to 31st March, 1977.

INSTITUTION

The Karnataka Agriculture Foundation, Hubli, Distt. Dharwar.

[No. 1097 (F. No. 203/6/75-ITA. II)]

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 1975

आयकर

का० आ० 4938.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संस्था को "विहित प्राधिकारी" भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के प्रयोजनों के लिये अनुमोदित किया गया है ।

संस्था

गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद ।

यह अधिसूचना 1-4-75 से 31-3-77 तक प्रभावी रहेगी ।

[सं० 1104(फा० सं० 203/57/75—आई टी ए II)]

टी० पी० झुनझुनवाला, उप-सचिव

New Delhi, the 29th September, 1975

S.O. 4938.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Indian Council of Agricultural Research, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961.

INSTITUTION

Gujarat Vidyapith, Ahmedabad.

This notification will be effective from 1-4-75 to 31-3-1977.

[No. 1104 (F. No. 203/57/75-ITA. II)]

T. P. JHUNJHUNWALA, Dy Secy.

आयकर आयुक्त, कार्यालय विदर्भ एंव मराहवाड़ा

नागपुर, 13 अक्तूबर, 1975

का० आ० 4939.—चूंकि केन्द्रीय सरकार की राय में यह लोक हित में आवश्यक और जरूरी है कि उन व्यतिक्रमी करदाताओं के नाम और पते प्रकाशित किए जाए जिनका उल्लेख इसके आगे व्यतिक्रमी करदाताओं के रूप में किया गया है और जिन्होंने वित्तीय वर्ष 1974-75 के 31 मार्च 1975 तक 9 मास से अधिक समय से 25,000 रु० या उससे अधिक आयकर जमा नहीं किया है ।

और चूंकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 287 में प्रदत्त शक्तियों तथा ऐसी सभी अन्य शक्तियों से, जो इस बारे में सरकार को समर्थ करती है, केन्द्रीय सरकार ने अपने तारीख 9-6-1969 के आदेश सं० 1/1/69 आई टी (बी) के द्वारा सभी आयकर आयुक्तों को इस बात का प्राधिकार और निर्देश दिया है कि वे ऐसे व्यतिक्रमी कर दाताओं के नाम और पते प्रकाशित करें।

अतः मैं, आयकर आयुक्त विदर्भ एवम मराठवाड़ा, नागपुर एतद्‌द्वारा अब विदर्भ एवम् मराठवाड़ा प्रभार के 31 मार्च, 1975 तक के व्यतिक्रमी करदाताओं के नाम तथा पते प्रकाशित कर रहा हूं।

(i) भाग 'क' के लिए है: कर रकम जो 9 मास से लेकर 1 वर्ष 3 मास तक की अवधि से जमा नहीं कराई गई है।

(ii) भाग 'ख' के लिए है: कर रकम जो 1 वर्ष 3 मास से लेकर 2 वर्ष 3 मास तक की अवधि से जमा नहीं कराई गई है।

(i) भाग 'ग' के लिए है: कर रकम जो 2 वर्ष, 3 मास से अधिक समय से जमा नहीं कराई गई है।

(ii) सारी रकम जमा न कराने के लिए।

1. श्री ए० एस० दिक्षित, वर्धा (iii) 1612418 और (iv) 1612418
2. श्री आदम अली मार्फत मैसर्स के० एस० एम हसनजी एण्ड सन्स, नागपुर (i) 52000, (iii) 59000 और (iv) 111000.
3. मसर्स अभिरी शाप, नागपुर (iii) 149191 और (iv) 149191
4. श्री ए० ए० हाजी० अमरावती (व्य) (iii) 30273 और (iv) 30273
5. श्री भिवराज तेजमेल संचेती, मलकापुर (i) 37940 और (iv) 37940
6. मैसर्स बलराम तोलुराम (हि० अ०प०) तुमसर (i) 1735 (iii) 1787606 और (iv) 1789341.
7. श्री बनवारी लाल लोईया (हि० अ०प०) कामठी, (ii) 27454, (iii) 1024307 और (iv) 1051761
8. मैसर्स भारत माइनिंग एण्ड ट्रैडिंग (प्र०) लि० (कं०) विशाखापटनम (iii) 29620 और (iv) 29620
9. मैसर्स भागमल प्रल्हादराय (पं० फ०), अकोला (iii) 412848 और (iv) 412848
10. श्री भगीरथ प्रसाद कालुराम, परभणी (iii) 75150 और (iv) 75150
11. श्री चन्द्रकान्त मोर, विधिक उत्तराधिकारी, श्री नरसिंगदास मोर तुमसर (i) 6000, (ii) 17000, (iii) 313000, और (iv) 3153000
12. श्री चन्द्रकान्त मोर, (हि०अ०प०) तुमसर (i) 1230000, (ii) 1524,000 और (iv) 1647000
13. मैसर्स सितादल ट्रेडिंग कं० (पं० फं०), वर्दवान पश्चिम बंगाल (iii) 86931 और (iv) 86931
14. मैसर्स डिलर्स एण्ड कं० प्रा० लि० जयपुर (i) 57284. (iii) 2053571 और (iv) 2110855
15. श्री दुर्गाप्रसाद सराफ, तुमसर, विधिक उत्तराधिकारी, स्व० श्रीमती सुगनीदेवी सराफ तुमसर (i) 218285 (iii) 804659 और (iv) 1022944
16. स्वापुटन वादनी गणशेरजंग बहादुर राणा (व्य) द्वारा एजेंण्ट मैसर्स आर० बी० श्रीराम एण्ड कं० प्रा०लि०, विशाखापटनम (iii) 56761 और (iv) 56761
17. श्री दुर्गाप्रसाद सराफ तुमसर (व्य) (iii) 574618 और (iv) 574618
18. श्री दुर्गाप्रसाद सराफ विधिक उत्तराधिकारी, स्व० श्रीराम दालुराम, तुमसर (iii) 575520 और (iv) 575520.
19. मैसर्स दुर्गाप्रसाद श्रीराम (हि०अ०प०), तुमसर (iii) 1020789 और (iv) 1020789.
20. श्री फकरुद्दीन मो०, अली नागपुर (iii) 318689 और (iv) 318689
21. श्री धासिलाल सुवालाल जयपुरिया, (हि०अ०प०) तुमसर, (iii) 108227 और (iv) 108227
22. मैसर्स गोवर्धनदास गोपिकिसन (पं० फा०) गोंदिया (iii) 470822 और (iv) 470892
23. श्री गुलाबदास रामबिलासदास (व्य) नागपुर (iii) 790655 और (iv) 790655
24. मैसर्स गुढ़घाट माइन्स (पं० फ०) तुमसर, (iii) 1614392 और (iv) 1614392
25. श्री जयनारायण नन्दकिशोर (व्य) द्वारा, एजेंण्ट मैसर्स आर० बी० श्रीराम एण्ड कं० प्रा० लि० विशाखापटनम (iii) 45133 और (iv) 45133.
26. मैसर्स जयपुरिया ब्रदर्स (पं० फ०) तुमसर (iii) 1624379 और (iv) 1624379
27. मैसर्स जानकी जनरल स्टोर्स, इंसापुरी, नागपुर (iii) 35967 और (iv) 35967
28. मैसर्स के० एस० आर० एन० हसनजी एण्ड सन्स, नागपुर (i) 1000 (ii) 5000, (iii) 46000 और (iv) 71000.
29. डा० कजुमल जेठानंद, नेताजी डिस्पेंसरी, महाल, नागपुर (ii) 47316 और (iv) 47316
30. श्रीमती कृष्णादेवी लोईया, कामठी (iii) 144696 और (iv) 144696
31. श्री बी० जी० कोल्हटकर, नागपुर (iii) 31673 और (iv) 31673
32. मैसर्स लक्ष्मी लाईम वर्क्स, यवतमाल (iii) 117168 और (iv) 117168
33. श्रीमति लक्ष्मीबाई गायकवाड़, (व्य०) नागपुर (iii) 29432 और (iv) 29432
34. श्री मोहसिनअली फैजलहुसैन (व्य) मार्फत मसर्स जवाहर ट्रेडर्स एण्ड कं०, भोपाल (iii) 37513 और (iv) 37513
35. मैसर्स के० मुसा मोहम्मद (पं० फ०), गोंदिया (iii) 80622 और (iv) 80622
36. श्री डी० डब्लयू मंवपे, नागपुर (iii) 63172 और (iv) 63172
37. श्री एन० पी० लाहोटी, (हि० अ० प०) लातूर (i) 49181, (iii) 51867 और (iv) 107948
36. श्रीमति निर्मलाबाई सोलव (व्य), नागपुर (iii) 97796 और 97796
39. मैसर्स निझामाबाद बिडी मैनुफेक्चर्स कं, कामटी (i) 79000, (ii) 47870, (iii) 308481 और (iv) 435351

40. नागपुर ऑरेन्ज ग्रोवर्स असोसिएशन, नागपुर (iii) 130615 और (iv) 130615
41. मैसर्स नागपुर ग्लास वर्क्स, नागपुर (iii) 77824 और (iv) 77824
42. श्री प्रल्हाद रामगोपाल तिवारी, (व्य०) अकोला (iii) 159911 और (iv) 159911
43. मैसर्स रामकृष्णा रामनाथ (हि० अ० प०), कामठी (i) 10000, (ii) 85960, (iii) 1546894 और (iv) 1642854
44. श्री रामविधान भिवराज संचेती, मलकापुर (i) 26483 और (iv) 26483
45. श्री रामेश्वरदास रामदास (व्य०) जयपुर (i) 28807, (iii) 629210 और (iv) 658017
46. मैसर्स आर० आर० अग्रवाल प्रा० लि० मार्फत शंकर बिड़ी फैक्टरी नागपुर (i) 34758, (ii) 262267, (iii) 768355 और (iv) 1065380
47. श्री रामनारायण मोर (हि० अ० प०) तुमसर (i) 170000, (ii) 3000, (iii) 2685000 और (iv) 2858000
48. मैसर्स आर० आर० लोईया एण्ड सन्स (अप० फ०) (i) 273662, (iii) 944338 और (iv) 1218000
49. मैसर्स रामकृष्णा रामनाथ बिड़ी प्रा० लि०, मार्फत शंकर बिड़ी फैक्टरी, नागपुर (i) 354836, (ii) 153421, (iii) 489390 और (iv) 997697
50. मैसर्स रामकृष्णा रामनाथ सन्स, नागपुर (i) 34050, (ii) 40249, (iii) 611118 और (iv) 685417
51. श्री राधाकिसन लोईया (हि० अ० प०), कामठी (ii) 15590 (iii) 1663412 और (iv) 1679002
52. श्री जी० डी० रानाडे, नागपुर (ii) 18807 (iii) 91726 और (iv) 110533
53. श्री रामाकान्त लोईया (हि० अ० प०) कामठी (ii) 52409, (iii) 960207 और (iv) 1012616
54. मैसर्स रामकृष्णा रामनाथ (पं० फ०), कामठी (ii) 132170, (iii) 2371634 और (iv) 2503804
55. श्री रमेशचन्द्र लोईया मार्फत राज भवन, कामठी (ii) 12715, (iii) 88620 और (iv) 101335
56. श्री आर० एन० लाधा (व्य०) अमरावती (ii) 44363 और (iv) 44363
57. मैसर्स रामचन्द्र रामरतन (अपं० फ०) अमरावती (ii) 52860 और (iv) 52860
58. श्री राजीव ईश्वरलाल मोर (व्य०) तुमसर (iii) 56255 और (iv) 56255
59. आर० एस० बी० जयपुरिया (व्य०) तुमसर (iii) 85367 और (iv) 85367
60. मैसर्स रामनिवास मुरलीधर एण्ड बलराम तोलुराम (पं० फ०) तुमसर (iii) 154472 और (iv) 154472
61. श्री रामकुमार रामगोपाल बोहरा (अनिवासी) द्वारा एजेन्ट मैसर्स आर० बी० श्रीराम एण्ड कं० लि० विशाखापटनम (iii) 242057 और (iv) 242057
62. मैसर्स रामचन्द्र ट्रान्सपोर्ट कं० प्रा० लि० अमरावती (iii) 372015 और (iv) 372015
63. मैसर्स आर० बी० श्रीराम दुर्गाप्रसाद एण्ड फतेचंद नरसिंगदास (एक्सपोर्ट) फर्म (पं० फ०) तुमसर (iii) 407189 और (iv) 407189
64. मैसर्स आर० एस० गोपीकिसन अग्रवाल (शिपर्स) प्रा० लि० तुमसर (iii) 1343079 और (iv) 1343079
65. श्री रामनारायण मोर, विधिक उत्तराधिकारी, स्व० श्री फतेचंद नरसिंगदास मोर, तुमसर (iii) 1978000 और (iv) 1978000
66. मैसर्स रामविलास गुलाबदास (हि० अ० प०) नागपुर (iii) 3545814 और (iv) 3545814
67. मैसर्स आर० बी० श्रीराम दुर्गाप्रसाद, प्रा० लि० तुमसर (iii) 23857481 और (iv) 23857481
68. मैसर्स श्रीराम दुर्गाप्रसाद (हि० अ० प०) तुमसर (i) 878636 और (iv) 878636
69. श्री उम्रबीर हुसेन, विधिक उत्तराधिकारी, स्व० श्री हाशिमभाई मार्फत मैसर्स के० एम० एस० हुसनजी एण्ड सन्स, इतवारी नागपुर (i) 32000, (iii) 55000 और (iv) 87000
70. श्री एम० के० मुखर्जी (व्य०) नागपुर (iii) 80857 और (iv) 80857
71. श्री संतोषकुमार अग्रवाल (व्य०) तुमसर (iii) 105770 और (iv) 105770
72. मैसर्स श्रीराम दुर्गाप्रसाद (हि० अ० प०) तुमसर (iii) 616773 और (iv) 616773
73. श्रीमति सुधादेवी लोईया (व्य०) कामठी (iii) 104324 और (iv) 104324
74. मैसर्स सुवर्णा ट्रान्सपोर्ट कं० प्रा० लि० बुलढाणा (ii) 96999 और (i) 96999
75. उमाशंकर दुर्गाप्रसाद (हि० अ० प०) तुमसर (iii) 777636 और (iv) 777636
76. उमाशंकर लोईया, कामठी (i) 106855 (ii) 23754 (iii) 140821 और (iv) 271430

[फ० सं० वसूली० (64)/75-76]

ह०/-

वि० रा० बापट, आयकर आयुक्त

नागपुर

तारीख 13-10-1975

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF INCOMETAX VIDHARBHA AND MARATHWADA

Nagpur, the 13th October, 1975

S.O. 4939.—Whereas the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in public interest to publish the names and addresses hereinafter specified relating to tax defaulters who were in default of payment of tax of Rs. 25000 and above for the periods exceeding 9 months as on 31st March, 1975 relating to Financial year 1974-75.

And whereas in exercise of the powers conferred by the Section 287 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and all others powers enabling it in this behalf, the Central Government by its order F. No. 1/1/69-IT(B) dated 9-6-1969 hereby authorised and directed all Commissioners of Income-tax to publish the names and addresses of such tax defaulters.

Now, therefore, I, Commissioner of Income-tax, Vidharbha and Marathwada, Nagpur, hereby publish the names and addresses of the tax defaulters in Vidharbha and Marathwada charge as on 31-3-1975.

(i) is for Part 'A'—Amount in default for periods exceeding 9 months but not exceeding 1 year and 3 months.

(ii) for Part 'B'—Amount in default for period of 1 year & 3 months and above but not exceeding 2 years & 3 months.

(iii) For Part 'C'—Amount in default for 2 years and 3 months above.

(iv) For total amount in default.

1. Shri A. S. Dixit, Wardha (iii) 1612418 and (iv) 1612418

2. Shri Adamdi, C/o M/s. K.S.M. Hassonjee & Sonts, Nagpur (i) 52000, (iii) 59000 and (iv) 111000.

3. M/s. Abidi Shop, Nagpur (iii) 149191 and (iv) 149191.

4. Shri A. A. Haji, Amravati (Indl) (iii) 30273 and (iv) 30273.

5. Shri Bhivraj Teimal Sancheti, Malkapur (i) 37940 and (iv) 37940.

6. M/s. Balaram Toluram (HUF), Tumsar (i) 1735, (iii) 1787606 and (iv) 1789341.

7. Shri Banwarilal Loiva (HUF) Kamatee, (ii) 27454 (iii) 1024307 and (iv) 1051761.

8. M/s. Bharat Minig & Trading (Pvt.) Ltd. (Coy) Vishakapatnam (iii) 29620 and (iv) 29620.

9. M/s. Bagmal Prahladrai (RF), Akola (iii) 412848 and (iv) 412848.

10. Shri Bhagirath Prasad Kaluram, Parbhani (iii) 75150 and (iv) 75150.

11. Shri Chandrakant Mor Legal heir of Late Shri Narsinghdas Mor, Tumsar (i) 6000, (ii) 17000, (iii) 3130000 and (iv) 3153000.

12. Shri Chandrakant Mor, (HUF) Tumsar (i) 123000, (ii) 1524000 and (iv) 1647000.

13. M/s. Citadel Trading Co. (RF), Burdwan, West Bengal (iii) 86931 and (iv) 86931.

14. M/s. Dealers and Co. Pvt. Ltd., Jaipur (i) 57284, (iii) 2053571 and (iv) 2110855.

15. Shri Durgaprasad Saraf, Tumsar L/H of Late Smt. Sugnidevi Saraf, Tumsar, (i) 218285, (iii) 804659 (iv) 1022944.

16. Capt. Dadli Shamsherjang Bahadur Rana (Indl) through Agent M/s. R. B. Shreeram & Co. Pvt. Ltd., Vishakapatnam (iii) 56761 and (iv) 56751.

17. Shri Durgaprasad Saraf. Tumsar (Indl.) (iii) 574618 and (iv) 574618.

18. Shri Durgaprasad Saraf L/H of Late Shreeram Daularam, Tumsar (iii) 575520 and (iv) 575520.

19. M/s. Durgaprasad Shreeram (HUF), Tumsar (iii) 1020789 and (iv) 1020789.

20. Shri Fakruddin Mohd. Ali, Nagpur (iii) 318689 and (iv) 318689.

21. Shri Gasilal Suwalal Jaipuria, (HUF) Tumsar, (iii) 108227 and (iv) 108227.

22. M/s. Goverdhandas Gopikisan, (RF) Gondia (iii) 470822 and (iv) 470822.

23. Shri Gulabdas Rambiladas, (Indl.) Nagpur (iii) 790655 and (iv) 790655.

24. M/s. Gudrughat Mines (R.F.) Tumsar (iii) 1614392 and (iv) 1614392.

25. Shri Jainaravan Nandkishore (Indl.), Through Agent M/s R. B. Shreeram & Co. Pvt. Ltd., Vishakhapatnam (iii) and 45133 and (iv) 45133.

26. M/s. Jaipuria Bros. (RF), Tumsar (iii) 1624379 and (iv) 1624379.

27. M/s. Janki General Stores, Hansapuri Nagpur (iii) 35967 and (iv) 35967.

28. M/s. K. S. M. Hasanjee & Sons, Nagpur (i) 10000, (ii) 5000, (iii) 56000 and (iv) 71000.

29. Dr. Kachumal Jethanand, Netaji Dispensary, Mahal, Nagpur (ii) 47316 and (iv) 47316.

30. Smt. Krishnadevi Loiya, Kamptee (iii) 144696 and (iv) 144696.

31. Shri V. G. Kolhatkar, Nagpur (iii) 31673 and (iv) 31673.

32. M/s. Laxmi Lime Works, Yeotmal (iii) 117168 and (iv) 117168.

33. Smt. Laxmibai Gaikwad, (Indl) Nagpur (iii) 29432 and (iv) 29432.

34. Shri Mohsinali Faizalhussain (Indl) C/o M/s Jawahar Traders & Co., Bhopal (iii) 37513 and (iv) 37513.

35. M/s. K. Mussa Mohd. (R.F.), Gondia (iii) 80622 and (iv) 80622.

36. Shri D.W. Mandpe, Nagpur (iii) 63172 and (iv) 63172.

37. Shri N. P. Lahoti, (HUF) Latur (i) 49181, (iii) 51867 and (iv) 107948.

38. Smt. Nirmalabai Solao (Indl), Nagpur, (iii) 97796 and (iv) 97796.

39. M/s. Nizamabad Bidi Manufactures Co., Kamptee (i) 79000, (ii) 47870, (iii) 308481 and (iv) 435351.

40. Nagpur Orange Growers Association, Nagpur (iii) 130615. and (iv) 130615.

41. M/s. Nagpur Glass Works, Nagpur (iii) 77824 and (iv) 77824.

42. Shri Prahladrai Ramgopal Tiwari, (Indl) Akola (iii) 159911 nd (iv) 159911.

43 M/s. Ramkrishna Ramnath (HUF), Kamptee (i) 10000, (ii) 85960, (iii) 1546894 and (iv) 1642854.

44. Shri Ramdas Bhivraj Sancheti, Malkapur (i) 26483 and (iv) 26483.

45. Shri Rameshwardas Ramdas (Indl.) Jaipur (i) 28807, (iii) 629210 and (iv) 658017.

46. M/s. R. R. Agarwal Pvt. Ltd., C/o Shankar Bidi Factory, Nagpur (i) 34758, (ii) 262267, (iii) 768355 and (iv) 1065380.

47. Shri Ramnarayan Mor, (HUF) Tumsar (i) 170000, (ii) 3000, (iii) 2685000 and (iv) 2858000.

48. M/s. R. R. Ioiya & Sons (URF), Kamptee (i) 273662, (iii) 944338 and (iv) 1218000.

49. M/s. Ramkrishna Ramnath Bidi Pvt. Ltd., C/o Shankar Bidi Factory, Nagpur (i) 354836, (ii) 153421, (iii) 489390 and (iv) 997697.

50. M/s. Ramkrishna Ramnath Sons, Nagpur (i) 34050, (ii) 40249, (iii) 611118 and (iv) 685417.

51. Shri Radhakishan Ioiya (HUF), Kamptee (ii) 15590, (iii) 1663412 and (iv) 1679002.

52. Shri G. V. Ranade, Nagpur (ii) 18807, (iii) 91726 and (iv) 110533.

53. Shri Ramakant Loiya, (HUF) Kamptee, (ii) 52409, (iii) 960207 and (iv) 1012616.

54. M/s. Ramkrishna Ramnath (R.F.), Kamptee (ii) 132170, (iii) 2371634 and (iv) 2503804.

55. Shri Rameshchandra Loiya C/o Raj Bhawan, Kamptee (ii) 12715, (iii) 88620 and (iv) 101335.

56. Shri R. N. Ladha (Indl.) Amravati. (ii) 44363 and (iv) 44363.

57. M/s. Ramchandra Ramratan (URF), Amravati (ii) 52860 and (iv) 52860.

58. Shri Rajiv Ishwarlal Mor (Indl.) Tumsar (iii) 56255 and (iv) 56255.

59. R.S.G.L. Jaipuria (Indl.) Tumsar, (iii) 85367 and (iv) 85367.

60. M/s. Rambilas Murlidhar and Bularam Tolurum (RF) Tumsar, (iii) 154472 and (iv), 154472.

61. Shri Ramkumar Ramgopal Bohara (Non-resident) Through Agent M/s. R. B. Shreeram and Co. Ltd., Vishakapatnam (iii) 242057 and (iv) 242057.

62. M/s. Ramchandra Transport Co. Pvt. Ltd., Amravati. (iii) 372015 and (iv) 372015.

63. M/s. R. B. Shreeram Durgaprasad and Fatehand Narsinghdas (Export) Firm (R.F.) Tumsar, (iii) 407189 and (iv) 407189.

64. M/s. R. S. Gopikisan Agarwal (Shippers) Pvt. Ltd. Tumsar. (iii) 1343079 and (iv) 1343079.

65. Shri Ramnarain Mor, Legal Heir of Late Shri Fatehchand Narsinghdas Mor, Tumsar (iii) 1978000 and (iv) 1978000.

66. M/s. Rambilas Gulabdas (HUF) Nagpur (iii) 3545814 and (iv) 3545814.

67. M/s. R. B. Shreeram Durgaprasad Pvt. Ltd. Tumsar (ii) 23857481 and (iv) 23857481.

68. M/s. Shreeram Durgaprasad (HUF) Tumsar. (i) 878636 and (iv) 878636.

69. Shri Shabir Hussain, Legal heir of Late Shri Hatimbhai, C/o M/s. K.S.M. Hassonjee and sons, Itwari, Nagpur (i) 32000; (iii) 55000 and (iv) 87000.

70. Shri S. K. Mukherjee (Indl.) Nagpur (iii) 80857 and (iv) 80857.

71. Shri Santoshkumar Agarwal (Indl.), Tumsar (iii) 105770 and (iv) 105770.

72. M/s. Shreeram Durgaprasad (HUF) Tumsar (iii) 616773 and (iv) 616773.

73. Smt. Sudhadevi Loiya (Indl.) Kamptee (iii) 104324 and (iv) 104324.

74. M/s. Suwarna Transport Co. Pvt. Ltd., Buldhana. (ii) 96999 and (iv) 96999.

75. Umashankar Durgaprasad (HUF) Tumsar. (iii) 777636 and (iv) 777636.

76. Umashankar Loiya, Kamptee, (i) 106855, (ii) 23754, (iii) 140821 and (iv) 271430.

[F. No Recy. (64)/75-76.]

Sd/-

V. R. BAPAT, Commossioner

आदेश

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 1975

का० आ० 4940.—केन्द्रीय सरकार स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 (1968 का 45) की धारा 80 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि सीमा-शुल्क कलक्टर (निवारक) मुम्बई की अधिकारिता के भीतर कार्य करने वाले किसी स्वर्ण नियंत्रण अधिकारी के द्वारा इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी विनिश्चय या आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे विनिश्चय या आदेश के विरुद्ध अपील, उक्त धारा में विनिर्दिष्ट समय के भीतर सीमा-शुल्क अपील कलक्टर मुम्बई को कर सकेगा।

[सं० 10/75 फा० सं० 132/11/74/ख० नि० II]

एम० जी० अब्रोल, अतिरिक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 5th November, 1975

S.O. 4940.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (1) of section 80 of the Gold (Control) Act, 1968 (45 of 1968), the Central Government hereby directs that a person aggrieved by any decision or order made under the said Act by a Gold Control Officer functioning within the jurisdiction of the Collector of Customs (Preventive) Bombay, may prefer an appeal against such decision or order, within the time specified in the said section 80, to the Appellate Collector of Customs, Bombay.

[No. 15/75 F. No. 132/11/74-GC. II]

M. G. ABROL, Addl. Secy.

बैंकिंग विभाग

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर, 1975

का० आ० 4941.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, एतद्द्वारा घोषणा करती है कि पुल्लुपल्लम् पोर्ट, कोचीन में, चार्टर्ड बैंक द्वारा धृत 6 सैंट भूमि की उस अचल सम्पत्ति के संबंध में, जिस पर कि नगरपालिका संख्या 8/320 ए से 320/एच तक के 9 दुकान-कमरे बने हैं, उक्त बैंक पर, उक्त अधिनियम की धारा 9 के उपबन्ध, 4 अक्तूबर, 1976 तक लागू नहीं होंगे।

[सं० 15(20)-बी० ओ०III-75]

मे० भा० उसगांवकर, अवर सचिव

(Department of Banking)

New Delhi, the 21st October, 1975

S.O. 4941.—In exercise of the powers conferred by section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of section 9 of the said Act shall not apply, till the 4th October, 1976, to the Chartered Bank, in respect of the immovable property of 6 cents of land with nine shop rooms thereon bearing Municipal Nos. VIII/320A to 320H held by it at Pullupuram, Fort Cochin.

[No. 15(20)-B.O. III/75]

M. B. USGAONKAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 29 अक्तूबर, 1975

का० आ० 4942:—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के खण्ड 8 के उपखंड (1) के साथ पठित खण्ड 3 के उपखण्ड (क) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात्, श्री सी० पी० शाह को 30 अक्तूबर, 1975 से प्रारम्भ होने वाली और 29 अक्तूबर, 1976 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए, बैंक आफ इंडिया के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करती है ।

[सं० एफ० 9/10/75-बी० ओ० I-(1)]

New Delhi, the 29th October, 1975

S.O. 4942.—In pursuance of sub-clause (a) of clause 3, read with sub-clause (1) of clause 8, of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India, hereby appoints Shri C. P. Shah as the Managing Director of Bank of India for the period commencing on 30th October, 1975 and ending with 29th October, 1976.

[No. F. 9/10/75-BO. I-1]

का० आ० 4943:—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम, 1970 के खण्ड 7 के साथ पठित खण्ड 5 के उपखण्ड (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात्, श्री सी० पी० शाह को, जिन्हें 30 अक्तूबर, 1975 से बैंक आफ इण्डिया के प्रबन्ध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, उसी तारीख से बैंक आफ इंडिया के निदेशक-बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करती है ।

[सं० एफ० 9/10/75-बी० ओ० I-(2)]

निर्मल चन्द्र सेन गुप्ता, सचिव ।

S.O. 4943.—In pursuance of sub-clause (1) of clause 5, read with clause 7 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India, hereby appoints Shri C. P. Shah, who has been appointed as Managing Director of Bank of India with effect from 30th October, 1975, to be the Chairman of the Board of Directors of Bank of India with effect from the same date.

[No. F. 9/10/75-BO. I-2]

N. C. SEN GUPTA, Secy.

नई दिल्ली, 31 अक्तूबर, 1975

भारतीय रिजर्व बैंक

का० आ० 4944:—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसरण में अक्तूबर 1975 के दिनांक 24 को समाप्त हुए सप्ताह के लिए लेखा

(इश्यू विभाग)

देयताएं	रुपये	रुपये	आस्तियां	रुपये	रुपये
बैंकिंग विभाग में रखे हुए नोट	22,49,48,000		सोने का सिक्का और बुलियन :—		
			(क) भारत में रखा हुआ	183,82,56,000	
			(ख) भारत के बाहर रखा हुआ	—	
संचलन में नोट	6269,52,74,000		विदेशी प्रतिभूतियां	121,73,97,000	
जारी किये गये कुल नोट		6292,02,22,000	जोड़		304,26,53,000
			रुपये का सिक्का		17,35,97,000
			भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां		5970,39,72,000
			देशी विनिमय बिल और दूसरे वाणिज्य पत्र		—
कुल देयताएं		6292,02,22,000	कुल आस्तियां		6292,02,22,000

दिनांक : 29 अक्तूबर, 1975 ।

आर० के० हजारी उप गवर्नर

24 अक्तूबर 1975 को भारतीय रिजर्व बैंक के बैंकिंग विभाग के कार्यकलाप का विवरण

देयताएं	रुपये	आस्तियां	रुपये
चुकता पूंजी	5,00,00,000	नोट	22,49,48,000
आरक्षित निधि	150,00,00,000	रुपये का सिक्का	2,80,000
राष्ट्रीय कृषि ऋण		छोटा सिक्का	5,19,000
(दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि	334,00,00,000	खरीदे और भुनाये गये बिल	
राष्ट्रीय कृषि ऋण		(क) देशी	88,86,87,000
(स्थिरीकरण) निधि	140,00,00,000	(ख) विदेशी	..
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण		(ग) सरकारी खजाना बिल	781,19,43,000
(दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि	390,00,00,000	विदेशों में रखा हुआ बकाया*	782,21,95,000
जमाराशियां :—		निवेश**	516,39,24,000
(क) सरकारी		ऋण और अग्रिम :—	
(i) केन्द्रीय सरकार	55,92,36,000	(i) केन्द्रीय सरकार को	..
(ii) राज्य सरकारें	7,87,04,000	(ii) राज्य सरकारों को@	113,32,00,000
(ख) बैंक		ऋण और अग्रिम :—	
(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक	538,84,11,000	(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को†	155,19,20,000
(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	17,00,37,000	(ii) राज्य सहकारी बैंकों को ††	343,16,95,000
(iii) गैर अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	1,62,68,000	(iii) दूसरों को	13,18,56,000
(iv) अन्य बैंक	64,26,000	राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से ऋण, अग्रिम और निवेश	
		(क) ऋण और अग्रिम :—	
		(i) राज्य सरकारों को	69,60,45,000
		(ii) राज्य सहकारी बैंकों को	13,13,26,000
		(iii) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों को	..
		(iv) कृषि पुनर्वित्त निगम को	87,00,00,000
(ग) अन्य	1221,27,05,000	(ख) केन्द्रीय भूमिबन्धक बैंकों के डिबेंचरों में निवेश	10,60,13,000
		राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से ऋण और अग्रिम	
देय बिल	178,32,30,000	राज्य सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम	94,55,06,000
		राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से	
अन्य देयताएं	728,17,54,000	ऋण, अग्रिम और निवेश	
		(क) विकास बैंक को ऋण और अग्रिम	333,25,56,000
		(ख) विकास बैंक द्वारा जारी किये गये बांडों/डिबेंचरों में निवेश	..
		अन्य आस्तियां	344,41,58,000
रुपये	3768,67,71,000	रुपये	3768,67,71,000

*नकदी, आवधिक जमा और अल्पकालीन प्रतिभूतियां शामिल हैं ।

**राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि और राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि में से किये गये निवेश शामिल नहीं हैं।

@राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं है, परन्तु राज्य सरकारों को दिये गये अस्थायी ओवर-ड्राफ्ट शामिल हैं ।

†भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 17(4)(ग) के अधीन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को मीयादी बिलों पर अग्रिम दिये गये 65,02,00,000 रुपये शामिल हैं ।

††राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि और राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि से प्रदत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं ।

दिनांक : 29 अक्तूबर, 1975

आर० के० हजारी, उप गवर्नर

[सं० फा० 10(i)/75-नो०ओ० I]

प० व० मीरअन्दामी, अवर सचिव

(Department of Banking)

RESERVE BANK OF INDIA

New Delhi, the 31st October, 1975

S.O. 4041.—An Account pursuant to the Reserve Bank of India Act, 1934, for the week ended the 24th day of October, 1975

ISSUE DEPARTMENT

LIABILITIES	Rs.	Rs.	ASSETS	Rs.	Rs.
Notes held in the Banking Department	22,49,48,000		Gold Coin and Bullion :— (a) Held in India	182,52,56,000	
Notes in circulation	6269,52,74,000		(b) Held outside India	..	
			Foreign Securities	121,73,97,000	
Total notes issued		6292,02,22,000	Total		304,26,53,000
			Rupee Coin		17,35,97,000
			Government of India Rupee Securities		5970,39,72,000
			Internal Bills of Exchange and other commercial paper		..
Total Liabilities		6292,02,22,000	Total Assets		6292,02,22,000

R. K. HAZARI, Dy. Governor.

Dated the 29th day of October, 1975

Statement of the Affairs of the Reserve Bank of India, Banking Department as on the 24th October, 1975

LIABILITIES	Rs.	ASSETS	Rs.
Capital Paid Up	5,00,00,000	Notes	22,49,48,000
		Rupee Coin	2,80,000
Reserve Fund	150,00,00,000	Small Coin	5,19,000
		Bills Purchased and Discounted :—	
National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund	334,00,00,000	(a) Internal	88,86,87,000
		(b) External	..
		(c) Government Treasury Bills	781,19,43,000
National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	140,00,00,000	Balances Held Abroad*	782,21,95,000
		Investments**	516,39,24,000
		Loans and Advances to :—	
		(i) Central Government	..
National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	390,00,00,000	(ii) State Governments@	113,37,00,000
		Loans and Advances to :—	
Deposits :—		(i) Scheduled Commercial Banks†	155,19,20,000
(a) Government		(ii) State Co-operative Banks††	343,16,95,000
(i) Central Government	55,92,36,000	(iii) Others	13,18,56,000
(ii) State Governments	7,87,04,000	Loans Advances and Investments from National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund :	
(b) Banks :			
(i) Scheduled Commercial Banks	538,84,11,000	(a) Loans and Advances to :—	..
(ii) Scheduled State Cooperative Banks	17,00,37,000	(i) State Government	69,60,45,000
(iii) Non-Scheduled State Co-operative Banks	1,62,68,000	(ii) State Co-operativs Banks	13,13,26,000
(iv) Other Banks	64,26,000	(iii) Central Land Mortgage Banks	..
(c) Others	1221,27,05,000	(iv) Agricultural Refinance Corporation	87,00,00,000
Bills Payable	178,32,30,000	(b) Investment in Central Land Mortgage Bank Debentures	10,60,13,000
Other Liabilities	728,17,54,000	Loans and Advances from National Agricultural Credit (Stabilisation) Fund	
		Loans and Advances to State Co-operative Banks	94,55,06,000
		Loans, Advances and Investments from National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund :	
		(a) Loans and Advances to the Development Bank	333,25,56,000
		(b) Investment in bonds/debentures issued by the Development Bank	
		Other Assets	344,41,58,000
RUPEES	3768,67,71,000	RUPEES	3768,67,71,000

*Includes Cash, Fixed Deposits and Short-term Securities.

**Excluding Investments from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund.

@Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund, but including temporary overdrafts to State Governments.

†Includes Rs. 65,02,00,000/- advanced to scheduled commercial banks against usance bills under Section 17(4)(c) of the Reserve Bank of India Act.

††Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and the National Agricultura Credit (Stabilisation) Fund.

R. K. HAZARI, Dy. Governor.
[No. F. 10(1)/75—BO. I]

Dated the 29th day of October, 1975

C.W. MIRCHANDANI, Under Secy.

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 1975

का० आ० 4945.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, एतद्द्वारा घोषणा करती है कि विजया बैंक लि०, मंगलौर द्वारा मंगलौर (साउथ कनारा) में धृत अचल सम्पत्ति (भूमि-प्लाट टी० एस० 832) के संबंध में, उक्त बैंक पर, उक्त अधिनियम की धारा 9 के उपबन्ध 5 अक्तूबर, 1976 तक लागू नहीं होंगे ।

[सं० 15(43)-बी० ओ० III/75]

मे० भा० उसगांवकर, अवर सचिव

New Delhi, the 5th November, 1975

S.O. 4945.—In exercise of the powers conferred by Section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of Section 9 of the said Act shall not apply till 5th October 1976, to the Vijaya Bank Ltd., Mangalore in respect of the immovable property (plot of land bearing T. S. No. 832) held by it at Mangalore (South Kanara).

[No. 15(43)-B.O. III/75]

M. B. USGAONKAR, Under Secy.

आयकर आयुक्त कार्यालय

पटियाला, 9 अक्तूबर, 1975

आयकर

का० आ० 4946.—आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 287 के अधीन ऐसे चूककर्ताओं की सूची, जिन्हें 31-3-1975 को 25,000 रु० अथवा उससे अधिक कर संदत्त करना था—(i) चूक की ऐसी रकम के लिए है जो नौ मास से अधिक अवधि के लिए है परन्तु एक वर्ष और तीन मास से अधिक की अवधि के लिए नहीं है (ii) चूक की ऐसी रकम के लिए है, जो एक वर्ष और तीन मास की अवधि के लिए तथा उससे अधिक अवधि के लिए है, परन्तु दो वर्ष और तीन मास से अधिक की अवधि के लिए नहीं है । (iii) चूक की ऐसी रकम के लिए है जो दो वर्ष तथा तीन मास की अवधि के लिए तथा उससे अधिक की अवधि के लिए है (iv) चूक की कुल रकम के लिए है ।

1. मैसर्स गिर्सन निटिंग वर्क्स, सबन बाजार, लुधियाना (i) 3,14,653 (ii) 3,591 (iii) 77,016 (iv) 3,95,260

2. श्री मंगत राय मार्फत यथोपरि (i) 3,74,515 (ii) 13,434 (iii) 25,129 (iv) 4,13,078

3. श्री रमेश कुमार मार्फत यथोपरि (i) 1,03,490 (ii) 2,365 (iii) 1,959 (iv) 1,09,814

4. श्री बाबू राम अग्रवाल, तलाब मन्दिर रोड, लुधियाना (i) 4,91,061 (iv) 4,91,061

5. श्री शिव कुमार मार्फत यथोपरि (i) 1,21,490 (iii) 7,611 (iv) 1,29,101

6. मैसर्स धनवन्त सिंह सेखों, द्वारा श्री बलवन्त सिंह, 671, सैक्टर 8-बी, चण्डीगढ़ (i) 73,041 (iv) 73,041

7. मैसर्स प्रीमियर बस सर्विस, पटियाला (iii) 68,126 (iv) 68,126

8. मैसर्स कलकत्ता बस सर्विस (प्रा०) लि०, पटियाला । (iii) 29,204 (iv) 29,204

9. मैसर्स पटियाला बस सर्विस (प्रा०) लि०, सरहिन्द (iii) 84,845 (iv) 84,845

10. श्री सिरी राम मार्फत जिन्दल स्टील वर्क्स, मलेरकोटला (iii) 3,11,667 (iv) 3,11,667

11. श्रीमती बचनी देवी मार्फत यथोपरि (iii) 68,425 (iv) 68,425

12. मैसर्स जिन्दल स्टील वर्क्स (पंजीकृत फर्म) मलेरकोटला (iii) 50,847 (iv) 50,847

13. श्री बली राम मार्फत यथोपरि (iii) 45,084 (iv) 45,084

14. मैसर्स जिन्दल स्टील वर्क्स, मलेरकोटला । (iii) 32,841 (iv) 32,841

15. मैसर्स शाम लाल सूद एण्ड कं०, रोपड़ (i) 31,649 (iv) 31,649

16. श्रीपृथ्वी चन्द सूद, बी माल, शिमला (iii) 70,234 (iv) 70,234

17. मैसर्स मैटरोपोल होटल, बी माल, शिमला (iii) 60,986 (iv) 60,986

18. मैसर्स कांगड़ा आयरन एण्ड स्टील सिन्डीकेट, कांगड़ा (iii) 54,129 (iv) 54,129

19. श्री सुखदेव सिंह मार्फत गुरबख्श स्टील एण्ड वायर प्रोडक्टस, कांगड़ा (iii) 26,651 (iv) 26,651

20. श्री देविन्दर कुमार बरोता, चत्तर सिंह का कानूनी वारिस, भूतपूर्व संसद सदस्य, चम्बा (iii) 43,355 (iv) 43,355

21. मैसर्स आजाद हिन्द कैमिकल्स (प्रा०) लि०, कांगड़ा (iii) 90,922 (iv) 90,922

22. श्री पूर्ण चन्द उर्फ पूर्ण सिंह, गांव राजेमाजरा, रोपड़ (i) 96,000 (iv) 96,000

[फा० सं० रैक/प्रकाशन/iii]

बी० पी० गुप्ता, आयुक्त

(Office of the Commissioner of Income-tax)

Patiala, the 9th October, 1975

INCOME-TAX

S.O. 4946.—List of defaulters for payment of tax of Rs. 25000 or more as on 31-3-1975 u/s 287 of the I.T. Act, 1961-(i) is for amount in default for periods exceeding nine months but not exceeding one year and three months, (ii) for amount in default for period of one year and three months and above but not exceeding two years and three months, (iii) for amount in default for period of two years and three months and above (iv) for total amount in default.

1. M/s. Girson Knitting Works, Saban Bazar, Ludhiana, (i) 3,14,653 (ii) 3,591 (iii) 77,016 (iv) 3,95,260.

2. Shri Mangat Rai, C/o above. (i) 3,74,515 (ii) 13,434 (iii) 25, 129 (iv) 4,13,078.

3. Shri Ramesh Kumar C/o above. (i) 1,05,490 (ii) 2,365 (iii) 25,129 (iv) 4,13,078.

4. Shri Babu Ram Aggarwal, Talab Mandir Road, Ludhiana, (i) 4,91,061, (iv) 4,91,061.

5. Shri Shiv Kumar C/o above. (i) 1,21,490 (iii) 7,611, (iv) 1,29,101.

6. M/s Dhanwant Singh Sekhon, through Shri Balwant Singh, 671, Sec. 8-B, Chandigarh (i) 73,041, (iv) 73,041.

7. M/s. Premier Bus Service, Patiala (iii) 68,126 (iv) 68,126.

8. M/s. Calcutta Bus Service (P) Ltd., Patiala (iii) 29,204, (iv) 29,204.

9. M/s. Patiala Bus Service, (P) Ltd., Sirhind. (iii) 84.845 (iv) 84,845.

10. Shri Siri Ram C/o Jindal Steel Works, Malerkotla (iii) 3,11,667 (iv) 3,11,667.

11. Smt. Bachni Devi C/o above (iii) 68,425 (iv) 68,425.

12. M/s. Jindal Steel Works (RF) Malerkotla. (iii) 50,847 (iv) 50,847.

13. Shri Wali Ram C/o above. (iii) 45,084 (iv) 45,084.

14. M/s. Jindal Steel Works, Malerkotla. (iii) 32,841 (iv) 32,841.

15. M/s. Sham Lal Sood & Co., Ropar. (i) 31,649, (iv) 31,649.

16. Shri Prithi Chand Sood, The Mall Simla (iii) 70,234 (iv) 70,234.

17. M/s. Metropole Hotel, The Mall, Simla. (iii) 60.986 (iv) 60,986.

18. M/s. Kangra Iron & Steel Syndicate Kangra. (iii) 54,129 (iv) 54,129.

19. Shri Sukhdev Singh C/o Sh. Gurbax Steel & Wire Products, Kangra (iii) 26,651 (iv) 26,651.

20. Shri Devinder Kumar Barotra, L/Heir of Shri Chattar Singh, Ex-MP, Chamba. (iii) 43,355 (iv) 43,355.

21. M/s. Azad Hind Chemicals (P) Ltd., Kangra. (iii) 90,922 (iv) 99,922.

22. Sh. Puran Chand alias Puran Singh, Vill. Rajemajra Ropar (i) 96,000 (iv) 96,000.

[F. No. REC/PUBLICATION/III]

V. P. GUPTA, Commissioner.

आयकर आयुक्त कार्यालय, पटियाला-II

पटियाला, 22 अक्तूबर, 1975

का०आ० 4947—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में यह आवश्यक तथा समीचीन है कि ऐसे करदाताओं के नाम तथा उनसे संबंधित अन्य विशिष्टियां प्रकाशित की जाएं, जिन पर वित्तीय वर्ष 1974-75 के दौरान 5000/- रु० से अन्यून का जुर्माना लगाया गया था ।

और यतः आयकर अधिनियम (1961 का 43) की धारा 287 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का तथा इस निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने अपने दिनांक 25 मार्च, 1969 के आदेश द्वारा सभी आयकर आयुक्तों को, उनके अधिकार क्षेत्र के भीतर ऐसे करदाताओं के नाम, पते, हैसियत, कर निर्धारण वर्ष और लगाये गये जुर्माने का ब्यौरा, जिसमें करदाताओं से संबंधित जुर्माने की राशि तथा प्रकृति (प्रकार) भी शामिल होगी तथा जिन पर वित्तीय वर्ष 1974-75 के दौरान 5000/- रु० से अन्यून का जुर्माना लगाया गया था प्रकाशित करने के लिए प्राधिकृत किया है ।

अतः अब केन्द्रीय सरकार द्वारा उसके दिनांक 25 जून, 1969 के पूर्वोक्त आदेश द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं इससे संलग्न अनुसूची में पूर्वोक्त करदाताओं के नाम तथा अन्य विशिष्टियां प्रकाशित करता हूं ।

आयकर विभाग, पटियाला

ऐसे करदाता जिन पर वित्तीय वर्ष 1974-75 के दौरान आय छिपाने के कारण 5000/- रु० से अन्यून का जुर्माना लगाया गया था; (iv) हैसियत के लिए है--'सी' कम्पनी के लिए: (ii) कर निर्धारण वर्ष के लिए तथा (iii) लगाये गये जुर्माने के लिए है ।

1. मैसर्स द हरियाणा इन्डस्ट्रीज (प्रा०) लि०, रोहतक (i) 'सी' (ii) 1965-66 (iii) 75,000 रु०

[फा० सं० मुख्य/प्रका०/75-76/]

Patiala, the 22nd October, 1975

S.O. 4947.—Whereas the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in public interest to publish the names and other particulars relating to assessees on whom penalty of not less than Rs. 5,000 was imposed during the financial year 1974-75;

And whereas in exercise of the powers conferred by section 287 of the Income-tax Act (43 of 1961) and all other powers enabling them in this behalf the Central Government has by its order dated 25th March, 1969 authorised all Commissioners of Income-tax to publish the names, addresses, status, assessment year and details of penalties levied which would include the amounts and nature of penalties relating to assessees, within their jurisdiction and on whom a penalty of not less than Rs. 5,000 was imposed during, the financial year 1974-75;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred on me by the Central Government by its aforesaid order dated 25th March, 1969 I hereby publish in the schedule, hereto annexed, the names and other particulars of the assessees aforesaid.

Income-tax Department, Patiala

Assessees on whom a penalty of not less than Rs. 5000 was imposed for concealment of income during the financial year 1974-75; (i) is for status 'C' for Company : (ii) for assessment year and (iii) for penalty imposed.

1. M/s. The Haryana Industries (P) Ltd.; Rohtak (i) 'C' (ii) 1965-66 (iii) Rs. 7,500.

[F. No. H.Q. II/Pub/75-76]

पटियाला, 25 अक्तूबर, 1975

का० आ० 4948.—यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में यह आवश्यक तथा समीचीन है कि वित्तीय वर्ष 1974-75 के दौरान ऐसे सभी करदाताओं के :—

(i) जो कि व्यष्टि, अथवा हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब हैं तथा जिनकी आय एक लाख रुपयों से अधिक निर्धारित की गई है, और

(ii) जो फर्म, कम्पनी अथवा अन्य व्यक्ति संगम हैं, जिनकी आय दस लाख रुपये से अधिक निर्धारित की गई है,

नाम तथा उनसे सम्बन्धित यहां इसके पश्चात् विनिर्दिष्ट अन्य विशिष्टियां प्रकाशित की जाएं;

और यतः आयकर अधिनियम (1961 का 43) की धारा 287 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का तथा इस निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने अपने दिनांक 5 जुलाई, 1974 के आदेश द्वारा सभी आयकर आयुक्तों को वित्तीय वर्ष 1974-75 के दौरान अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर स्थित ऐसे करदाताओं से सम्बन्धित नाम, पते, हैसियत तथा कर निर्धारण वर्ष और दी गई आय विवरणी, कर निर्धारित आय, दिया जाने वाला कर तथा दिया गया कर प्रकाशित करने के लिये प्राधिकृत किया है।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार द्वारा उसके दिनांक 5 जुलाई, 1974 के पूर्वोक्त आदेश द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं इससे संलग्न अनुसूची में पूर्वोक्त करदाताओं के नाम तथा अन्य विशिष्टियां प्रकाशित करता हूं।

आयकर विभाग, पटियाला

ऐसे सभी व्यष्टियों तथा हिन्दू अविभक्त कुटुम्बों के नाम, जिनकी आय वित्तीय वर्ष 1974-75 के दौरान एक लाख रुपये से अधिक निर्धारित की गई है : (i) हैसियत के लिए—'आई' व्यष्टि के लिए, 'एच' हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब के लिए, (ii) निर्धारण वर्ष के लिए, (iii) दी गई आय विवरणी के लिए, (iv) निर्धारित आय के लिए, (v) दिये जाने वाले कर के लिए, (vi) दिये गये कर के लिए है।

1. मोदी डी० डी० एण्ड सन्ज, सुनाम (i) 'एच' (ii) 1974-75 (iii) 1,67,621 रु० (iv) 1,68,060 रु० (v) 1,32,197 रु० तथा (vi) 1,32,197 रु०।

2. श्री दीपक राज नाथ मार्फत मैसर्ज दीपक वुलन इन्डस्ट्रीज, पानीपत (i) आई (ii) 1973-74 (iii) 1,01,010 रु० (iv) 1,02,870 रु० (v) 62,440 रु० तथा (vi) 62,440 रु०।

3. श्री डी० डी० पुरी मार्फत मैसर्ज सरस्वती इन्डस्ट्रीयल सिन्डीकेट, यमुना नगर (i) आई (ii) 1974-75 (iii) 1,81,906 रु० (iv) 1,91,040 रु० (v) 1,00,544 रु० तथा (vi) 1,00,544 रु०।

4. श्री के० आर० मल्होत्रा मार्फत मैसर्ज पंजाब व्यापार एवं पूर्ति कं०, यमुना नगर (i) आई (ii) 1974-75 (iii) 1,27,230 रु० (iv) 1,27,280 रु० (v) 83,153 रु० तथा (vi) 83,153 रु०।

5. श्रीमती भगवती देवी, गिनेरीवाला, सरसा (i) आई (ii) 1974-75 (iii) 1,94,660 रु० (iv) 1,95,880 रु० (v) 1,32,118 रु० तथा (vi) 1,32,118 रु०।

[फा० संख्या मुख्य० II प्रशासन/आ० कर/75-76/2]

एम० एस० उन्नीनायर, आयकर आयुक्त।

Patiala, the 25th October, 1975

S.O. 4948.—Whereas the Central Government is of opinion that it is necessary and expedient in the public interest to publish the names and other particulars hereinafter specified relating to assessees :

(i) being Individuals, or Hindu Undivided Families, who have been assessed on an income of more than one lakh of rupees, and

(ii) being firms, companies, or other association of persons, who have been assessed on an income of more than ten lakhs of rupees,

during the financial year 1974-75;

And whereas in exercise of the powers conferred by section 287 of the Income-tax Act (43 of 1961) and all other powers enabling them in this behalf, the Central Government has by its order dated 5th July, 1974, authorised all Commissioners of Income-tax to publish the names, addresses, status and assessment year, relating to assessees within their jurisdiction and the income returned by, the income assessed on, the tax payable by, and the tax paid by, such assessees during the financial year 1974-75;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred on me by the Central Government by its aforesaid order dated 5th July, 1974, I hereby publish in the schedule, hereto annexed, the names and other particulars of the assessees aforesaid.

INCOME-TAX DEPARTMENT PATIALA

Names of all Individuals and Hindu Undivided Families assessed on an income of more than Rs. one lakh during financial year 1974-75 : (i) is for status—'I' for Individual, 'H' for H.U.F, (ii) for Assessment year, (iii) for Income returned, (iv) for Income assessed, (v) for Tax payable and (vi) for Tax paid.

1. Modi D. D. & Sons, Sunam (i) 'H' (ii) 1974-75 (iii) Rs. 1,67621, (iv) Rs. 1,68,060, (v) Rs. 1,32,197, (vi) Rs. 1,32,197.

2. Shri Deepak Raj Nath C/o M/s. Deepak Woollen Industries, Panipat (i) 'I', (ii) 1973-74, (iii) Rs. 1,01,010, (iv) Rs. 1,02,870, (v) Rs. 62,440 and (vi) Rs. 62,440.

3. Shri D. D. Puri C/o M/s. Saraswati Industrial Syndicate, Yamunanager (i) I (ii) 1974-75 (iii) Rs. 1,81,906 (iv) Rs. 1,91,040 (v) 1,00,544 and (vi) Rs. 1,00,544.

4. Shri K. R. Malhotra C/o M/s Punjab Business and Supply Co. Yamunanagar (i) 'I' (ii) 1974-75 (iii) Rs. 1,27,230 (iv) Rs. 1,27,280 (v) Rs. 83,153 and (vi) Rs. 83,153.

5. Smt. Bhagwati Devi, Ganeriwala, Sirsa (i) 'I' (ii) 1974-75 (iii) Rs. 1,94.660 (iv) Rs. 1,95,880 (v) Rs. 1,32,118 and (vi) 1,32,118.

[F. No. HQ II/Pub/I. Tax/75-76/2]

M. S. UNNINAYAR, Commissioner.

पटियाला, 27 अक्तूबर, 1975

का०आ० 4949.—आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 287 के अधीन ऐसे करदाताओं की सूची, जिन पर वित्तीय वर्ष 1974-75 के दौरान आय छिपाने के कारण 5000 रु० (पांच हजार रुपये) से अधिक का जुर्माना लगाया गया था : (i) हैसियत के लिए है,—'एफ' फर्म के लिए,

'ए ओ पी' व्यक्ति संगम के लिए तथा 'आई' व्यष्टि के लिए, (ii) कर निर्धारण वर्ष के लिए है (iii) लगाये गये जुर्माने के लिये है।

1. श्री देव राज मार्फत शान्ति सरूप देव राज, चौड़ा बाजार, लुधियाना (i) 'आई' (ii) 1968-69 (iii) 8000 (ii) 1969-70 (iii) 8000.
2. मैसर्ज गिर्सन निटिंग वर्क्स, सबन बाजार, लुधियाना। (i) 'एफ' (ii) 1970 71 (iii) 85,580.
3. मैसर्ज बस्सी गुजरान लेबर एण्ड कन्स्ट्रक्शन सोसाइटी लिमि०, गांव डुगरी, जिला लुधियाना (i) 'ए ओ पी' (ii) 1970-71 (iii) 31,477.

[फा० सं० रैक /प्रकाशन II]

वी० पी० गुप्ता, आयुक्त

Patiala, the 27th October, 1975

S.O. 4949.—List of assessees on whom a penalty of not less than Rs. 5000 (Five thousand) was imposed for concealment of income during the financial year 1974-75, under section 287 of the I.T. Act, 1961.(i) stand for statu—'F' for firm, 'AOP' for Association of persons and 'I' for Individual, (ii) stands for assessment year (iii) for amount of penalty.

1. Sh. Dev Raj C/o Shanti Sarup Dev Raj Chaura Bazar, Ludhiana (i) 'I' (ii) 1968-69 (iii) 8000 (ii) 1969-70 (iii) 8000.
2. M/Girson Knitting Works, Saban Bazar, Ludhiana (i) 'F' 1970-71 (iii) 85,580.
3. M/s. Bassi Gujjran Labour & Construction Society Ltd., village Dugri, Distt. Ludhana (i) 'AOP' (ii) 1970-71 (iii) 31,477.

[F. No. Rec/Publication/II]

V. P. GUPTA, Commissioner

आयकर आयुक्त का कार्यालय, केरल

आयकर विभाग

कोच्चिन, 28 अक्तूबर, 1975

का० आ० 4950.—करदाताओं की सूची निम्नलिखित है :—

(अ) जिनपर व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब होने से, एक लाख रुपये से अधिक आय पर निर्धारित किया गया है (नाम संलग्न अनुसूची (i) में है।

(आ) जिनपर फर्म या व्यक्तियों का संगम या कंपनी होने से, बस लाख रुपये से अधिक आय पर निर्धारित किया गया है (नाम संलग्न अनुसूची (2) में है)

(i) स्थिति की सूचना; "ऐ"—व्यक्ति के लिए और "को"—कंपनी के लिए (ii) निर्धारण वर्ष (iii) निर्धारित आय (iv) निर्धारित आय (v) आयकर देय (vi) आयकर प्रदत्त।

यह सूचना 74-75 में की गई निर्धारण के अनुसार है।

(अ) (1) श्री सी० एल० आनन्द, मैनेजिंग डायरेक्टर, मेसर्स तोषिबा आनन्द लाम्पस् लि०, एरणकुलम। (i) ऐ (ii) 73-74 (iii) 88600 (iv) 101700 (v) 18753 (vi) 18753 (2) श्री के०जे० अगस्टीन, के० जे० जोसफ एन्ड कं० कोच्चिन-2. (i) ए (ii) 72-73 (iii) 82410 (iv) 144330 (v) 100584 (vi) 44629 (3) श्री० ए० अब्दुल रहिमान, चावकाड, (i) ऐ (ii) 72-73 (iii) 221004 (iv) 225480 (v) 176707 (vi) 172922 (4) श्री ए० अब्दुल रहिमान, चावकाड (i) ऐ (ii) 73-74 (iii) 190505 (iv) 193430 (v) 143798 (vi) 101808 (5) हाजी ए० अब्दुलखातर, चावकाड (i) ऐ (ii) 73-74 (iii) 115270 (iv) 117530 (v) 73956 (vi) 10488 (6) श्री टी० अब्दुलकरीम मुसलियार, कम्पिकेट्टिल हाऊस, किलिकोल्लूर, कोइलोन (i) ऐ (ii) 74-75 (iii) 143857 (iv) 163890 (v) 115711 (vi) 115711 (7) श्री एस० अनियन, प्राधिकृतः पी शत्रुघन्न पिल्लै, श्रीवराहन, तेवल्ली, कोल्लम (i) ऐ (ii) 74-75 (iii) 73930 (iv) 133780 (v) 97444 (vi) 97444 (8) श्री टी० असुमा बीवी, कम्पिकेट्टिल हाऊस, किलिकोल्लूर, कोल्लम (i) ऐ (ii) 74-75 (iii) 144820 (iv) 165750 (v) 118701 (vi) 118701 (9) श्री यू० के० अप्पू, कालिकट् (i) ऐ (ii) 74-75 (iii) 127960 (iv) 126940 (v) 84585 (vi) 30000 (10) श्री एम० अप्पुकुट्टि, कालिकट् (i) ऐ (ii) 72-73 (iii) (—) 11970 (iv) 115110 (v) 73701 (vi) 3154 (11) पी० बेरनाड आन्नो, मेसर्स पोल आन्नो एण्ड सन्ज, कोच्चिन-3 (i) ऐ (ii) 72-73 (iii) 116620 (iv) 119970 (v) 78172 (vi) 14000 (12) श्री सी० के० बाबू नाइडु, कालिकट (i) ऐ (ii) 74-75 (iii) 119900 (iv) 119900 (v) 79625 (vi) 79625 (13) श्री ए० पी० बालकृष्ण पिल्लै, कालिकट (i) ऐ (ii) 74-75 (iii) 109750 (iv) 101690 (v) 68835 (vi) 68835 (14) श्री० आर० चन्द्रशेखरन, पार्टनर, मे० आर० रामलिंगय्यर, एरणाकुलम (i) ऐ (ii) 74-75 (iii) 98300 (iv) 102050 (v) 61686 (vi) 58334 (15) श्री ए० डब्ल्यू० जे० केपर, कोरटिट् (i) ऐ (ii) 74-75 (iii) 166300 (iv) 166300 (v) 120796 (vi) 120796 (16) श्री जी० धरमराजन, पी० डब्ल्यू० डी० कोण्ट्राक्टर, करलूविला वीडु, कौन्सी, (i) ऐ (ii) 73-74 (iii) 90650 (iv) 126960 (v) 39723 (vi) 39723 (17) के० जे० फ्रान्सीस, ट्रिच्चूर (i) ऐ (ii) 70-71 (iii) 222555 (iv) 226400 (v) 149672 (vi) 149672 (ii) 71-72 (iii) 179359 (iv) 183200 (v) 130716 (vi) 130716 (ii) 69-70 (iii) 257300 (iv) 261140 (v) 176677 (vi) 176677 (18) श्री जे० इ० फोरब्स, कोरट्टिट (i) ऐ (ii) 74-75 (iii) 160720 (iv) 160720 (v) 115662 (vi) 115662 (19) जे०इ०आर० ग्रिफिस, कोरट्टी (i) ऐ (ii) 74-75 (iii) 170500 (iv) 170500 (v) 124706 (vi) 124706 (20) श्री ऐ० वी० गोविन्दन, ट्रिच्चूर (i) ऐ (ii) 73-74 (iii) 124853 (iv) 131360 (v) 88651 (vi) 88651 (21) श्री पी० गोपिनाथन नायर, जूपिटर काष्यू कं०, कोल्लम (i) ऐ (ii) 73-74 (iii) 107070 (iv) 107380 (v) 67761 (vi) 67761 (22) एच० एच० गौरी पार्वती बाई, कोडियार पालस, तिरुवनन्तपुरम (i) ऐ (ii) 74-75 (iii) 176670 (iv) 181210 (v) 109060 (vi) 96638 (23) एच० एच० गौरी लक्ष्मी बाई, प्रिन्सेस, कौडियार पालस, तिरुवनन्तपुरम, (i) ऐ (ii) 74-75 (iii) 197677 (iv) 199200 (v) 134651 (vi) 134651 (24) श्री पी० वी० गंगाधरन, कालिकट (i) ऐ (ii) 74-75 (iii) 109222 (iv) 111165 (v) 75516 (vi) 49356 (25) श्री० एम० हरिदास, कालिकट (i) ऐ (ii) 72-73 (iii) 208 (iv) 136730 (v) 65992 (26) श्री जोसेफ जोन, कुन्नत फिनान्शियल कोरपोरेशन, तुरवूर (i) ऐ (ii) 73-74 (iii) 78613 (iv) 116120 (v) 74635

(27) श्री पी० टी० जोसेफ, जुवल्लर, कोट्टयम (i) ऐ (ii) 74-75 (iii) 80540 (iv) 111310 (v) 70205 (vi) 51592 (28) श्री एम० जयराजन, कालिकट (i) ऐ (ii) 72-73 (iii) (-)1047 (iv) 103040 (v) 62597 (29) श्री कुरियन अब्रहाम, 'ऊपूट्टिल', कोट्टयम (i) ऐ (ii) 74-75 (iii) 115420 (iv) 115420 (v) 73656 (vi) 73656 (30) श्री सी० आर केशवन वैद्यर, इरिन्जाल कुडा, (i) ऐ (ii) 72-73 (iii) 102190 (iv) 119350 (v) 77602 (vi) 61816 (31) श्री सी० एम० एम० लारन्स, वेन्टवोर्त एस्टेट, चेरम्बाडी पी० ओ (i) ऐ (ii) 73-74 (iii) 135295 (iv) 146650 (v) 101346 (vi) 101346 (32) मेरी पोल बाबी, चिट्टूर रोड, एरणाकुलम (i) ऐ (ii) 72-73 (iii) 92330 (iv) 110880 (v) 69810 (vi) 14705 (33) श्री सी० के० मनिलाल, पार्टनर, लाल प्रोडक्ट्स, एरणाकुलम (i) ऐ (ii) 72-73 (iii) 142550 (iv) 141810 (v) 98265 (vi) 98265 (34) श्री सी० जी० आर० मेक नेइलि, मलयालम प्लान्टेशन्स लि०, अप्पर सूरिनेलि एस्टेट, सूरिनेलि पी० ओ० (i) ऐ (ii) 72-73 (iii) 109200 (iv) 109200 (v) 68206 (vi) 68206 (35) श्री सी० जी० आर० मेक नेइलि, मलयालम प्लान्टेशन्स लि०, (i) ऐ (ii) 73-74 (iii) 102160 (iv) 105040 (v) 64390 (vi) 64390 (36) श्री ई० जे० मेक इन्तोष, कोरट्टि (i) ऐ (ii) 74-75 (iii) 132660 (iv) 132660 (v) 89846 (vi) 89846 (37) श्रीमती टी० मरियम बीवी, कम्पिकेट्टिल हाऊस, किलिकोल्लूर, कोल्लम । (i) ऐ (ii) 74-75 (iii) 136618 (iv) 141210 (v) 99987 (vi) 99987 (38) श्रीमती टी० मइमून बीवी, कम्पिकेट्टिल हाउस, किलिकोल्लूर, कोल्लम (i) ऐ (ii) 74-75 (iii) 136573 (iv) 140840 (v) 99415 (vi) 99415 (39) श्री के० राजेन्द्रप्रसाद, कोइलोन मरयिन प्रोड्यूस कं०, कोल्लम (i) ऐ (ii) 74-75 (iii) 92120 (iv) 110450 (v) 71829 (vi) 71829 (40) एच० एच० रामवर्मा, 1 प्रिन्स, कौडियार पालस, तिरुवनन्तपुरम (i) ऐ (ii) 74-75 (iii) 250530 (iv) 256530 (v) 220858 (vi) 220858 (41) श्री एन० लोरन्स, ऐसफील्ड एस्टेट, कलत्तुकरिस (i) ऐ (ii) 72-73 (iii) 140055 (iv) 141850 (v) 97066 (vi) 97066 (ii) 73-74 (iii) 132885 (iv) 134460 (v) 97155 (vi) 97155 (ii) 74-75 (iii) 132325 (iv) 134220 (v) 90263 (vi) 90263 (42) श्री पी० सोलमन अब्रो, मे० पोल आब्रो एण्ड सन्स, कोच्चिन-3 (i) ऐ (ii) 72-73 (iii) 116620 (iv) 153360 (v) 108891 (vi) 7339 (43) एच० एच० सेतु पार्वती बाई, कौडियार पालस, तिरुवनन्तपुरम (i) ऐ (ii) 74-75 (iii) 246480 (iv) 246490 (v) 211035 (vi) 211035 (44) टी० सफिया बीवी, कम्पिकेट्टिल हाऊस, किलिकोल्लूर कोल्लम (i) ऐ (ii) 74-75 (iii) 139470 (iv) 143730 (v) 102740 (vi) 102740 (45) स्वर्गीय बी० एन० श्रीधरन उण्णि, "धुवारका" तैकाड, तिरुवनन्तपुरम (i) ऐ (ii) 69-70 (iii) 127127 (iv) 186020 (v) 46247 (46) श्री सैद अब्दुरहिमान जिफ्रि, कालिकट (i) ऐ (ii) 72-73 (iii) 20640 (iv) 152860 (v) 108376 (47) श्री पेरिका हमीद, कालिकट (i) ऐ (ii) 72-73 (iii) 18110 (iv) 100040 (v) 59807 (48) श्री सैद फसल जिफ्रि, कालिकट (i) ऐ (ii) 72-73 (iii) 47430 (iv) 151950 (v) 107552 (49) श्री सैद अलावी जिफ्री, कालिकट (i) ऐ (ii) 72-73 (iii) 92400 (iv) 130440 (v) 86586 (vi) 19261 (50) श्री ओ० तोमस, मेनेजिंग डायरेक्टर, फोरब्स इवार्ट एण्ड फिगिस लि०, कोच्चिन (i) ऐ (ii) 73-74 (iii) 108550 (iv) 114290 (v) 72947 (vi) 66798 (51) उमयबाम बीवी, टी, कम्पिकेट्टिल हाऊस, किलिकोल्लूर, कोल्लम (i) ऐ (ii) 74-75 (iii) 144180 (iv) 150430 (v) 106196 (vi) 106196 (52) श्री ए० एन० विश्वनाथकम्मत, हिन्दुस्तान हार्डवेयर्स, कोच्चिन-2 (i) ऐ (ii) 72-73 (iii) 100984 (iv) 102000 (v) 61621 (vi) 61621 (53) श्री एम० के० विजयराघवन, त्रिच्चूर (i) ऐ (ii) 63-64 (iii) 184538 (iv) 190330 (v) 129804 (vi) 129804 (54) श्रीमती के० वसन्ता, श्रीवास, तामरकुलम, कोल्लम (i) ऐ (ii) 74-75 (iii) 106440 (iv) 114200 (v) 85543 (vi) 85543 (55) श्रीमती के० के० यशोधरा, ट्रिच्चूर (i) ऐ (ii) 74-75 (iii) 104540 (iv) 106480 (v) 68852 (vi) 66233 ।

(आ) (1) मे० चाकोलास स्पिन्निंग एण्ड वीविंग मिल्स लि०, कलमश्शेरी (i) प्राइवेट लि० कम्पनी (ii) 74-75 (iii) 116130 (iv) 1388940 (v) 906232 (vi) 580983 (2) मे० फोरब्स इवार्ड एण्ड फिगिस लि०, कोच्चिन-3 (i) प्राइवेट लि० कंपनी (ii) 73-74 (iii) 1116700 (iv) 1140040 (v) 759609 (vi) 759609 (3) निलम्पूर कोविलकम फोरस्ट्स, निलम्पूर (i) ए०ओ० पी० (ii) 71-72 (iii)--(iv) 3750000 (v) 1884066 (4) वेस्टेण इण्डिया कोट्टणस लि०, पापिनिश्शेरी (i) कंपनी (ii) 74-75 (iii) 1057200 (iv) 1579210 (v) 983033 (vi) 655826।

× × × × ×

(क) आयकर अधिनियम 1961 के खण्ड 271 (1)(सी) के अनुसार आय की सूचना छिपाने के कारण जिन्हें दण्डित किया गया है या जहां गत वर्षों के दण्डों पर दिये हुए अपील का फैसला 1974-75 में दिया जा चुका है ।

(ख) आय विवरणी देने के या लेखाबहियां प्रस्तुत करने के अभाव में दण्डित किया गया है ।

(क) (1) मे० एकमेल प्रोडक्शन्स, आलप्पी, (i) रेजिस्टर्ड फर्म (ii) 1964-65 (iii) 9854 (2) पी० एल० औसेफ, चैम्पियन फायर वर्कस एन्ड इन्डस्ट्रीस, इरिन्जालकुडा (i) ऐ (ii) 1971-72 (iii) 12360 ।

(ख) (1) पी० ए० अब्दुल रहिमानकुट्टी एण्ड सन्स, कोच्चिन-1 (i) फर्म (रजिस्टर्ड) (ii) 1970-71 (iii) 14472 (2) एम० पी० आज़ाद, आजाद होटल, पथवन्गाडी, तिरुवनन्तपुरम (i) ऐ (ii) 70-71 (iii) 18050 (3) पी० बी० रघुनाथ, 19ए, 3 फ्लोर, पैपवाल बिल्डिंग्स, कोलबा रोड, बंबई-5 (i) ऐ (ii) 1970-71 (iii) 16340।

[सी० सं० 10/बी/टेक/ए/75-76 (1)]

पी० सदगोपन, आयुक्त ।

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF INCOME-TAX, KERALA

(Income-Tax Department)

Cochin, the 28th October, 1975

S.O.4950.—Following is the list of assessees (a) being the individuals or Hindu Undivided Families, who have been assessed on an income of more than one lakh of rupees, in Schedule I appended hereto; (b) being Firms, Association of Persons or Companies who have been assessed on an income of

more than 10 lakhs of rupees, in Schedule II appended hereto: (i) indicates status—'I' for 'Individual' and 'Co.' for company. (ii) Assessment Year (iii) Income returned (iv) Income assessed (v) Income-tax payable (vi) Income-tax paid. The information is with reference to assessments made during 1974-75.

(A) (1) Shri. C.L. Anand, Mg. Director, M/s. Toshiba Anand Lamps Ltd. Ernakulam (i) I (ii) 73-74 (iii) 88600 (iv) 101700 (v) 18753 (vi) 18753 (2) Shri K.J. Augustine, K.J. Joseph & Co., Cochin-2. (i) I (ii) 72-73 (iii) 82410 (iv) 144330 (v) 100584 (vi) 44629 (3) Shri A. Abdul Rahiman, Choughat (i) I (ii) 72-73 (iii) 221004 (iv) 225480 (v) 176707 (vi) 172922 (4) Shri A. Abdul Rahiman, Choughat (i) I (ii) 73-74 (iii) 190505 (iv) 193430 (v) 143798 (vi) 101808 (5) Haji A. Abdulkhader, Choughat (i) I (ii) 73-74 (iii) 115270 (iv) 117530 (v) 73956 (vi) 10488 (6) Shri T. Abdulkarim Musaliar, Kampikettil House, Kilikollur, Quilon (i) I (ii) 74-75 (iii) 143857 (iv) 163890 (v) 115711 (vi) 115711 (7) Shri S. Aniyan, Re. by P. Satrughnan Pillai, Sreevarahan Thevally, Quilon (i) I (ii) 74-75 (iii) 73930 (iv) 133780 (v) 97444 (vi) 97444 (8) Shri T. Assuma Beevee, Kampikettil House, Kilikolloor, Quilon (i) I (ii) 74-75 (iii) 144820 (iv) 165750 (v) 118701 (vi) 118701 (9) Shri U.K. Appu, Calicut (i) I (ii) 74-75 (iii) 127960 (iv) 126940 (v) 84585 (vi) 30000 (10) Shri M. Appukutty, Calicut (i) I (ii) 72-73 (iii) (—) 11970 (iv) 115110 (v) 73701 (vi) 3154 (11) P. Bernad Abro, M/s. Paul Abrao & Sons, Cochin-3 (i) I (ii) 72-73 (iii) 116620 (iv) 119970 (v) 78172 (vi) 14000 (12) Shri C.K. Babu Naidu, Calicut (i) I (ii) 74-75 (iii) 119900 (iv) 119900 (v) 79625 (vi) 79625 (13) Shri A.P. Balakrishna Pillai, Calicut (i) I (ii) 74-75 (iii) 109750 (iv) 101690 (v) 68835 (vi) 68835 (14) Shri R. Chandrasekharan, Partner M/s R. Ramalinga Iyer, Ernakulam (i) I (ii) 74-75 (iii) 98300 (iv) 102050 (v) 61686 (vi) 58334 (15) Shri A.W.J. Caper, Koratty, (i) I (ii) 74-75 (iii) 166300 (iv) 166300 (v) 120796 (vi) 120796 (16) Shri G. Dharmajan, PWD Contractor, Kalluvila Veedu, Kanchi, (i) I (ii) 73-74 (iii) 90650 (iv) 126960 (v) 39723 (vi) 39723 (17) K.J. Francis, Trichur (i) I (ii) 70-71 (iii) 222555 (iv) 226400 (v) 149672 (vi) 149672 (ii) 71-72 (iii) 179359 (iv) 183200 (v) 130716 (vi) 130716 (ii) 69-70 (iii) 257300 (iv) 261140 (v) 176677 (vi) 176677 (18) Shri. J.E. Forbes, Koratty (i) I (ii) 74-75 (iii) 160720 (iv) 160720 (v) 115662 (vi) 115662 (19) J-E. R. Griffith, Koratty, (i) I (ii) 74-75 (iii) 170500 (iv) 170500 (v) 124706 (vi) 124706 (20) Shri I.V. Govindan, Trichur (i) I (ii) 73-74 (iii) 124853 (iv) 131360 (v) 88651 (vi) 88651 (21) Shri P. Gopinathan Nair, Jupitor Ceshew Co. Quilon (i) I (ii) 73-74 (iii) 107070 (iv) 107380 (v) 67761 (vi) 67761 (22) H.H. Gouri Parvathi Bavi, Kaudiar Palace, Trivandrum (i) I (ii) 74-75 (iii) 176670 (iv) 184210 (v) 109060 (vi) 96638. (23) H.H. Gouri Lakshmi Bayi, Princess, Kaudiar Palace, Trivandrum (i) I (ii) 74-75 (iii) 197677 (iv) 199200 (v) 134651 (vi) 134651 (24) Shri P.V. Gangadharan, Calicut (i) I (ii) 74-75 (iii) 109222 (iv) 111165 (v) 75516 (vi) 49356 (25) Shri. M. Harides, Calicut (i) I (ii) 72-73 (iii) 208 (iv) 136730 (v) 65992 (26) Shri. Joseph John, Kunnath Financial Corporation, Thuraveor (i) I (ii) 73-74 (iii) 78613 (iv) 116120 (v) 74635 (27) Shri P.T. Joseph, Joweller Kottayam (i) I (ii) 74-75 (iii) 80540 (iv) 111310 (v) 70205 (vi) 51592 (28) Shri M. Jayarajan, Calicut (i) I (ii) 72-73 (iii) (—) 1047 (iv) 103040 (v) 62597 (29) Shri Kurian Abraham 'Ooppoottil' Kottayam (i) I (ii) 74-75 (iii) 115420 (iv) 115420 (v) 73656 (vi) 73656 (30) Shri C.R. Kesavan Vaidyar, Irinjalakuda (i) I (ii) 72-73 (iii) 102190 (iv) 119350 (v) 77602 (vi) 61816 (31) Shri C.M.M. Lawrence, Wentworth Estate, Cherambadi (P. O) (i) I (ii) 73-74 (iii) 135295 (iv) 146650 (v) 101346 (vi) 101346 (32) Mary Paul Abro, Chittoor Road, Ernakulam (i) I (ii) 72-73 (iii) 92330 (iv) 110880 (v) 69810 (vi) 14705 (33) Shri C.K. Manilal, Partner, Lal Products, Ernakulam (i) I (ii) 72-73 (iii) 142550 (iv) 141810 (v) 98265 (vi) 98265 (34) Shri C.G.R. Mc. Neilly, Malayalam Plantations Ltd., Upper Surinelle Estate, Surenelli P.O. (i) I (ii) 72-73 (iii) 109200 (iv) 109200 (v) 68206 (vi) 68206 (35) Shri C.G. R. Mc. Neilly, Malayalam Plantations Ltd. (i) I (ii) 73-74 (iii) 102160 (iv) 105040 (v) 64390 (vi) 64390 (36) Shri. E.J. Mc. Intosh, Koratty (i) I (ii) 74-75 (iii) 132660 (iv) 132660 (v) 89846 (vi) 89846 (37) Smt. T. Mariam Beevi, Kampikettil House, Killikollur, Quilon (i) I (ii) 74-75 (iii) 136618 (iv) 141210 (v) 99987 (vi) 99987 (38) Smt. T. Maimoom Beevi, Kampikettil House, Kilikollur, Quilon, (i) I (ii) 74-75 (iii) 136574 (iv) 140840 (v) 99415 (vi) 99415 (39) Shri K. Rajendra Prasad, Quilon Marine Produce Co., Quilon (i) I (ii) 74-75 (iii) 92120 (iv) 110450 (v) 71829 (vi) 71829. (40) H.H. Ramavarma, 1st Prince, Kaudiar Palace Trivandrum (i) I (ii) 74-75 (iii) 250530 (iv) 256530 (v) 220858 (vi) 220858 (41) Shri N. Slorence, Isfield Estate, Kalthuruthy (i) I (ii) 72-73 (iii) 140055 (iv) 141850 (v) 97066 (vi) 97066 (ii) 73-74 (iii) 132885 (iv) 134460 (v) 97155 (vi) 97155 (ii) 74-75 (iii) 132325 (iv) 134220 (v) 90263 (vi) 90263 (42) Shri P. Solomon Abrac, M/s. Paul Abro & Sons, Cochin-3 (i) I (ii) 72-73 (iii) 116620 (iv) 153360 (v) 108891 (vi) 7339 (43) H.H. Sethu Parvathi Bayi, Kaudiar Palace, Trivandrum (i) I (ii) 74-75 (iii) 246480 (iv) 246490 (v) 211035 (vi) 211035 (44) T. Safia Beevi, Kampikettil House, Kilikollur, Quilon (i) I (ii) 74-75 (iii) 139470 (iv) 143730 (v) 102740 (vi) 102740 (45) Late B.N. Sreodharan Unni, "Dwaraka", Thycaud, Trivandrum (i) I (ii) 69-70 (iii) 127127 (iv) 186020 (v) 46247 (46) Shri Syed Abdurahiman Jifri, Calicut (i) I (ii) 72-73 (iii) 20640 (iv) 152860 (v) 108376 (47) Shri Shorifa Hameed, Calicut (i) I (ii) 72-73 (iii) 18110 (iv) 100040 (v) 59807 (48) Shri Syed Fazal Jifri, Calicut (i) I (ii) 72-73 (iii) 47430 (iv) 151950 (v) 107552 (49) Shri Syed Alavi Jifri, Calicut (i) I (ii) 72-73 (iii) 92400 (iv) 130440 (v) 86586 (vi) 19261 (50) Shri. O. Thomas, Mg. Director, Forbes Eward & Figgis Ltd. Cochin (i) I (ii) 73-74 (iii) 108550 (iv) 114290 (v) 72947 (vi) 66798 (51) Umaiban Beevi. T. Kampikettil House, Kilikollur, Quilon (i) I (ii) 74-75 (iii) 144180 (iv) 150430 (v) 106196 (vi) 106196 (52) Shri A.N. Viswanathakamath, Hindustan Hardwares, Cochin-2 (i) I (ii) 72-73 (iii) 100984 (iv) 102000 (v) 61621 (vi) 61621 (53) Shri M.K. Vijayaraghavan, Trichur (i) I (ii) 63-64 (iii) 184538 (iv) 190330 (v) 129804 (vi) 129804 (54) Smt. K. Vasantha, Sreevilas, Thamarakulam, Quilon (i) I (ii) 74-75 (iii) 106440 (iv) 114200 (v) 85543 (vi) 85543 (55) Smt. K.K. Yeshodhara, Trichur (i) I (ii) 74-75 (iii) 104540 (iv) 106480 (v) 68852 (vi) 66233.

X X X X X

(B) (1) M/s. Chackolas Spinning & Weaving Mills Ltd., Kalamassery (i) Pvt. Ltd. Company (ii) 74-75 (iii) 116130 (iv) 1388940 (v) 906232 (vi) 580983 (2) M/s. Forbes Eward & Figgis Ltd., Cochin-3. (i) Pvt. Ltd. Company (ii) 73-74 (iii) 1116700 (iv) 1140040 (v) 759609 (vi) 759609 (3) Nilambur Kovilakam Forests, Nilambur, (i) A.O.P. (ii) 71-72 (iii)—(iv) 3750000 (v) 1884066 (4) Western India Cottons Ltd., Pappinisseri (i) Coy. (ii) 74-75 (iii) 1057200 (iv) 1579210 (v) 983033 (vi) 655826.

X X X X X

Persons who have been (a) penalised for concealment of income u/s. 271(1)(c) of the I.T. Act 1961 or where appeals against penalties levied in earlier years have been decided during the financial year 1974-75 ; (b) Penalised for failure to file returns of income or to produce books of account. (i) indicates status (ii) Asst. year (iii) Amount of penalty.

a. 1. M/s. Excell Productions, Alleppey, (i) Registered firm (ii) 1964-65 (iii) 9854 (2) P.L. Ouseph, Champion Fire Works & Industries, Irinjalakuda (i) I (ii) 1971-72 (iii) 12360.

b. (1) P.A. Abdul Rahimankutty & Sons, Cochin-1 (i) Firm (Reg.) (ii) 1970-71 (iii) 14472 (2) M.P. Azad, Azad Hotel, Pazhavangadi, Trivandrum (i) I (ii) 70-71 (iii) 18050, (3) P.V. Ragunath, 19A, 3rd Floor, Pipewall Buildings, Colaba Road, Bombay-5 (i) I (ii) 1970-71 (iii) 16340.

[C.No. 10/B/Tech/A/75-76(1)]

P. SADAGOPAN, Commissioner

केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क समाहर्तालय

पूना, 9 जुलाई, 1975

का०आ० 4951.—केन्द्रीय उत्पादशुल्क नियम, 1944 के नियम 143 और 233 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं आदेश देता हूं कि समाहर्तालय की दिनांक 9 मई, 1968 की अधिसूचना सं० 2/केन्द्रीय उत्पादशुल्क/1968 में निम्नलिखित संशोधन किया जाये ।

क्रमसंख्या (1) के रूप में निम्नलिखित अतिरिक्त मद समाविष्ट की जाये ।

"(1) टैरिफ मद 4-II (5) के अधीन आने वाले 'चबाने के तम्बाकू' के विनिर्माण में प्रयोग हेतु विभिन्न आकारों का फ्लेक तम्बाकू प्राप्त करने के लिये पूरी पत्ती के रूप में प्रसंस्कृत आई०ए०सी० तम्बाकू दलना (क्रश करना) ।

वर्तमान क्रमसंख्या बदलकर उस के स्थान पर 2 से 7 क्रमसंख्या कर दी जाये ।

[अधिसूचना सं० 2/केन्द्रीय उत्पादशुल्क/1975 फा०सं० 5(4) 30-38/टी० डी०/75]

जे०एम० वर्मा, समाहर्ता

CENTRAL EXCISE COLLECTORATE

Poona, the 9th July, 1975

S.O. 4951.—In exercise of the powers veste in me under Rules 143 and 233 of the Central Excise Rules, 1944, I order that the following amendments shall be made in this Collectorate Notification No. 2/Central Excise/1968 dated the 9th May, 1968.

Following additional item as Serial No. (1) may be inserted.

"(1) Crushing of IAC Tobacco cured in whole leaf form for obtaining different sizes of flake Tobacco intended to be used for manufacture of 'Chewing Tobacco' falling under T.I. 4 II(5)."

The existing serial numbers may be renumbered as 2 to 7.

[Notification No. 2/Central Excise/1975. F. No. V(4) 30-38/TD/75]

J. M. VERMA, Collector

केन्द्रीय उत्पादशुल्क समाहर्ता कार्यालय,

दिल्ली, 3 अक्तूबर, 1975

का० आ० 4952—केन्द्रीय उत्पादशुल्क नियमावली 1944 के नियम 5 के अन्तर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं एतद्द्वारा, दिल्ली केन्द्रीय उत्पादशुल्क समाहर्ता कार्यालय के उप-समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादशुल्क को यह प्राधिकार देता हूं कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में, केन्द्रीय उत्पादशुल्क नियमावली 1944 के नियम 173 जी० (4) के अन्तर्गत 'समाहर्ता' की शक्तियों का प्रयोग करें ।

भूतपूर्व दिल्ली समाहर्ता कार्यालय की तारीख 4-11-68 की अधिसूचना सं० 9/68 की क्रम संख्या 2 को इस सीमा तक संशोधित माना जाये।

[सी० सं० 1/75/4(8 /1 सी०ई०/73]

एम०एस० मेहता, समाहर्ता

CENTRAL EXCISE COLLECTORATE

(Central Excise)

Delhi, the 3rd October, 1975

S.O. 4952.—In exercise of the powers confererd upon me under Rule 5 of Central Excise Rules, 1944, I hereby authorise the Deputy Collector of Central Excise of the Delhi Central Excise Collectorate, to exercise within his jurisdiction, the powers of the 'Collector' under Rule 173G(4) of the Central Excise Rules, 1944.

2. The Sl. No. 2 of the Notification No. 9/68 dated 4-11-1968 of the erstwhile Delhi Collectorate should be treated as modified to this extent.

[C. No. 1/75/IV(8) 1CE/73]

M. S. MEHTA, Collector.

(केन्द्रीय उत्पाद शुल्क)

बड़ोदा, 27 अक्तूबर 1975

(सीमा शुल्क)

का० आ० 4953—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, गुजरात राज्य, बलसार जिला 'नवसारी' को भांडागार स्थान (बर हाऊसिंग स्टेशन) होने की घोषणा करता हूं ।

[सं० 2/75/8/48.31/सी०शु०/75]

एच०आर० सिएम, समाहर्ता

CENTRAL EXCISE

(Customs)

Baroda, the 27th October, 1975

S.O. 4953.—In exercise of the powers conferred on me by Section 9 of the Customs Act, 1962, I declare "NAVSARI', District Bulsar, in the State of Gujarat, to be a warehousing station.

[No. 2/75/VIII/48.31/Cus./75]

H. R. SYIEM, Collector.

सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादशुल्क समाहर्तालय, गोआ

पणजी, 28 अक्तूबर, 1975

का०आ० 4954—वित्त मंत्रालय (राजस्व तथा बीमा विभाग) की अधिसूचना संख्या 79/सीमाशुल्क/फा० सं० 473/2/75 सीमाVII दिनांक 18-7-75 के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 62 की धारा 9 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, एतद्द्वारा केन्द्र प्रशासित क्षेत्र गोआ के बिचेलिम तालुका में स्थित सिरीगांव ग्राम को भांडागार केन्द्र घोषित करता हूं ।

(फा० सं० 10/3/74 आई०और ई० से जारी)

ज्योतिमय दत्त,

सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादशुल्क समाहर्ता ।

COLLECTORATE OF CUSTOMS AND CENTRAL EXCISE-GOA

Panaji, the 28th October, 1975

S.O. 4954.—In exercise of the powers conferred on me under Section 9 of the Customs Act, 62, read with Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) Notification No. 79/Customs/F. No. 473/2/75-Cus. VII, dated 18-7-1975 I hereby declare village Sirigae, Bichelim Taluka, in the Union Territory of Goa, to be a Warehousing Station.

[Issues from F. No. 10/3/74-I& E]

J. DATTA, Collector of Customs & Central Excise

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 1975

का० आ० 4955—निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार वाणिज्य मंत्रालय में निदेशक (क्वालिटी नियंत्रण), श्री बी० कृष्णन्, आई०ए०एस०, को 22 अक्तूबर, 1975 के पूर्वाह्न से निरीक्षण तथा क्वालिटी नियंत्रण के निदेशक के रूप में एतद्द्वारा नियुक्त करती है ।

[फाइल संख्या 3(88)/75-ई०आई०एण्ड०ई०पी०]

के० वी० बाल सुब्रह्मण्यम, उपनिदेशक ।

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 22nd November, 1975

S.O. 4955.—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby appoints Shri V. Krishnan, I.A.S., Director (Quality Control) in the Ministry of Commerce, as the Director of Inspection and Quality Control, with effect from the forenoon of the 22nd October, 1975.

[F. No. 3(88)/75-E.I&E.P.]

K. V. BALASUBRAMANIAM, Dy. Director

संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात का कार्यालय

आदेश

कलकत्ता 16 अगस्त, 1975

का० आ० 4956.—राज्य व्यापार निगम भारत लि०, चन्द्रलोक, 36, जनपथ रोड, नई दिल्ली को बबूल के गोंद के आयात के लिये 21970 रुपये मूल्य का एक आयात लाइसेंस जी०टी० /177496/सी०/एक्स० एक्स०/50/सी०/37-38, दिनांक 28-2-74 वास्तविक उपयोक्ता फर्म सर्वश्री धनवन्तरी चिकित्सालय, 23ए०, कलाकार स्ट्रीट, कलकत्ता के नाम में प्राधिकार पत्र के साथ प्रदान किया गया था। फर्म ने लाइसेंस की अनुलिपि के लिये इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल लाइसेंस (सीमाशुल्क निकासी और मुद्रा विनिमय नियंत्रण दोनों प्रतियां) जो राज्य व्यापार निगम, नई दिल्ली, द्वारा उपर्युक्त वास्तविक उपयोक्ता फर्म को भेजा गया था उपयोग करने से पहले ही और किसी भी सीमाशुल्क प्राधिकारी से पंजीकृत कराये बिना ही फर्म से खो गया है या अस्थानस्थ हो गया है।

अपने तर्क के समर्थन में आवेदक ने महानगरीय मजिस्ट्रेट 16 कोर्ट कलकत्ता के सामने शपथ लेकर एक शपथ पत्र इस संबंध में दाखिल किया है कि लाइसेंस का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया गया है और न किसी भी उद्देश्य/प्राप्ति के लिये हमारे द्वारा या हमारी ओर से या किसी अन्य पक्ष द्वारा वह रद्द किया गया, रेहन रखा गया था या हस्तान्तरित किया गया था दिया गया है।

आवेदक ने मूल लाइसेंस की सीमाशुल्क और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रतियों को रद्द करने के लिये प्रार्थना की है और उसके बदले में फर्म ने उक्त लाइसेंस की अनुलिपि प्रतियों के लिये आवेदन किया है और वचन दिया है कि मूल लाइसेंस की सीमाशुल्क और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रतियां बाद में मिल गई तो निर्गम प्राधिकारियों को वापिस कर दी जायेंगी। राज्य व्यापार निगम ने भी सूचना दी है कि उन्हें इस विषय में कोई आपत्ति नहीं है। मैं संतुष्ट हूं कि मूल लाइसेंस सं० जी०टी०/1774961/सी०/एक्स०एक्स०/50 सी०/37-38 दिनांक 28-2-74 की सीमाशुल्क और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रतियां खो गई हैं या अस्थानस्थ हो गई हैं और निदेश देता हूं कि उक्त वास्तविक उपयोक्ता फर्म को एक अनुलिपि लाइसेंस दोनों (सीमाशुल्क प्रयोजन और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रतियां) जारी किया जाये। उक्त लाइसेंस की मूल सीमाशुल्क और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रतियां एतद्द्वारा रद्द की जाती हैं।

[सं०ए०यू० 79537/51/ए०एम०-74/3/132]

के०पी० नारायण, उप मुख्य नियंत्रक,

कृते संयुक्त मुख्य नियंत्रक

OFFICE OF THE JT. CHIEF CONTROLLER OF IMPORTS AND EXPORTS

ORDER

Calcutta, the 16th August, 1975

S.O. 4956.—The State Trading Corporation of India Ltd., Chandralok, 36, Janpath, New Delhi were granted Import licence G/T/1774961/C/XX/50/C/37-38 dated 28-2-1974 with L/A to the Acual User firm M/s. Dhanwantari Chikitsalaya, 23A, Kalakar St. Calcutta for import of Gum Arabic for Rs. 21970. The firm have applied for duplicate copy of licence on the ground that the original licence (both Customs purpose & Exchange Control copy) has been lost or misplaced before utilisation and without having been registered with any Customs Authorities by the above Actual User firm to whom the original licence was sent by the S.T.C. New Delhi.

In support of their contention the applicant have filed an affidavit sworn in before the Metropolitan Magistrate, Sixteenth Court, Calcutta to the effect that the licence has not been utilised at all and that the same has not been cancelled, pledged, transferred or handed over by them or on their behalf to any other party for any purpose/consideration whatsoever.

The applicant have made a request to cancel the original Customs purpose and Exchange Control copies of the licence in lieu of which duplicate copies have been applied for by them and undertake to return the original Customs and Exchange Control copies of the licence to issuing authority, if traced out later on S.T.C. New Delhi has also intimated their 'No objection' in this regard. I am satisfied that the Original Customs purpose and Exchange Control copies of the licence No. G/T/1774061/C/XX/50/C/37-38 dated 28-2-74 have been lost or misplaced and direct that a duplicate licence (both Customs Purpose & Exchange Control copies) be issued to the Applicant Actual User firm.

The original Customs and Exchange Control copies of the licence are hereby cancelled.

[No. AU/79537/51/AM 74/III/132]

K. N. KAPOOR, Dy. Chief Controller

उप मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय,

आदेश

हैदराबाद, 11 अक्तूबर, 1975

का० आ० 4957.—सर्वश्री बैसीकैम इन्डस्ट्रीज, 1-4-445, मुशीराबाद, कावेदीगुडा रोड, सिकन्दराबाद को 1,45,658 रुपये का एक आयात लाइसेंस सं० पी०/एस०/1744347/सी०/एक्स० एक्स/50/ क्यू०/37-38 दिनांक 30-3-74 जो कि अंकित मूल्य के और 50% तक के लिये भी वैध है, स्वीकृत किया गया था। उन्होंने उक्त लाइसेंस की अनुलिपि मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति के लिये इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल प्रति 1,94,529 रु० के लिये उपयोग करने के बाद खो गई/अस्थानस्थ हो गई है

2. अपने तर्क के समर्थन में आवेदक ने आयात व्यापार नियंत्रक निगम एवं क्रियाविधि हैंडबुक 1975-76 की कंडिका 320(2) जिसे परिशिष्ट 8 के साथ पढ़ा जाये के अन्तर्गत अपेक्षित स्टाम्प कागज पर एक शपथ पत्र दाखिल किया है। मैं संतुष्ट हूं कि मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति खो गई/अस्थानस्थ हो गई है।

3. यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955, दिनांक 7-12-1955 की धारा 9(सी० सी०) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर मैं लाइसेंस सं० पी०एस०/1744347/सी०/एक्स०एक्स/50/

डब्ल्यू०/37-38 दिनांक 30-3-74 की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति को रद्द करने का आदेश देता हूं ।

4. आवेदक को अब उक्त लाइसेंस की अनुलिपि मुद्रा विनिमय लाइसेंस नियंत्रण प्रयोजन प्रति जारी करने के मामले पर आयात व्यापार नियंत्रण निगम एवं क्रियाविधि हैंडबुक 1975-76 की कंडिका 320 के अनुसार विचार किया जायेगा ।

[सं० बी-98/एस०एस०आई०/डी०/32/ए०एम/74/हैद०]
के० एम० आर० मेनन, उप-मुख्य नियंत्रक

OFFICE OF THE DY. CONTROLLER OF IMPORT AND

CANCELLATION ORDER

Hyderabad, the 1st October, 1975

S.O. 4957.—M/s. Basichem Industries. 1-4-445, Musheerabad, Kavadiguda Road, Secunderabad-3 were granted licence No. P/S/1744347/C/XX/50/W/37-38 dated 30-3-74 for Rs. 1,45,658 which is also valid for further 50 per cent of the face value. They have now supplied for issue of 'duplicate copy of the Exchange Control purposes copy' the above licence on the ground that the original copy has been lost/misplaced having been utilised to the extent of Rs. 1,94,529.

(2) The applicant has filed an affidavit on stamped paper in support of their contention as required under 320(2) read with Appendix 8 of Import Trade Control Hand Book of Rules & Procedure, 1975-76. I am satisfied that the original Exchange Control purposes copy has been lost/misplaced.

(3) In exercise of the powers conferred on me under Clause 9(cc) of Import (Control) Order 1955, dated 7-12-1955 as amended upto date, I order the cancellation of the Exchange Control Purposes copy of Licence No P/S/1744347/C/XX/50/W/37-38 dated 30-3-1974.

(4) The applicant's case will now be considered for the issue of duplicate Excange Control purposes copy of the above licence in accordance with para 320 of Import Trade Control Hand Book of Rules and Procedure, 1975-76.

[File No. B-98/SSI/D-32/AM-74/Hyd]
K.M.R. MENON, Dy. Chief Controller

संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात का कार्यालय, (केन्द्रीय लाइसेंस क्षेत्र)

आदेश

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 1975

का० आ० 4958.—सर्वश्री मोहम्मद मोहिद्दीन पी० बाक्स संख्या 172, दुकान संख्या 11, नई मार्केट मार्गाव, गोआ को 3438 रुपये मूल्य का लाइसेंस संख्या पी०/ई०/1811916, दिनांक 27-11-74 स्वीकृत किया गया था जिसकी वैधता सार्वजनिक सूचना संख्या 149/74 दिनांक 4 10-74 के अन्तर्गत 31-12-74 तक की थी। उन्होंने इस संबंध में एक शपथ पत्र दाखिल किया है कि उक्त लाइसेंस की दोनों मूल प्रतियां किसी भी सीमाशुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत कराये बिना ही और उनका बिल्कुल उपयोग किये बिना ही खो गई/अस्थानस्थ हो गई हैं ।

अद्यतन यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक 7-12-1955 की धारा 9(सी०सी०) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर मैं एतद्द्वारा लाइसेंस संख्या पी०ई०/181/1916, दिनांक 27-11-74, मूल्य 3438 रुपये (तीन हजार चार सौ अड़तीस रुपये) माल) की सीमाशुल्क एवं मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रतियों को रद्द करने का आदेश देता हूं ।

[संख्या 21(बी०)4/33 /इराक/74-75/पी०एन०1 49/74/आई० एस० डब्ल्यू० ए०/सी०एल०ए०]
के० एन० कपूर, उप-मुख्य नियंत्रक,
कृते संयुक्त मुख्य नियंत्रक

OFFICE OF THE JT. CHIEF CONTROLLER OF IMPORTS AND EXPORTS

CANCELLATION ORDER

New Delhi, the 11th July, 1975

S.O. 4958.—M/s. Mohamed Mohidin P. Box No. 172 Shop No. 11, New Market, Margao Goa were granted an import licence N. P/E/1811916 dated 27-11-1974 for Rs. 3438 with a validity period upto 31-12-1974 under Punblic Notice No. 149/74 dated 4-10-74. They have given an affidavit to the effect that the both copies of the above said licence has been lost/misplaced without having been registered with any custom authorities and without having been utilised at all.

In exercise of the powers conferred on me under clause 9(cc) of Imoprt (Control) Order, 1955 dated 7-12-1955 as amended upto-date, I do hereby order the cancellation of the Customs & Exchange Control Purposes copies of licence No. P/E/1811916 dated 27-11-1974 value of Rs. 3438 (Rs. There Thousand four hundred and thirty eight only).

[File No. 21 (b) IV/333/Iraq/74-75/P. N. 149/74/ISWA/CLA]
K. N. KAPOOR, Dy. Chief Controller,
for Jt. Chief Controller

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(नागरिक पूर्ति और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 17 अक्तूबर, 1975

का० आ० 4959.—केन्द्रीय सरकार, बहु एकक सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1942 (1942 का 6) की धारा 5ब द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के भूतपूर्व कृषि मंत्रालय (सहकारिता विभाग) की अधिसूचना संख्या एल०-11011/2/70-पी०एंड सी० तारीख 8 नवम्बर, 1973 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम सं० 9 के सामने की प्रविष्टियों में, स्तम्भ (2) में, मद (ii) के पश्चात् निम्नलिखित मद अन्त:स्थापित की जायेगी, अर्थात् :—

"(iii) हथकरघा, बिजलीकरघा और सहकारी टैक्सटाइल मिलों का निदेशक और पदेन सहकारी सोसायटियों का अपर रजिस्ट्रार महाराष्ट्र राज्य, नागपुर ।"

[संख्या एल०-11011/2/70-विधि तथा प्रबन्ध]
ना०कृष्णामूर्ति, उप सचिव,

MINISTRY OF INDUSTRY & CVIL SUPPLIES

(Department of Civil Supplies and Cooperation)

New Delhi, the 17th October, 1975

S.O. 4959.—In exercise of the powers confered by Section 5-B of the Multi-Unit Cooperative Societies Act, 1942 (6 of 1942) the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Agriculture (Development of Cooperation)

No. L. 11011/2/70-P&C dated the 8th November, 1973, namely :—

In the table to the said notification, in the entries against S. No. 9, in column (2), after item (ii), the following item shall be inserted, namely :—

"(iii) Director of Handlooms, Powerlooms and Cooperative Textiles and ex-officio Additional Registrar of Cooperative Societies Maharashtra State, Nagpur."

[No. L. 11011/2/70-I.&M]
N. KRISHNAMURTHI, Dy. Secy.

(भारी उद्योग विभाग)

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 1975

का० आ० 4960.—सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में वर्णित अधिकारी को जो सरकार के राजपत्रित अधिकारी की पंक्ति के समतुल्य अधिकारी है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती है, जो उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सरकारी स्थानों के प्रवर्गों की बाबत उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सम्पदा अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेगा ।

सारणी

अधिकारी का पदाभिधान	सरकारी स्थानों के प्रवर्ग और अधिकारिता की स्थानीय सीमायें
1	2
मुख्य सुरक्षा अधिकारी, स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, लखनऊ ।	लखनऊ जिला की लखनऊ तहसील के बिजनौर परगना में गाहर और गोरी ग्रामों में स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड के, या उसके द्वारा या उसकी ओर से पट्टे के रूप में लिये गये परिसर।

[फा०सं० 16(42)/75-ए०ई०आई० II]
एम०एम० घोष, संयुक्त सचिव,

(Department of Heavy Industry)

New Delhi, the 10th November, 1975

S. O. 4960.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints the officer mentioned in column (1) of the Table below, being an officer equivalent to the rank of a Gazetted Officer of Government, to be an Estate Officer, for the purposes of the said Act who shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on Estate Officers by or under the said Act in respect of the categories of public premises specified in column (2) of the said Table.

TABLE

Designation of the Officer	Categories of public premises and local limits of jurisdiction
(1)	(2)
Chief Security Officer, Scooters India Ltd., Lucknow.	Promises belonging to, or taken as lease by or on behalf of the Scooters India Ltd., Lucknow in Gahroo and Gauri Villages in Bijnore pargana of Lucknow Tehsil of Lucknow District.

[F. No. 16(42)/75-AEI(I)]
S.M. GHOSH Jt. Secy.

इस्पात और खान मंत्रालय

(इस्पात विभाग)

नई दिल्ली, 17 अक्तूबर, 1975

का० आ० 4961.—भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19) की धारा 8 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची में लौह अयस्क बोर्ड का नाम सार्वजनिक संस्था के रूप में जोड़ती है ।

[सं० 17(8)/73-आई०ओ०एम०]

MINISTRY OF STEEL & MINES

(Department of Steel)

New Delhi, the 17th October, 1975

S.O. 4961.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 8 of the Provident Funds Act, 1925 (19 of 1925), the Central Government hereby adds the name of the Iron Ore Board, as public institution, to the Schedule to the said Act.

[No. 17(8)/73 IOM]

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 1975

का० आ० 4962.—भविष्य निधि अधिनियम, 1935 (1925 का 19) की धारा 8 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि उक्त अधिनियम के उपबन्ध लौह अयस्क बोर्ड के पेंशन प्राप्त न करने वाले कर्मचारियों के लाभ के लिये बनाई गई अंशदायी भविष्य निधि पर भी लागू होंगे।

[सं० 17(8)/73-आई०ओ०एम०]
एम० एम० हुसैन, अवर सचिव

New Delhi, the 27th October, 1975

S.O. 4962.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 8 of the Provident Funds Act, 1925 (19 of 1925), the Central Government hereby directs that the provisions of the said Act shall apply to the Contributory Provident Fund established for the benefit of non-pensionable employees of the Iron Ore Board.

[No. 17(8)/73-IOM]
M. M. HUSSAIN, Under Secy.

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 1975

का० आ० 4963.—पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 5 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अन्तर्गत, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा मद्रास निगम के चिकित्सा अधिकारी डा० वी० वेंकटनारायण को उनके सामने दी गई तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिये पशु कल्याण मंडल का सदस्य मनोनीत करती है ।

सदस्य	तारीख	श्रेणी
1. डा० वेंकटनारायण	24-9-75	धारा 5(I)(ई) मद्रास निगम के प्रतिनिधि ।

[सं० 14-27/73-एल०डी०-I]
गुरबचन मोहन, अवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION

(Department of Agriculture)

New Delhi, the 4th November, 1975

S.O. 4963.—Under provisions of Sub-section (1) of Section 5 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960, the Central Govt. hereby nominates Dr. V. Venkatanarayana, Veterinary Officer, Corporation of Madras, to be members of the Animal Welfare Board for a period of three years from the date mentioned against him :—

Member	Date	Category
1. Dr. V. Verkatanaryana	24-9-75	Section 5(1)(c)— Representative of the Corporation of Madras.

[No. 14-27/73-LDI]
GURDIAL MOHAN, Under Secy.

कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 1975

का० आ० 4964.—कृषि उत्पाद उपकर अधिनियम 1940 की धारा 7 की उपधारा (2) के अनुसार केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा बनायी गयी स्थायी वित्त समिति की विनियमावली में निम्नलिखित संशोधन सामान्य सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

उक्त विनियमावली में विनियम 2 (iii) के स्थान पर निम्नलिखित विनियम होगा :

"2. (iii) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के शासी निकाय का वित्त सदस्य ।"

[सं० 24 (2)/75-समन्वय I (डेयर)]

(Department of Agricultural Research and Education)

New Delhi, the 6th November, 1975

S.O. 4964.—The following amendment to the Standing Finance Committee Regulations, 1940, made by the Indian Council of Agricultural Research, with the previous approval of the Central Government in pursuance of sub-section (2) of Section 7 of the Agricultural Produce Cess Act, 1940 are published for general information namely :—

In the said Regulations, for Regulation 2(iii), the following regulation shall be substituted, namely :—

"2. (iii) Member-Finance of the Indian Council of Agricultural Research Governing Body."

[No. 24(2)/75-Cdn-I(DARE)]

का० आ० 4965.—कृषि उत्पाद उपकर अधिनियम की धारा 7(2) में निहित व्यवस्था के अनुसार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा बनायी गयी स्थायी वित्त समिति की विनियमावली के विनियम 2 (IV) के अनुसरण में परिषद् के शासी निकाय द्वारा निकाय के निम्नलिखित सदस्यों को दिनांक 18 अगस्त, 1975 से एक वर्ष की अवधि के लिये अथवा जब तक उनके उत्तराधिकारियों का निकाय द्वारा विधिवत् निर्वाचन न हो तब तक के लिये इन दोनों में से जो भी बाद में हो, परिषद् की स्थायी वित्त समिति का सदस्य निर्वाचित किया गया है।

1. श्री डी० डी० देसाई, लोक सभा सदस्य, 24 सईद अब्दुल्ला ब्रेलवी रोड, फोर्ट, बम्बई-(400001)
2. श्री भानु प्रताप सिंह, सचिव, सरदार वल्लभ भाई महाविद्यालय, भावुआ, जिला रोहतास, बिहार।
3. प्रोफैसर एल० एन० मंडल, डीन, फैकल्टी आफ एग्रीकल्चर, विधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, कल्याणी, पश्चिमी बंगाल।
4. डा० जी० रंगास्वामी, उप-कुलपति, तमिल नाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बतूर-3
5. डा० जी० एस० रंधावा, निदेशक भारतीय बागानी अनुसंधान संस्थान, 255, अपर पैलेस आरचर्डस, बंगलौर-(560006)
6. श्री शंकर दयाल सिंह, लोक सभा सदस्य, परिजात पब्लिकेशन्स डाक बंगलो रोड, पटना-1
7. श्री वी० एस० त्यागराज मुदलियार, 17/4 नंगम्बक्कम हाई रोड, मद्रास-(600034) तामिल नाडु

[सं० 35(1)/75-समन्वय-I (डेयर)]

एस० सी० दत्ता, उप-सचिव

S.O. 4965.—In pursuance of regulation 2(iv) of the Standing Finance Committee Regulations framed by the Indian Council of Agricultural Research in pursuance of provision contained in Section 7(2) of the A. P. Cess Act, 1940, the following members of the Governing Body of the Council have been elected by that Body to be members of the Standing Finance Committee of the Council for a period of one year with effect from he 18th August, 1975 or till such time as their successors are duly elected by that Body, whichever is later :—

1. Shri D. D. Desai, Member, Lok Sabha 24, Syed Abdullah Brelvi Road, Fort, Bombay-400001.
2. Shri Bhanu Pratap Singh, Secretary, Sardar Vallabhbhai College, Bhabua, Distt. Rohtas, Bihar.
3. Prof. L. N. Mandal, Dean, Faculty of Agriculture, Bidhan Chandra Krishi Vishwa Vidyalaya, Kalyani, West Bengal.
4. Dr. G. Rangaswami, Vice-Chancellor, Tamil Nadu Agricultural University, Coimbatore-3.
5. Dr. G. S. Randhawa, Director, Indian Institute of Horticultural Research, 255, Upper Palace Orchards, Bangalore-560006.
6. Shri Shankar Dayal Singh, Member, Lok Sabha, Parijat Publications, Dak Banglow Road, Patna-1.
7. Shri V. S. Tyagaraja Mudaliar, 17/4 Nungambakkam High Road, Madras,-600034.

[No. 35(1)/75-Cdn(I) (DARE)]
S. C. DUTTA, Dy. Secy.

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY PLANNING

(Department of Health)

New Delhi, the 30th September, 1975

CORRIGENDUM

S.O. 4966.—In partial modification of this Ministry's Order No. V. 11016/13/75-MPT dated the 4th July, 1975 the date 7th January, 1976 occuring against sub-para (1) of para 3 may be read as 1st July, 1976. Thus para 3(i) of the said order will hereinafter be read as :—

"(i) a further period ending on the 1st July, 1976".

[No. V. 11016/13/75-MPT]
V. K. AGNIHOTRI, Under Secy.

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय

(पैट्रोलियम विभाग)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 31 अक्तूबर, 1975

का० आ० 4967—पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय नई दिल्ली दिनांक 31 अक्तूबर, 1975 पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962

जिला : मेहसाना

गुजरात राज्य जिला मेहसाना सोभासन जी जी एस कम सी टी एफ से दूध सागर डायरी मेहसाना तक पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार के अर्जन के लिए पैट्रोलियम पाइपलाइन अधिनियम (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 के खंड 3(1) के अन्तर्गत जारी पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय पेट्रोलियम विभाग, नई दिल्ली की अधिसूचना सं० 12016/13/74-एल एण्ड एल दिनांक 7-11-74 तथा खंड 6(i) के अन्तर्गत जारी अधिसूचना सं० 12016/13/74-एल एण्ड एल दिनांक 28-4-1975 से संलग्न अनुसूची में :—

पढ़ें				के स्थान पर			
मेहसाना में सोभासन जी जी एस कम सी टी एफ से दूध सागर डायरी				जी जी एस सोभासन से दूध सागर डायरी			
गांव कूकास ब्लाक नं०	जिला मेहसाना क्षेत्र		तालुका मेहसाना	गांव कूकास ब्लाक नं०	जिला मेहसाना क्षेत्र		तालुका मेहसाना
	एच०	ए आर ई	सी ए आर ई		एच०	ए०आर०ई०	सी ए आर ई
295	0	08	55	295	0	05	25
296	0	04	20	296	0	09	45
302	0	09	00	302	0	03	15
301	0	11	25	301	0	12	45
303	0	03	75	303	0	19	35
303/पी	0	15	60				

[सं० 12016/13/74—एल० एण्ड एल०]

MINISTRY OF PETROLEUM & CHEMICALS

(Dept. of Petroleum)

ERRATUM

New Delhi, the 31st October, 1975

S.O. 4967.—Ministry of Petroleum & Chemicals, New Delhi, Dated 1975, Petrolcum Pipeline (Acquisition of Right Users in land) Act, 1962,

District - Mehsana.

In schedule appended to the Govt. Notification, Ministry of Petroleum & Chemicals Department of Petroleum, New Delhi, number 12016 13/74-L&L dated 7-11-74. issued U/S 3(1) and notification number 12016/13/74-L&L dated 28th April, 1975, issued under section 6(1) of Petroleum Pipeline Act, (Acquisition of Right of Users in land) Act, 1962, for the Acquisition of User for laying gas pipeline from Sobhasan G.G.S.-Cum-C.T.F. To Dudh sagar Dairy, at Mehsana in Gujarat State, District Mehsana.

READ	FOR
Sobhasan G.G.S.-Cum-C.T.F. To Dudhsagar Dairy at Mehsana.	G.G.S. Sobhasan to Dudhsagar Dairy.

Village KUKAS Block No.	District MEHSANA Area		Taluka MEHSANA	Village KUKAS Block No.	District MEHSANA Area		Taluks MEHSANA
	H.	Are.	C. Are.		H.	Are.	C. Are.
295	0	08	55	295	0	05	25
296	0	04	20	296	0	09	45
302	0	09	00	302	0	03	155
301	0	11	25	301	0	12	45
303	0	03	75	303	0	19	35
303/P	0	15	60				

[No. 12016/13/74-L & L]

का० आ० 4968.—यतः पैट्रोलियम, पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (पैट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० आ० सं० 1754 तारीख 20-5-1975 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी के उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और, आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी संवर्कों से मुक्त रूप में, इस घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

के० जी० ई० से जी० जी० एस० 8 तक की पाइपलाइन

राज्य: गुजरात जिला: मेहसाना तालुका: कालोल

गांव	सर्वेक्षण नं०	हैक्टेयर	ए० आर० ई०	सेन्टी ए० आर० ई०
1	2	3	4	5
कालोल	669/1	0	01	05
	669/2	0	06	45
	674	0	10	50
	675/5	0	04	50
	675/2	0	16	65
	726	0	24	00
	755	0	04	55
	721	0	16	50
	756	0	01	00
	760	0	10	20
	761	0	06	00
	763	0	05	10
	762	0	06	00
	764/3	0	07	50
	925	0	12	50
	921	0	17	85
	922/1	0	01	80
	919/3	0	09	60
	919/2	0	07	80
	919/1	0	01	05
	1043	0	04	80
	1044/1	0	10	50
	1049/2	0	07	50
	1049/1	0	04	05
	1048/2	0	01	00
	1048/1	0	14	85
	1056	0	24	15
	1055	0	12	15
	1055	0	14	70
	1065/2	0	07	80
	1065/1	0	07	50
	1066/2	0	00	50
	1072	0	13	50
	1071/3	0	01	65
	1071/4	0	05	55
	1071/2	0	07	80
	1071/1	0	09	00
	1070/3	0	01	00
	1117	0	03	60
	1118	0	08	40

[सं० 12016/2/75-एल० एंड एल०]

S.O. 4968.—Whereas by a notification of the Govt. of India in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Department of Petroleum) S.O. No. 1754 Dated 20-5-75 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipelines.

And whereas the Competent Authority has under sub section (1) of section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has alter considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now therefore in exercise of the Power conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines;

And further in exercise of the power conferred by sub-section (4) of that Section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from all encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from KCE to G.G.S. 8

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kalol

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Kalol	669/1	0	01	05
	669/2	0	06	45
	674	0	10	50
	675/5	0	04	50
	675/2	0	16	65
	726	0	24	00
	755	0	04	55
	721	0	16	50
	756	0	01	00
	760	0	10	20
	761	0	06	00
	763	0	05	10
	762	0	06	00
	764/3	0	07	50
	925	0	12	30
	921	0	17	85
	922/1	0	01	80
	919/3	0	09	60
	919/2	0	07	80
	919/1	0	01	05
	1043	0	04	80
	1044/1	0	10	50
	1049/2	0	07	50
	1049/1	0	04	05
	1048/2	0	01	00
	1048/1	0	14	85
	1056	0	24	15
	1055	0	12	15
	1055	0	14	70
	1065/2	0	07	80
	1065/1	0	07	50
	1066/2	0	00	50
	1072	0	13	50
	1071/3	0	01	65
	1071/4	0	05	55
	1071/2	0	07	80
	1071/1	0	09	00
	1070/3	0	01	00
	1117	0	03	60
	1118	0	08	40

[No. 12016/2/75-L&L]

का० आ० 4969.—यतः पैट्रोलियम, पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (पैट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० आ० सं० 1237 तारीख 31-3-1975 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी के उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, यतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और, आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी संधकों से मुक्त रूप में इस घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

जी० एस० के टी० एफ० से जी० जी० एस० तक पाइपलाइन बिछाने के लिये

राज्य: गुजरात जिला: केईरा तालुका बोरसाद

गांव	सर्वेक्षण नं.	हैक्टेयर	ए आर ई	सेण्टी ए आई
विवेल	65	0	02	85
	64	0	03	15
	69	0	01	40
	61	0	06	30
	62	0	05	60
	56	0	14	00
	57	0	00	35
	45	0	12	95
	कार्ट ट्रेक	0	00	70
	257	0	06	00
	कार्ट ट्रेक	0	01	80
	258	0	09	60
	268	0	18	00
	269	0	18	00
	270	0	03	60
	272	0	15	60
	271	0	00	60
	274	0	12	00
	275	0	13	20
	279	0	00	60
देहवान--	791	0	12	00
(देहवान)	594	0	06	60
	593	0	07	80
	592	0	03	60
	596	0	00	00
कापूरा--	595	0	00	60

[सं० ए 12016/5/75-एल० एंड एल०]

S.O. 4969.—Whereas by a notification of the Govt. of India in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Department of Petroleum) S.O. No. 1237 Dated 31-3-75 under sub-section (I) of section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipelines.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now therefore in exercise of the Power conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines;

And further in exercise of the power conferred by sub-section (4) of that Section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from all encumbrances.

SCHEDULE

For Laying Pipeline From D.S. KTF to G.G.S.

State : Gujarat District : Kaira Taluka : Borsad

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Divel	65	0	02	80
	64	0	03	15
	69	0	01	40
	61	0	06	30
	62	0	05	60
	56	0	14	00
	57	0	00	35
	45	0	12	95
	Cart-Track	0	00	70
	257	0	06	00
	Cart-Track	0	01	80
	258	0	09	60
	268	0	18	00
	269	0	18	00
	270	0	03	60
	272	0	15	60
	271	0	00	60
	274	0	12	00
	275	0	13	20
	279	0	00	60
Dehvan	791	0	12	00
	594	0	06	60
	593	0	07	80
	592	0	03	60
	596	0	15	00
Kankapura	595	0	00	60

[No. 12016/5/75-L&L]

शुद्धि पत्र

का० आ० 4970.--पेट्रोलियम पाइप लाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत गुजरात राज्य के जिला अहमदाबाद तालुका विरामगाम के लिये भारत के राजपत्र के भाग-II खंड 3(ii) के पृष्ठ संख्या 3071 से 3072 तक दिनांक 16-8-75 को प्रकाशित का० आ० संख्या 2677 के द्वारा भारत सरकार, पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 12017/1/75 एल एंड एल दिनांक 28-7-75 के साथ संलग्न अनुसूची के स्थान पर अब से इसके साथ संलग्न अनुसूची को पढ़ें।

अनुसूची

तालुका: विरामगाम जिला : अहमदाबाद गुजरात राज्य

के स्थान पर		पढ़ें	
क्रमांक	तक	क्रमांक	तक
	एच० ए० वर्गमील		एच० ए० वर्गमील
76	0-42-1	676	0-42-10

के स्थान पर	पढ़ें
—	हंसलपुर सुरेशवर

[सं० 12017/1/75-एल० एंड एल०]

ERRATUM

S.O. 4970.—In the schedule appended to the notification of the Government of India Ministry of Petroleum & Chemicals No. 12017/1/75-L&L dt. 28-7-75 published vide S.O. No. 2677 dated 16-8-75 from page No. 3071 to 3072 of the Gazette of India Part II Section 3(ii) for Taluka Viramgam, Dist. Ahmedabad, Gujarat State, under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of right of user in land) Act, 1962 (50 of 1962) read as per the schedule annexed hereto.

SCHEDULE

Taluka : Viramgam Dist. : Ahmedabad Gujarat State

For		Read	
S.No.	Extent	S.No.	Extent
	H.A. Sq. M.		H.A. Sq. M.
76	0-42-01	676	0-42-10

For	Read
—	Hansalpur Sureshver

[No. 12017/1/75-L&L]

शुद्धि-पत्र

का० आ० 4971.--पेट्रोलियम पाइप लाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत गुजरात राज्य के जिला अहमदाबाद तालुका सनन्द के लिये भारत के राजपत्र के भाग-II खंड 3 (ii) के पृष्ठ संख्या 3064 से 3071 तक दिनांक 16-8-1975 को प्रकाशित का० आ० संख्या 2676 के द्वारा भारत सरकार, पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 12017/2/75-एल एंड एल दिनांक 25-7-75 के साथ संलग्न अनुसूची के स्थान पर अब से इसके साथ संलग्न अनुसूची को पढ़ें।

अनुसूची

तालुका: सनन्द जिला: अहमदाबाद गुजरात राज्य

के स्थान पर	पढ़ें
सनथल	सनाथल

गांव : नावापुर तालुका : सनन्द जिला : अहमदाबाद गुजरात राज्य

के स्थान पर		पढ़ें	
क्रमांक	तक	क्रमांक	तक
	एच० ए० वर्गमील		ए० ए० वर्गमील
74	0-14-45	74	0-14-56
71	0-00-62	71	0-10-62

गांव : सनन्द	तालुका : सनन्द	जिला : अहमदाबाद	गुजरात राज्य
1283/3	0-25-00	1283/1	0-25-00
1701	0-00-54	1701	0-00-45
208/2	0-10-05	2080/2	0-10-05

गांव: खोराज	तालुका: सनन्द	जिला: अहमदाबाद	गुजरात राज्य
593	0-32-00	593	0-32-00

[सं० 12017/2/75-एल० एंड एल०]

ERRATUM

S.O. 4971.—In the schedule appended to the notification of the Government of India, Ministry of Petroleum & Chemicals No. 12017/2/75-L&L dt. 25-7-75 published vide S.O. No. 2676 dated 16-8-75 from page No. 3064 to 3071 of the Gazette of India Part II Section 3(ii) for Taluka Sanand Dist. Ahmedabad, Gujarat State, under sub-section (1) of Section 6 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of user in land) Act, 1962 (50 of 1962) read as per the schedule annexed hereto.

SCHEDULE

Taluka : Sanand	Dist : Ahmedabad	Gujarat State
For	Read	
Santhal	Sanathal	

Village : Navapura	Ta : Sanand	Dist : Ahmedabad	Gujarat State
For		Read	
S.No.	Extent	S.No.	Extent
	H.A. Sq. M.		H.A. Sq. M.
74	0–14–45	74	0–14–56
71	0–00–62	71	0–10–62

Village : Sanand	Ta : Sanand	Dist. : Ahmedabad	Gujarat State
1283/3	0–25–00	1283/1	0–25–00
1701	0–00–54	1701	0–00–45
208/2	0–10–05	2080/2	0–10–05

Village : Khoraj	Ta : Sanand	Dist. : Ahmedabad	Gujarat State
593	0–32–00	593	0–32–20

[No.-12017/ 2/75-L&L

शुद्धि पत्र

का०आ० 4972.—पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (पैट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना संख्या (12019/2/74–एल एण्ड एल/1) दिनांक 23–12–75 के अन्तर्गत भारत के राजपत्र भाग II खण्ड 3 उपखंड ii दिनांक 4–1–75 के पृष्ठ संख्या 52 से 61 तक।

गांव सतसई	ग्रांट	तालुका	अठखेल	जिला सिबसागर
	पढ़ें		के स्थान पर	

सर्वेक्षण सं०	हेक्टेयर	ए.आर.ई.पी	ए.आर.ई.	सर्वेक्षण सं०	हेक्टेयर	ए.आर.ई. पी०	ए.आर.ई.
28	0	2	81	24 क	0	2	81
63 ख	0	2	01	48 ख	0	2	01
64 ख	0	15	52	48 ङ	0	15	52

[सं० 12019/2/74—एल० एण्ड एल०/1]

ERRATUM

S.O.4972.—In the Notification of Government of India in the Ministry of Petroleum & Chemicals (Department of PetroleumNo. (12019/2/74-L &L/I) dated 23-12-74 under S.O. No. 29 in the Gazette of India, Part II, Section 3. Sub-Section (ii) dated 4-1-75 page No. 52 to 61.

VILLAGE : SATSAI GRANT, TALUKA : ATHKHEL, DISTRICT : SIBSAGAR

READ				FOR			
Survey No.	Hectare	Are	P. Are.	Survey No.	Hectare	Are. P.	Are.
28	0	2	81	24 Kha	0	2	81
63 Kha	0	2	01	48 Kha	0	2	01
64 Kha	0	15	52	48 Unga	0	15	52

[No. 12019/2/74-L &L]/I]

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 1975

का० आ० 4973 :--यतः पेट्रोलियम, पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० आ० सं० 119 तारीख 26-12-74 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी के उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना के संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और, आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी संघकों से मुक्त रूप में इस घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

लाकवा कूप नं० 41 से लाकवा जी ओ एस० न० 1 तक पाइपलाइन

राज्य : असम जिला : सिबसागर तालुका : सिलाकउटी

गांव	सर्वेक्षण सं०	हैक्टेयर	ए० आर० ई०	सेन्टी ए आर०ई
लक्वा चान बगिचा और वेलो गूरी	82/खा	0	0	13
	83/खा	0	5	22
	83/ग	0	0	67
	84/खा	0	0	13
	84/घा	0	0	27
	85/खा	0	2	27
	101/खा	0	1	20

[सं० 12016/8/74-एल० एंड एल०/1]

New Delhi, the 4th November, 1975

S.O. 4973.—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Department of Petroleum) S.O. No. 119 dated 26-12-75 under subsection (1) of Section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acqiure the Right of User in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipelines;

And whereas the competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore in exercise of the power conferred by subsection (1) of the section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines;

And further in exercise of the power conferred by subsection (4) of that Section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest in this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from all encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Lakwa well No. 41 to Lakwa GGS No. 1

State :Assam District : Sibsagar, Taluk : Silakuti

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Lakwa Chah Bagicha and Veloguri Dubi	82 Kha	0	0	13
	83 Kha	0	5	22
	83 Unga	0	0	67
	84 Kha	0	0	13
	84 Gha	0	0	72
	85 Kha	0	2	27
	101 Kha	0	1	20

[No. 12016/8/74-L&L/I]

का० आ० 4974 :--यतः पेट्रोलियम, पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० आ० सं० 120 तारीख 26-12-74 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी के उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और, आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी संघकों से मुक्त रूप में इस घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

गेलेकी कूप नं० जी० ओ० (10) से कूप नं० जी एल० (9) तक पाइप-लाइन

राज्य: असम जिला: सिबसागर तालुका: अथखेल

गांव	सर्वेक्षण नं०	हैक्टेयर	ए० आर० ई०	सेण्टी ए० आर० ई०
छुटिया गांव	339खा	0	8	03
	340 खा	0	12	71
	501 खा	0	11	77
	514खा	0	1	74
	513 खा	0	17	13
	1032 खा	0	24	22
	815 खा	0	17	66
	847 खा	0	1	07

[सं० 12016/8/74-एल० एंड एल०/II]

S.O. 4974.—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Department of Petroleum) S.O. No. 120 dated 26-12-74 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipelines;

And whereas the competent Authority has under sub-secion (1) of section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now therefore in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the righ of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines;

And further in exercise of the power conferred by sub-section (4) of that Section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest in this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from all encumbrances.

SCHEDULE

Pipe Line from Geleki Well No. GO(10) To Well No. GL(9)

State : Assam District : Sibsagar Taluk : Athkhel

Village	Survey No.	Hectare	Ares	Centiares
Chutia Gaon	339 Kha	0	8	03
	340 Kha	0	12	71
	501 Kha	0	11	77
	514 Kha	0	1	74
	513 Kha	0	17	13
	1032 Kha	0	24	22
	815 Kha	0	17	66
	847 Kha	0	1	07

[No. 12016/8/74-L&L/II]

का० आ० 4975 :—यतः पेट्रोलियम, पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० आ० सं० 30 दिनांक 23-12-74 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी के उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार के उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्-द्वारा अर्जित किया जाता है।

और, आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी संघर्षों से मुक्त रूप में इस घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

गेलेकी कूप नं० जी० एल० से गेलेकी कूप सं० 1 तक की पाइपलाइन

राज्य: असम जिला: सिबसागर तालुका : अथखेल

गांव	सर्वेक्षण नं०	हैक्टेयर	ए० आर० ई०	सेण्टी-एर
अथखेल ग्रांट नं० 2	26 ख	0	14	45

[सं० 12019/2/74-एल० एण्ड एल०]

S.O. 4975.—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Department of Petroleum) S.O. No. 30 dated 23-12-74 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipelines;

And whereas the competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the scheduled appended to this notification;

Now therefore in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines;

And further in exercise of the power conferred by sub-section (4) of that Section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest in this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from all encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Geleki GGS No. 3 to Geleki Well No. 1

State : Assam District : Sibsagar Taluk : Atkhkhel

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Athkhel Grant No. 2	26 Kha	0	14	45

[No. 12019/2/74-L&L/II]

का० आ० 4976.—यतः पैट्रोलियम, पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० आ० सं० 31 तारीख 23-12-74 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी के उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा(1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्-द्वारा अर्जित किया जाता है।

और, आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी संघकों से मुक्त रूप में इस घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

गेलेकी कूप नं० जी एल० से गेलेकी कूप नं० 1 तक की पाइपलाइन

राज्य : असम जिला : सिबसागर तालुका : अथखेल

गांव	सर्वेक्षण नं०	हैक्टेयर	ऐ० आर० सैण्टी-ईं०	एर
छुटिया गांव	1041 ख	0	0	27
	1033 ख	0	11	37
	938 ख	0	12	58
	937 ख	0	13	38
	935 ख	0	19	40
	914 ख	0	26	49
	913 ख	0	2	54
	881 ख	0	0	54
	849 ख	0	10	70
	851 ख	0	10	57
	1026 ख	0	1	20
	847	0	1	34

[सं० 12019/2/74-एल० एण्ड एल० 3]

S.O. 4976.—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Department of Petroleum) S.O. No. 31 dated 23-12-74 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipelines;

And whereas the competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the scheduled appended to this notification;

Now therefore in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines;

And further in exercise of the power conferred by sub-section (4) of that Section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest in this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from all encumbrances.

SCHEDULE

Pipe Line from Geleki Well No. GL to Geleki Well No. 1

State : Assam District : Sibsagar Taluk : Athkhel

Village	Survey No.	Hectare	Area	Centiare
Chutia Gaon	1041 Kha	0	0	27
	1033 Kha	0	11	37
	938 Kha	0	12	58
	937 Kha	0	13	38
	935 Kha	0	19	40
	914 Kha	0	26	49
	913 Kha	0	2	54
	881 Kha	0	0	54
	949 Kha	0	10	70
	851 Kha	0	10	57
	1026 Kha	0	1	20
	847 Kha	0	1	34

[No. 12019/2/74-L & L/III]

का० आ० 4977.—यतः पेट्रोलियम, पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० आ० सं० 32 तारीख 23-12-74 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी के उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और, आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी संघकों से मुक्त रूप में इस घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

गेलेकी जी० जी० एस० नं० 3 से गेलेकी कूप नं० 1 तक की पाइपलाइन

राज्य	असम	जिला : सिब-सागर		तालुका अथखेल
गाँव	सर्वेक्षण	हेक्टेयर	ऐ आर ई	सेण्टी-एर
नापाम बारुवती	2135 ख	0	7	09
	2144 ख	0	18	06
	2143 ख	0	22	34
	2143 ख	0	1	61
	1604 ख	0	6	15
	2142 ख	0	10	57
	2024 ख	0	8	03
	2147 ख	0	1	61

[सं० 12019/2/74-एल एण्ड एल/4]

S.O. 4977.—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Department of Petroleum) S.O. No. 32 dated 23-12-74 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipelines;

And whereas the competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the scheduled appended to this notification;

Now therefore in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines;

And further in exercise of the power conferred by sub-section (4) of that Section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest in this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from all encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Geleki GGS No. 3 to Geleki Well No. 1.

State : Assam District : Sibsagar Taluk : Athkhel

Village	Survey No.	Hectare	Area	Centiare
Napam Baruwati	2135 Kha	0	7	09
	2144 Kha	0	18	06
	2143 Kha	0	22	34
	2143 Kha	0	1	61
	1604 Kha	0	6	15
	2142 Kha	0	10	57
	2024 Kha	0	8	03
	2147 Kha	0	1	61

[No. 12019/2/74-L&L/IV]

का० आ० 4978. —यतः पेट्रोलियम, पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० आ० सं० 33 तारीख 23-12-74 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी के उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और, आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा—प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और, आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी संघकों से मुक्त रूप में इस घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

गेलेकी जी० जी० एस० नं० 3 से गेले की कूप नं० 1 तक की पाइपलाइन

राज्य	असम	जिला : सिब-सागर		तालुका : अथखेल
गाँव	सर्वेक्षण	हेक्टेएर	एआर ई	सेण्टीएर
अथखेल ग्रांट नं० 2	1 ख	1	9	16
	15 ख	0	35	86
	15 ङ	0	5	35

[सं० 12019/2/74-एल० एण्ड० एल 5]

S.O. 4978.—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Department of Petroleum) S.O. No. 33 dated 23-12-74 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipelines;

And whereas the competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now therefore in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines;

And further in exercise of the power conferred by sub-section (4) of that Section, the Central Government directs

that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest in this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from all encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Geleki GGS No. 3 to Geleki Well No. 1

State : Assam District : Sibsagar Taluk : Athkhel

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Athkhel Grant No. 2	1 Kha	1	9	16
	15 Kha	0	35	86
	15 Unga	0	5	35

[No. 12019/2/74-L&L/V]

का० आ० 4979.—यतः पेट्रोलियम, पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (पैट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० आ० सं० 34 तारीख 23-12-74 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और, आगे इस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी संघकों से मुक्त रूप में इस घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

गेलेकी कूप नं० जी० एल० से गेलेकी कूप नं० 1 तक पाइपलाइन बिछाने के लिये ।

राज्य : असम जिला : सिबसागर तालुका : अथखेल

गाँव	सर्वेक्षण	हेक्टेएर	ऐ आर	सेण्टीएर ई
गेलेकी ग्रांट नं 1	4 ख	0	5	62
	3 ख	0	0	94
	2 ख	0	1	61
	77 ख	0	21	81

[सं० 12019/2/74-एल० एण्ड० एल/6]

S.O. 4979.—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Department of Petroleum) S.O. No. 34 dated 23-12-74 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipelines :

And whereas the competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further, whereas the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the Schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines ;

And further in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of that Section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest in this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from all encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Geleki Well No. G1 to Geleki Well No. 1

State : Assam District : Sibsagar Taluka : Athkhel

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Gelki Grant No. 1	4 Kha	0	5	62
	3 Kha	0	0	94
	2 Kha	0	1	61
	77 Kha	0	21	81

[No. 12019/2/74-L&L/VI]

का० आ० 4980.—यतः पैट्रोलियम, पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन), अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (पैट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० आ० सं० 35 तारीख 23-12-74 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और, आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी संघकों से मुक्त रूप में इस घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

गेलेकी ग्रुप गैदरिंग स्टेशन नं० 3 से गेलेकी कूप नं० 1 तक पाइप-लाइन बिछाने के लिये ।

राज्य : असम	जिला : सिबसागर		तालुका : अथखेल	
गाँव	सर्वेक्षण नं०	हैक्टेएर	ऐ आर ई	सेण्टीएर
अथखेल ग्रांट नं० 1	21 ख	0	5	08

[सं० 12019/2/74-एल० एण्ड एल०/7]

S.O. 4980.—Where by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Department of Petroluem) S.O. No. 35 dated 23-12-74 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipelines;

And whereas the competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the Schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines ;

And further, in exercise of the power conferred by sub-section (4) of that Section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest in this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from all encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Geleki Group Gathering Station No. 3 to Geleki Well No. 1

State : Assam	District : Sibsagar		Taluka : Athkhel	
Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Athkhel Grant No. 1	21 Kha	0	5	08

[PN. 12019/2/74- L&L/VII]

का० आ० 4981.— यतः पैट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन), अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० आ० सं० 36, तारीख 23-12-74 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा-- प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और, आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी संघर्षों से मुक्त रूप में इस घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

रूद्रासागर जी० जी० एस० नं० 1 से लक्वा जी० जी० एस० नं० 1 तक पाइप-लाइन बिछाने के लिये ।

राज्य : असम	जिला : सिबसागर		तालुका : सिलकुटा	
गाँव	सर्वेक्षण नं०	हैक्टेएर	ऐ आर ई	सैण्टीयर
सोला चाहु बगीचा	2 ख	0	35	05
	2 ग	0	19	53
	2 ङ	0	12	71
	2 स	0	35	99
	3 ख	0	20	47
	13 ग	0	0	94
	63 स	0	88	56
	63 ह	0	14	32

[सं० 12019/2/74-एल० एण्ड एल/8]

टी० पी० सुब्रह्मनियन, अवर सचिव

S.O. 4981.—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Department of Petroleum) S.O. No. 36, daated 23-12-74 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipelines ;

And whereas the competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further, whereas the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the Schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines ;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of that Section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest in this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from all encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Ruirasagar GGS No. 1 To Lakwa GGS No . 1

State : Assam District : Sibsagar Taluk : Silakati

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Sola Chah Bagicha	2 Kha	0	35	05
	2 Ga	0	19	53
	2 Unga	0	12	71
	2 Sa	0	35	99
	3 Kha	0	20	47
	13 Ga	0	0	94
	63 Sa	0	88	56
	63 Jha	0	14	32

[No. 12019/2/74-L&L/VIII]

T. P. SUBRAHAMANYAN Under Secy.

(उर्वरक और रसायन विभाग)

का० आ० 4982.—सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार नीचे की सारणी में वर्णित अधिकारी को, जो सरकार के राजपत्रित अधिकारी की पंक्ति के समतुल्य अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती है, जो उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सरकारी स्थानों की बाबत अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर, उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सम्पदा अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेगा ।

सारणी

अधिकारी का पदाभिधान	सरकारी स्थानों के प्रवर्ग और अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं
(1)	(2)
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, गोरखपुर, यूनिट, गोरखपुर, भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड ।	भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड के, गोरखपुर उर्वरक कारखाने के, जिसमें उसकी नगरी भी सम्मिलित है, सरकारी स्थान ।

[फा० सं० एम-27013(5)/75-एफ 2]

ए० ए० वासुदेवन, अवर सचिव

(Department of Fertilizers and Chemicals)

S.O. 4982.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of the 1971), the Central Government hereby appoints the officer mentioned in column (1) of the Table below, being an officer equivalent to the rank of Gazetted Officer of Government, to be Estate Officer for the purposes of the said Act, who shall exercise the powers conferred, and perform the duties imposed, on Estate Officers by or under the said Act within the local limits of his jurisdiction in respect of the public premises specified in column (2) of the said Table.

TABLE

Designation of the officer	Categories of public premises and local limits of jurisdiction
1	2
Senior Administrative Officer, Gorakhpur Unit, Gorakhpur Fertilizer Corporation of India Limited.	Public premises of Gorakhpur Fertilizer Factory including its township belonging to Fertilizer Corporation of India Limited.

[F. No. M-27013(5)/75-Ferts.II]

A. A. VASUDEVAN Under Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 24 अक्तूबर, 1975

का० आ० 4983.—इसके साथ लगी प्रथम अनुसूची में निर्धारित प्रत्येक अधिनियम के उपबन्ध के अन्तर्गत जारी किये गये निदेशों के अनुसार केन्द्रीय सरकार, फिल्म सलाहकार बोर्ड, बम्बई की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, एतद्द्वारा, इसके साथ लगी द्वितीय अनुसूची के कालम 2 में दी गई फिल्म को उसके सभी भाषाओं के रूपान्तरों सहित जिनका वितरण उसके सामने उक्त द्वितीय अनुसूची के कालम 6 में दिया हुआ है, स्वीकृत करती है ।

प्रथम अनुसूची

(1) चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37वां केन्द्रीय अधिनियम) की धारा 12 की उपधारा (4) तथा धारा 16 ।

(2) बम्बई सिनेमा (विनियम) अधिनियम 1953 (1953 का 11वां अधिनियम) की धारा 5 की उपधारा (3) तथा धारा 9 ।

द्वितीय अनुसूची

क्रम संख्या	फिल्म का नाम	फिल्म की लम्बाई 35 मी मी०	आवेदक का नाम	निर्माता का नाम	क्या वैज्ञानिक फिल्म है या शिक्षा संबंधी फिल्म है, या समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म है या डाकूमेंट्री फिल्म है
1	2	3	4	5	6
1.	महाराष्ट्र समाचार संख्या 285	289.00 मीटर	सूचना तथा जन-संपर्क निदेशक, अधिकारी, महाराष्ट्र सरकार, बम्बई ।		समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म (केवल महाराष्ट्र सर्किट में प्रदर्शन के लिए) ।
2.	महाराष्ट्र समाचार संख्या 286	293.00 मीटर	सूचना तथा जन-संपर्क निदेशक, अधिकारी, महाराष्ट्र सरकार, बम्बई ।		समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म (केवल महाराष्ट्र सर्किट में प्रदर्शन के लिए) ।

[फा० सं० 6/1/75-एफ० पी०-परिशिष्ट-2019]

MINISTRY OF INFORMATION & BROAD CASTING

ORDER

New Delhi the 24th October, 1975

S.O. 4983.—In pursuance of the directions issued under the provisions of the enactments specified in the First Schedule annexed hereto the Central Government after considering the recommendations of the Film Advisory Board, Bombay hereby approves the films specified in column 2 of the Second Schedule annexed hereto inall its/their language versions to be of the description specified against it/each in columns 6 of the said Second Schedule.

THE FIRST SCHEDULE

(1) Sub-section (4) of the Section 12 of section 16 of the Cinematograph Act, 1952 (Central Act XXXVII of 1952).

(2) Sub-section (3) of section 5 and section 9 of the Bombay Cinemas (Regulation) Act, 1953 (Bombay Act XI of 1953).

THE SECOND SCHEDULE

S.No.	Title of the film	Length 35 mm	Name of the applicant	Name of the Producer	Whether a scientific film or a film intended for educational purposes or a film dealing with news & current events or a documentary film
1	2	3	4	5	6
1.	Maharashtra News No. 285	289.00 Metres	The Director of Information & Public Relations, Government of Maharashtra, Bombay.		Film dealing with news and current events (for release in Maharashtra Circuit).
2.	Maharashtra News No. 286	293.00 Meters	Do.		Do.

[F. No. 6/1/75-F(P) App. 2019]

आदेश

का०आ० 4984.—इसके साथ लगी प्रथम अनुसूची में निर्धारित प्रत्येक अधिनियम के उपबन्ध के अन्तर्गत जारी किये गए निदेशों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार, फिल्म सलाहकार बोर्ड, बम्बई की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, एतद्द्वारा, इसके साथ लगी द्वितीय अनुसूची के कालम 2 में दी गई फिल्मों को उनके गुजराती भाषा रूपांतरों सहित, जिनका विवरण प्रत्येक के सामने उक्त द्वितीय अनुसूची के कालम 6 में दिया हुआ है, स्वीकृत करती है :—

प्रथम अनुसूची

(1) चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37वां केन्द्रीय अधिनियम) की धारा 12 की उपधारा (4) तथा धारा 16

(2) बम्बई सिनेमा (विनियम) अधिनियम 1953 (1953 का 17वां बम्बई अधिनियम) की धारा 5 की उपधारा (3) तथा धारा 9

द्वितीय अनुसूची

क्रम संख्या	फिल्म का नाम	फिल्म की लम्बाई 35 मि० मी०	आवेदक का नाम	निर्माता का नाम	क्या वैज्ञानिक फिल्म है या शिक्षा संबंधी फिल्म है या समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म है या डाकुमेंट्री फिल्म है।
1	2	3	4	5	6
1.	महिति चित्र सं० 207	274.32 मीटर	सूचना निदेशक, गुजरात सरकार, गांधी नगर।		समाचार और सामयिक घटनाओं से संबंधित फिल्म (केवल गुजरात सर्किट के लिए)।
2.	महिति चित्र संख्या 208	243.83 मीटर	सूचना निदेशक, गुजरात सरकार, गांधी नगर।		समाचार और सामयिक घटनाओं से संबंधित फिल्म (केवल गुजरात सर्किट के लिए)।

[फा० संख्या 6/1/75-एफ० पी० परिशिष्ट 2020]

के० पी० के० नायर, अवर सचिव

ORDER

S.O. 4984.—In pursuance of the directions issued under the provisions of each of the enactments specified in the First Schedule annexed hereto, the Central Government after considering the recommendations of the Film Advisory Board, Bombay hereby approves the film/films specified in column 2 of the Second Schedule annexed hereto in Gujarati to be of the description specified against it/each in column 6 of the said Second Schedule.

THE FIRST SCHEDULE

(1) Sub-section 4 of the Section 12 and Section 16 of the Cinematograph Act, 1952 (Central Act XXXVII of 1952).

(2) Sub-section (3) of Section 5 and Section 9 of the Bombay Cinemas (Regulation) Act, 1953 (Bombay Act XVII of 1953).

THE SECOND SCHEDULE

S.No.	Title of the film	Length 35 mm	Name of the Applicant	Name of the Producer	Whether a Scientific film or a film intended for eduducational pruposes or a film dealing with news & current events or a documentary film
1	2	3	4	5	6
1.	Mahitichitra No. 207	274.32 Metres		Director of Information Govt. of Gujarat, Gandhi Nagar.	Film dealing with news and current events (For release in Gujarat Circuit only).
2.	Mahitichitra No. 208	243.83 Metres		Do.	Do.

[F. No. 6/1/75-FP App. 2020]
K.P.K. NAYAR, Under Secy.

संचार मंत्रालय

(डाक-तार बोर्ड)

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 1975

का. आ. 4985.—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खंड 3 के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने शंकरन कोइल टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 1-12-75 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है ।

[संख्या 5-18/75-पी. एच. बी.]

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(P & T BOARD)

New Delhi, the 13th November, 1975

S.O. 4985.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S. O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs, hereby specifies the 1-12-75 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Sankaran Koil Telephone Exchange, Tamil Nadu Circle.

[No. 5-18/75-PHB]

का. आ. 4986.—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खंड 3 के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने शंकर नगर टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 1-1-76 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है ।

[संख्या 5-18/75-पी. एच. बी.]

S.O. 4986.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S. O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs, hereby specifies the 1-1-1976 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Sankarnagar Telephone Exchange, Tamil Nadu Circle.

[No. 5-18/75-PHB]

का. आ. 4987.—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खंड 3 के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने विरार टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 1-12-75 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है ।

[संख्या 5-21/75-पी. एच. बी.]

S.O. 4987.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S. O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs, hereby specifies the 1-12-75 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Virar Telephone Exchange, Maharashtra Circle.

[No. 5-21/75-PHB]

नई दिल्ली 14 नवम्बर, 1975

का० आ० 4988.—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने गुरदासपुर टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 1-12-75 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है ।

[संख्या 5-10/75-पी०एच०बी०]

New Delhi, the 14th November, 1975

S.O. 4988.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S. O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs, hereby specifies the 1-12-75 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Gurdaspur Telephone Exchange N. W. Circle.

[No. 5-10/75-PHB]

का० आ० 4989.—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने संगमनेर टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 1-12-75 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है ।

[संख्या 5-21/75 पी०एच०बी]

पी० सी० गुप्ता, सहायक महानिदेशक ।

S.O. 4989.—In pursuance of para (a) Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S. O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs, hereby specifies the 1-12-75 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Sangamner Telephone Exchange, Maharashtra Circle.

[No. 5-21/75-PHB]

P. C. GUPTA, Asstt. Director General (PHB)

नौवहन एवं परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 1975

का० आ० 4990.—श्री के० पी० मुखर्जी ने, जिसे भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 1322, तारीख 7 अप्रैल, 1967 द्वारा स्थापित कलकत्ता डॉक श्रम बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था, डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) नियम, 1962 के नियम 4 के उपनियम (5) की मद (iv) के अधीन अपना पद छोड़ दिया है ;

और उक्त डॉक श्रम बोर्ड में एक रिक्ति हुई है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) नियम, 1962 के नियम 4 के उपबन्धों के अनुसरण में उक्त रिक्ति को अधिसूचित करती है ।

[सं० एल० डी० सी०/2/33/75]

वी० संकारालिंगम, अवर सचिव

MINISTRY OF SHIPPING & TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi, the 4th November, 1975

S.O. 4990.—Whereas Shri K. P. Mukherjee, who was appointed as a member of the Calcutta Dock Labour Board established by the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 1322, dated the 7th April, 1967, is deemed to have vacated his office under item (iv) of sub-rule (5) of rule 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Rules, 1962 ;

And whereas a vacancy has occurred in the said Dock Labour Board ;

Now therefore, in pursuance of the provisions of rule 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Rules, 1962, the Central Government hereby notifies the said vacancy.

[No. LDC/2/33/75]

V. SANKARALINGAM, Under Secy.

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली 16 अक्तूबर, 1975

का० आ० 4991.—केन्द्रीय सरकार, भारतीय रेल अधिनियम, 1890 (1890 का 9) की धारा 53 की उपधारा (1) और उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेल बोर्ड) की अधिसूचना सं० 75/एम० (एन)/951/69, तारीख 12 सितम्बर, 1975 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, '1 अनुज्ञात अधिक लदान की सीमा' के अधीन, उप मद (2) के पश्चात निम्नलिखित उप-मद और टिप्पण अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

"(3) बी० ओ० एक्स०, बी० ओ० आई०, बी० आर० एस०, बी० आर० एच०, बी० सी० एक्स०, बी० ओ० बी० एस०, बी० ओ० बी० एक्स०, वैगनों को उनकी वहन क्षमता से 2 मीटरी टन तक अधिक लदान करने दिया जा सकेगा ।

टिप्पण :—टैंक वैगनों की दशा में, किसी भी प्रकार का अधिक लदान नहीं करने दिया जाएगा ।"

[सं० 75/एम० (एन०)/951/69]

ए० एस० गुप्त, सचिव

पदेन संयुक्त सचिव

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

New Delhi, the 16th October, 1975

S.O. 4991.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and sub-section (4) of section 53 of the Indian Railways Act, 1890 (9 of 1890), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Railway Board) No. 75/M(N)/951/69, dated the 12th September, 1975, namely :—

In the said notification, under item '1. Extent of overloading permitted', after sub-item (2), the following sub-item and note shall be inserted, namely :—

"(3) BOX, BOI, BRS, BRH, BCX, BOBS, BOBX wagons may be permitted the loading tolerance to the extent of 2 tonnes over the carrying capacity.

Note : No overloading is permitted in the case of tank wagons."

[No. 75/M(N)/951/69]

A. L. GUPTA, Secy.,
ex-officio Jt. Secy.

श्रम मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 1975

का० आ० 4992.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के इंडियन कॉपर कॉम्पलेक्स की मोसाबोनी खान, डाकघर मोसाबोनी खानें, जिला सिंहभूम के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण (संख्या 2), धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या मैसर्स हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के इंडियन कॉपर कॉम्पलेक्स की मोसाबोनी खान डाकघर मोसाबोनी खान, जिला सिंहभूम के प्रबन्धतंत्र की, अपनी सुर्दा खान के टिम्बर मज़दूर--श्री नाइकी हो का नाम 25-12-1973 से हाजिरी रजिस्टर से काट देने की कार्रवाई न्यायोचित थी ? यदि नहीं, तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[संख्या एल०-43012/1/75/डी-4 (बी)]

MINISTRY OF LABOUR

ORDER

New Delhi, the 26th August, 1975

S.O. 4992.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Mosaboni Mines of Indian Copper Complex of Messrs Hindustan Copper Limited, Post Office Mosaboni Mines, District Singhbhum and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed ;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause(d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal (No. 2), Dhanbad constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the action of the management of Mosaboni Mines of Indian Copper Complex of Messrs Hindustan Copper Limited, Post Office Mosaboni Mines, District Singhbhum, in striking off the rolls the name of Shri Naiki Hoe, Timber Mazdoor of their Surda Mine with effect from 25-12-1973 was justified? If not, to what relief is the said workman entitled ?

[No. L-43012/1/75-D-IV (B)]

आदेश

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 1975

का० ग्रा० 4993.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स गोमटे मिनरॅल्स की रेडी आयरन ओर माइन, तिलकवाड़ी, बेलगाँव के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7 क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण (स० 2), मुम्बई को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या मैसर्स गोमटे मिनरॅल्स की रेडी आयरन ओर माइन के प्रबन्धतंत्र की, निम्नलिखित 106 स्थायी कर्मकारों को 15 मई, 1975 से छंटनी करने की कार्रवाई न्यायोचित थी ? यदि नहीं, तो सम्बंधित कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं ?

कर्मकारों के नाम :—

1. श्री वी० बी० कन्यालकर ।
2. श्री बी० जे० दीवा ।
3. श्री ए० एन० काम्बली ।
4. श्री एन० वी० नगोलकर ।
5. श्री आर० जे० काम्बली ।
6. श्री वी० ए० भुटे ।
7. श्री एस० आर० काम्बली ।
8. श्री पी० एल० अजगाओंकर ।
9. श्री एस० एन० काम्बली ।
10. श्री के० एस० काम्बली ।
11. श्री एन० एस० कृष्णाजी ।
12. श्री एम० एस० कृष्णाजी ।
13. श्री एच० बी० हुबकेरी ।
14. श्री ए० बी० लोड्रिक ।
15. श्री एम० बी० काम्बली ।
16. श्री एम० ए० पालयेकर ।
17. श्री के० एस० शिरोदकर ।
18. श्री ए० एन० कृष्णाजी ।
19. श्री पी० डी० फर्नान्डीस ।
20. श्री जी० के० राने ।
21. श्री ई० एम० फर्नान्डीस ।
22. श्री जे० डी० केरकर ।
23. श्री ए० जी० मन्जरेकर ।
24. श्री के० ए० काम्बली
25. श्री एन० एम० रेडकर ।
26. श्री जी० बी० रेडकर ।
27. श्री ए० एस० नायर ।
28. श्री ए० बी० कोरगाओंकर ।
29. श्री के० एल० मोराजकर ।
30. श्री एम० बी० अवाडे ।
31. श्री वी० के० नायक ।
32. श्री एस० एस० वेनगुरलेकर ।
33. श्री टी० टी० कोइल्हो ।
34. श्री टी० एस० पिलानकर ।
35. श्री जी० पी० साखोलकर
36. श्री एम० ए० सूर्याजी ।
37. श्री आई० जे० दीया ।
38. श्री के० एस० कामत ।
39. श्री बी० डी० मन्नेकर ।
40. श्री आर० डी० सुतर ।
41. श्री एम० ए० सतगाओकर ।
42 श्री एन० एन० रेडकर ।
13. श्री एम० बी० [illegible] ।
44. श्री यू० एम० पडवाल ।
45. श्री टी० आर० लोहार ।
46. श्री एस० जी० गावेकर ।
47. श्री एम० ए० सामन्त ।
48 श्री एन० एम० इब्राहिमपुरकर ।
49. श्री आर० एन० रेडकर ।
50. श्री जी० पी० रेड्डी ।
51. श्री एस० आर० वरखाण्डकर ।

52. श्री पी० एन० पोरेरा ।
53. श्री जी० एल० गुतर ।
54. श्री डी० ए० रोड्रिक ।
55. श्री एम० जी० यरखाण्डकर ।
56. श्री जे० एच० कन्यालकर ।
57. श्री एच० टी० कदम ।
58. श्री एस० डी० सूर्य वंशी ।
59. श्री बी० एन० अरोनवेकर ।
60. श्री डी० एन० मयेकर ।
61. श्री डी० एस० कन्यालकर ।
62. श्री यू० वी० सतोस्कर ।
63. श्री एन० के० तिवारेकर ।
64. श्री एम० टी० काम्बली ।
65. श्री जे० वी० गावडे ।
66. श्री आर० एन० पारब ।
67. श्री एम० ह० अरोलकर ।
68. श्री ए० ए० शतकर ।
69. श्री एस० बी० पेड्नेकर ।
70. श्री पी० बी० पेड्नेकर ।
71. श्री पाण्डुरंग जी० परब ।
72. श्री एम० जे० गाओतालकर ।
73. श्री टी० एस० परब ।
74. श्री डी० एच० काम्बली ।
75. श्री बी० टी० केरकर ।
76. श्री एच० एस० बादर ।
77. श्री बी० एन० काम्बली ।
78. श्री आर० डी० रेडकर ।
79. श्री एम० डी० पेडनेकर ।
80. श्री एन० जी० गोसावी ।
81. श्री एम० वी० गोवन्वी ।
82. श्री टी० एम० कोनाथकर ।
83. श्री सी० बी० काम्बली ।
84. श्री एस० बी० रेडकर ।
85. श्री बी० जी० नागोलकर ।
86. श्री अंकुश बी० रेडकर ।
87. श्री एस० बी० केरकर ।
88. श्री एल० आर० पारुलेकर ।
89. श्री एस० आर० गावडे ।
90. श्री केतन एम० शिवालकर ।
91. श्री एम० एम० रेडकर ।
92. श्री आर० एस० रेडकर ।
93. श्री के० बी० सूर्याजी ।
94. श्री एस० के० उपशेकर ।
95. श्री पी० डी० भुजग ।
96. श्री वी० वी० सावन्त ।
97. श्री के० एल० पेड्नेकर ।
98. श्री बी० ई० खान ।
99. श्री ए० ई० खान ।
100. श्री जे० एम० पालयेकर ।
101. श्री विथल के० गावन्वी ।
102 श्री राजाराम एस० सातोस्कर ।
103. श्री मधुकर बी० सावन्त ।
104. श्री आर० एम० पडवल ।
105. श्री सदानन्द शिरोदकर ।
106. श्री जी० वी० रावत ।

[संख्या एल०-26012/11/75-डी-4(बी)]

ORDER

New Delhi, the 1st September, 1975

S.O. 4993.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Redi Iron Ore Mine of Messrs Gogte Minerals, Tilakwadi, Belgaum and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal (No. 2), Bombay constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the action of the management of Redi Iron Ore Mine of Messrs Gogte Minerals in retrenching the following 106 permanent workmen with effect from the 15th May, 1975 was justified ? If not, to what relief are the concerned workmen entitled ?

Names of the workmen :—

1. Shri V. B. Kanyalkar.
2. Shri B. J. Deeya.
3. Shri A. N. Kambli.
4. Shri N. V. Nagolkar.
5. Shri R. J. Kambali.
6. Shri V. A. Bhute.
7. Shri S. R. Kambli.
8. Shri P. L. Ajgaonkar.
9. Shri S. N. Kambli.
10. Shri K. S. Kambli.
11. Shri N. S. Krishnaji.
12. Shri M. S. Krishnaji.
13. Shri H. B. Hukkeri.
14. Shri A. B. Lodric.
15. Shri M. B. Kambli.
16. Shri M. A. Palyekar.
17. Shri K. S. Shirodkar.
18. Shri A. N. Krishnaji.
19. Shri P. D. Fernandes.
20. Shri G. K. Rane.
21. Shri E. M. Fernandes.
22. Shri J. D. Kerkar.
23. Shri A. G. Manjarekar.
24. Shri K. A. Kambli.
25. Shri N. M. Redkar.
26. Shri G. V. Redkar.
27. Shri U. S. Nair.
28. Shri A. Y. Korgaonkar.

29. Shri K. L. Morajkat.
30. Shri M. B. Awade.
31. Shri V. K. Naik.
32. Shri S. S. Vengurlekar.
33. Shri T. T. Coelho.
34. Shri D. S. Pilankar.
35. Shri G. P. Sakholkar.
36. Shri M. A. Suryaji.
37. Shri I. J. Deeya.
38. Shri K. S. Kamat.
39. Shri B. D. Mannekar.
40. Shri R. D. Sutar.
41. Shri M. A. Salgaonkar.
42. Shri S. N. Redkar.
43. Shri M. V. Pilankar.
44. Shri U. S. Padval
45. Shri T. R. Lohar.
46. Shri S. G. Gadekar.
47. Shri S. A. Samant.
48. Shri N. S. Ibrahimpurkar.
49. Shri R. L. Redkar.
50. Shri G. P. Reddy.
51. Shri S. R. Warkhandkar.
52. Shri P. N. Pereira.
53. Shri G. L. Sutar.
54. Shri D. A. Rodric.
55. Shri M. G. Warkhandkar.
56. Shri J. H. Kanyalkar.
57. Shri H. T. Kadam.
58. Shri S. D. Suryawamshi.
59. Shri B. N. Arondekar.
60. Shri D. N. Mayekar.
61. Shri D. S. Kanyalkar.
62. Shri U. V. Satoskar.
63. Shri N. K. Trivarekar.
64. Shri M. T. Kambli.
65. Shri J. V. Gawade.
66. Shri R. M. Parab.
67. Shri M. E. Arolkar.
68. Shri A. A. Shatkar
69. Shri S. B. Pednekar.
70. Shri P. B. Pednekar.
71. Shri Pandurang G. Parab.
72. Shri M. J. Gaotalkar.
73. Shri T. S. Parab.
74. Shri D. H. Kambli.
75. Shri B. T. Kerkar.
76. Shri H. S. Vadar.
77. Shri B. H. Kambli.
78. Shri R. D. Redkar.
79. Shri M. D. Pednekar.
80. Shri N. G. Gosavi.
81. Shri M. B. Gavandi.
82. Shri T. M. Konadkar.
83. Shri C. V. Kambli.
84. Shri S. B. Redkar.
85. Shri V. G. Nagolkar.
86. Shri Ankush B. Redkar.
87. Shri S. V. Kerkar.
88. Shri L. R. Parulekar.
89. Shri S. R. Gawade.
90. Shri Kaitan M. Shivalkar.
91. Shri M. M. Redkar.
92. Shri R. S. Redkar.
93. Shri K. P. Suryaji.
94. Shri S .K. Upshekar.
95. Shri P. D. Bhujang.
96. Shri V. V. Sawant.
97. Shri K. S. Pednekar.
98. Shri B. E. Khan.
99. Shri A. E. Khan.
100. Shri J. M. Palyekar.
101. Shri Vithal K. Gavandi.
102. Shri Rajaram S. Satoskar.
103. Shri Madhukar V. Savant.
104. Shri R. M. Padval.
105. Shri Sadanand Shirodkar.
106. Shri G. V. Raut.

[No. L-26012/11/75-D-IV(B)]

आदेश

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 1975

का०आ० 4994.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इसमें उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लि० की जादूगुडा यूरेनियम माइन्स, जादूगुडा माइन्स, जिला सिंहभूम के प्रबन्धतन्त्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण (संख्या 2), धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या मैसर्स यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड की जादूगुडा यूरेनियम माइन्स, जादूगुडा माइन्स, जिला सिंहभूम के प्रबन्धतन्त्र की, जादूगुडा माइन्स के मिल प्रभाग के सहायक 'ग'—श्री चन्द्रेश्वर राय को 3 अगस्त, 1974 से पदच्युत करने की कार्रवाई न्यायोचित थी ? यदि नहीं, तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[संख्या एल०-29011/6/75-डी०ओ०/3(बी०)डी०-4 (बी)]

ORDER

New Delhi, the 3rd September, 1975

S.O. 4994.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Jaduguda Uranium Mines of Messrs Uranium Corporation of India Limited, Jaduguda Mines, District Singhbhum and their workman in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed ;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal (No. 2), Dhanbad constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the action of the management of Jaduguda Uranium Mines of Messrs Uranium Corporation of India Limited, Jaduguda Mines, District Singhbhum, in dismissing Shri Chandreswar Rai, Helper 'C', Mill Division, Jaduguda Mines with effect from the 3rd August, 1974 was justified? If not, to what relief is the said workman entitled?

[No. L-29011/6/75-D.O.3(B)/D-IV(B)]

आदेश

नई दिल्ली, 4 अक्तूबर, 1975

का० आ० 4995—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में हिन्दुस्तान कॉपर कॉर्म्प्लैक्स के खेत्री कॉपर कॉम्प्लैक्स, डाकघर खेत्री नगर, जिला झुनझुनू के प्रबन्धतन्त्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री यू० एन० माथुर होंगे, जिनका मुख्यालय जयपुर में होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है?

अनुसूची

क्या हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के खेत्री कॉम्प्लैक्स, डाकघर खेत्री नगर, जिला झुनझुनू के प्रबन्धतन्त्र की अपनी कोलीहान ताम्र खान में नियोजित सर्वश्री गजवीर सिंह सोढा (कम्प्रैसर ऑपरेटर), रामचन्द्र (सेम्पलर), फूल चन्द्र (खनिक) और ओम प्रकाश (ड्रिलमैन) को 31-5-1975 से पदच्युत करने की कार्रवाई न्यायोचित है? यदि नहीं, तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं?

[संख्या एल०-43011/3/75/डी० 4/बी०]

भूपेन्द्र नाथ, अनुभाग अधिकारी (विशेष)

ORDER

New Delhi, the 4th October, 1975

S.O. 4995.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Khetri Copper Complex of Hindustan Copper Complex, Post Office Khetrinagar, District Jhunjhunu and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10, of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri U. N. Mathur shall be the Presiding Officer, with headquarters at Jaipur and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

Whether the action of the management of Khetri Copper Complex of Hindustan Copper Limited, Post Office Khetrinagar, District Jhunjhunu in dismissing Sarvashri Gajvir Singh Sodha (Compressor Operator), Ram Chander (Sampler), Phoolchand (Miner) and Om Prakash (Drillman) employed in their Kolihan Copper Mine with effect from 31-5-1975, is justified? If not, to what relief are the said workmen entitled?

[No. L-43011/3/75/D.IV/B]

BHUPENDRA NATH, Section Officer (Spl.)

आदेश

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 1975

का०आ० 4996.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में बैंक आफ इंडिया से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण दिल्ली को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या बैंक आफ इंडिया के प्रबन्धतन्त्र को अपनी मेरठशाखा के लिपिक एवं टंकक श्री ए० के० जैन की 10 अप्रैल, 1975 से सेवायें समाप्त करने की कार्रवाई न्यायोचित है? यदि नहीं, तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है?

[सं० एल०-12012/98/75-डी०-II/-ए०]

ORDER

New Delhi, the 6th September, 1975

S.O. 4996.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Bank of India and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Delhi, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the management of the Bank of India is justified in terminating the services of Shri A. K. Jain, clerk-cum-Typist of the Meerut Branch of the said Bank with effect from the 10th April, 1975? If not, to what relief is the said workman entitled?

[No. L-12012/98/75/DII/A]

आदेश

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 1975

का०आ० 4997.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में पंजाब नेशनल बैंक से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करना वांछनीय समझती है ।

अत, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री एच०आर० सोधी होंगे जिनका मुख्यालय चण्डीगढ़ में होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या पंजाब नेशनल बैंक, चंडीगढ़ के प्रबन्धतन्त्र की अपने अधीनस्थ कर्मचारी श्री सुभाष चन्द्र को उक्त बैंक की काठमंडी शाखा में वफ्तरी के रूप में कार्य करने से रोकने और उक्त बैंक का रेलवे रोड रोहतक शाखा में जनवरी, 1975 में उसका स्थानान्तरण करने की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[सं० एल०-12012/102/75-डी०-2-ए०]

ORDER

New Delhi, the 8th September, 1975

S.O. 4997.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Punjab National Bank and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed ;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A and clause (d) of sub-section (1) of section 10, of the Industrial disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri H. R. Sodhi shall be the Presiding Officer, with headquarters at Chandigarh and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

Whether the action of the management of the Punjab National Bank, Chandigarh Region, is justified in denying Shri Subhas Chand subordinate Staff, to work as Daftri at the Kathmandi Branch of the said Bank and in transferring him to Railway Road, Rohtak Branch of the said Bank in January 1975 ? If not to what relief is the said workman entitled ?

[No. L. 12012/102/75/DII/A]

आदेश

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 1975

का० आ० 4998.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में नेशनल एण्योरेंस कम्पनी लिमिटेड से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्याय निर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण कलकत्ता को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या भारतीय साधारण बीमा निगम का एकक नेशनल एण्योरेंस कंपनी लिमिटेड के प्रबन्धतन्त्र का श्री बी०एस० दास, निरीक्षक की 22 सितम्बर, 1970 से सेवा समाप्त करने की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[सं० एल०-12011/13/71-आई०आर०-1]

ORDER

New Delhi, the 10th September, 1975

S.O. 4998.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the National Insurance Company Limited and their workman in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed ;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of Sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Calcutta constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the action of the management of the National Insurance Company Limited, a unit of the General Insurance Corporation of India, is justified in terminating the services of Shri B. S. Das, Inspector, with effect from the 22nd September 1970 ? If not, to what relief is the said workman entitled ?

[No. L. 17011/13/71/IR I]

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 1975

शुद्धिपत्र

का०आ० 4999.—भारत के राजपत्र, भाग-2, खंड 3(ii) तारीख 28 जून, 1975 के पृष्ठ 2231 पर संख्या का०आ० 2027 के अधीन प्रकाशित श्रम मंत्रालय के आदेश सं० एल० 12012/126/74-एल०आर०-III तारीख 20 मई, 1975 की अनुसूची में "अमृक लाल" के स्थान पर "अमृत लाल" पढ़ें।

[सं० एल०-12012/126/74-एल०आर०3]

New Delhi, the 11th September, 1975

CORRIGENDUM

S.O. 4999.—In the Schedule to Ministry of Labour Order No. L-12012/126/74-LR. III dated the 20th May, 1975, published on page 2331, Part II, Section 3(ii) of the Gazette of India dated the 28th June, 1975, under Number S.O. 2027, for "Amrik Lal", read "Amrit Lal".

[No. L. 12012/126/74-LR. III]

आदेश

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 1975

का०आ० 5000.—इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट औद्योगिक विवाद औद्योगिक अधिकरण, दिल्ली के समक्ष लम्बित है;

और अखिल भारतीय पंजाब नेशनल बैंक कर्मचारी संगम ने केन्द्रीय सरकार से यह निवेदन किया है कि वह उक्त विवाद को केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, धनबाद को इस कारण अन्तरित कर दे कि कर्मकार

बिहार राज्य में, आरा में नियोजित था, अतः सम्पूर्ण साक्ष्य आरा से प्राप्त करना है और यदि साक्ष्य को दिल्ली लाया जाता है तो इससे उसे कठिनाई होगी और खर्च भी उठाना पड़ेगा ;

और केन्द्रीय सरकार निवेदन को युक्तियुक्त समझती है ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 33 ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, औद्योगिक अधिकरण, दिल्ली के समक्ष लम्बित उक्त विवाद के सम्बन्ध में कार्यवाहियों को वापस लेती है और उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण (सं० 1) धनबाद को उक्त कार्यवाहियों के निपटारे के लिये अन्तरित करती है और यह निदेश देती है कि उक्त अधिकरण उक्त कार्यवाहियों पर उस प्रक्रम से कार्यवाही करेगा, जिस पर वे अन्तरित की जायें, और उनका विधि के अनुसार निपटारा करेगा ।

अनुसूची

क्रम सं०	अधिसूचना सं० और तारीख	पक्षकारों के नाम
1.	एल०-12012/106/74-एल० आर०3, तारीख 15 अप्रैल, 1975 ।	पंजाब नेशनल बैंक और उसके कर्मकार ।

[सं० एल०-12012/106/74-एल०आर०3]

ORDER

New Delhi, the 16th September, 1975

S.O. 5000.—Whereas the industrial dispute specified in the Schedule hereto annexed is pending before the Industrial Tribunal, Delhi ;

And, whereas the All India Punjab National Bank Employees Association has requested the Central Government for transferring the said dispute to the Central Government Industrial Tribunal, Dhanbad for the reason that, since the workman was employed at Arrah in Bihar State the entire evidence is to be adduced from Arrah and it would cause him hardship and expenditure, if the evidence is to be brought to Delhi ;

And, whereas the Central Government considers the request as reasonable ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 33B of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby withdraws the proceedings in relation to the said dispute pending before the Industrial Tribunal, Delhi, and transfers the same to the Central Government Industrial Tribunal (No. 1), Dhanbad, constituted under section 7A of the said Act, for the disposal of the said proceedings and directs that the said Tribunal shall proceed with the said proceedings from the stage at which it is transferred to it and dispose of the same according to law.

SCHEDULE

Sl. No.	Notification No. and date	Name of the parties
1.	L. 12012/106/74-LRIII, dated the 15th April, 1975.	Punjab National Bank and their workmen.

[No. L-12012/106/74-LR-III]

आदेश

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 1975

का०आ० 5001.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में भारतीय स्टेट बैंक से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण कलकत्ता को न्याय-निर्णयन के लिये निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या भारतीय स्टेट बैंक के कर्मकारों का, जिनका प्रतिनिधित्व भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी संगम, बंगाल सर्किल करता है, यह मांग कि ऐसी कैन्टीनों के कर्मचारिवृन्द को जो स्थानीय क्रियान्वयन समितियों द्वारा चलाई जा रही हैं वैसी ही हैसियत, वेतन और सुविधाएं देने के लिये जो बैंक के अन्य वर्ग 4 कर्मचारियों को उपलब्ध हैं, भारतीय स्टेट बैंक का कर्मचारी समझा जाय, न्यायोचित है ? यदि हां, तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं ?

[सं० एल-12011/10/75-डी-2/ए]

ORDER

New Delhi, the 17th September, 1975

S.O. 5001.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the State Bank of India and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Calcutta, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the demand of the workman of the State Bank of India represented by the State Bank of India Employees' Association, Bengal Circle, for treating the staff of such canteens which are run by the Local Implementation Committees, as workmen of State Bank of India for giving them the same status, pay and facilities as are available to other class IV employees of the Bank is justified ? If so, to what relief the workmen concerned are entitled ?

[No. L. 12011/10/75/DII/A]

आदेश

का० आ० 5002.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में भारतीय स्टेट बैंक से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करना वांछनीय समझती है ।

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण सं० 1 धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या भारतीय स्टेट बैंक के प्रबन्धतंत्र का, उक्त बैंक का देवगढ़ शाखा के रोकड़िया श्री श्यामाचरन मिश्र की सेवाएं 16 फरवरी, 1974 से समाप्त करने की कार्रवायी न्यायोचित है ? यदि नहीं तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[सं० एल-12012/78/75-डी० II/ए]

आर० कुंजीथापदम, अवर सचिव

ORDER

S.O. 5002.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the State Bank of India and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, No. (1) Dhanbad, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the action of the management of the State Bank of India in terminating the services of Shri Shyama Charan Mishra, Cashier in Deoghar Branch of the said Bank with effect from 16th February, 1974 is justified ? If not, to what relief is the said workman entitled ?

[No. L. 12012/78/75/DII/A]

R. KUNJITHAPADAM, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 1975

का० आ० 5003.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में कलकत्ता पत्तन न्यास, कलकत्ता से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कलकत्ता को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या कलकत्ता पत्तन न्यास के वरिष्ठ पोतकार अनुभाग के कर्मकारों को, बरसातियों के प्रदाय के लिये मांग न्याययोचित है ? यदि हां, तो किस मान पर और किस तारीख से ?

[संख्या एल-32011/21/75-डी० 4(ए)]

New Delhi, the 10th September, 1975

S.O. 5003.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Calcutta Port Trust, Calcutta and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the demand of the workmen of Senior Shipwright Section of Calcutta Port Trust for supply of rain coats is justified ? If so, on what scale and from what date ?

[No. L. 32011/21/75-D IV(A)]

आदेश

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 1975

का०आ० 5004.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स न्यू ढोलेरा शिपिंग एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड, मुम्बई के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करना वांछनीय है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण संख्या 2, मुम्बई को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या मैसर्स न्यू ढोलेरा शिपिंग एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड मुम्बई के प्रबन्धतंत्र को अपने कार्यालय सहायक, श्री बी० जे० भगत की 22 जून, 1974 से सेवाएं समाप्त करने की कार्रवाई न्यायोचित थी ? यदि नहीं तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[संख्या एल-31012/2/75-डी० 4(ए)]

नन्द लाल, अनुभाग अधिकारी (विशेष)

ORDER

New Delhi, the 20th September, 1975

S.O. 5004.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Messrs New Dholera Shipping and Trading Company Limited, Bombay, and their workman in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Bombay constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whetcher the action of the management of Messrs. New Dholera Shipping and Trading Company Limited, Bombay, in terminating the services of Shri B. J. Bhagat, their Office Assistant, with effect from the 22nd June, 1974, was justified ? If not, to what relief is the said workman entitled ?

[No. L-310012/2/75-D. IV(A)]

NAND LAL, Section Officer, (Spl.)

आदेश

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 1975

का० आ० 5005.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की जोयरामपुर कोलियरी, डाकघर खास जीनागोरा, जिला धनबाद के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण संख्या 2, धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की जोयरामपुर कोलियरी, डाकघर खास जीनागोरा, जिला धनबाद के प्रबन्धतंत्र की, निम्नलिखित श्रमिकों की सेवाओं का नियमितीकरण न करने की कार्रवाई न करने की कार्रवाई न्यायोचित है ?

(1) श्री कपुरा बोउरी

(2) श्री पौदी पंडित

(3) श्रीमती जितानी मियां कामिल

(4) श्री सुगा पासवान

(5) श्री रामबालक पासवान

(6) श्री बिगा पासवान

(7) श्री बिलोगोप (तिलोगोप)

(8) श्री हासमुद्दीन मियां

(9) श्री भोला मियां और

(10) श्री अनिक भुइया

यदि नहीं तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं और किस तारीख से।

[सं० एल-20012/95/75-डी०/III ए]

ORDER

New Delhi, the 17th September, 1975

S.O. 5005.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Joyrampur Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Khas Jeenagora, District Dhanbad and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereaes the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Dhanbad, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whethere the action of the management of Jayrampur Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited Post Office Khas Jeenagora, District Dhanbad, in not regularising the following workers, is justified ?

(1) Shri Kapura Bouri
(2) Sri Paudi Pandit
(3) Shrimati Jitani Mian Kamin
(4) Sri Suga Paswan
(5) Sri Rambalak Paswan
(6) Sri Diga Paswan
(7) Sri Bilo Gope (Tilo Gope)
(8) Sri Hasmuddin Mia
(9) Sri Bhola Mian
(10) Sri Anik Bhuia.

If not, to what relief are the said workmen entiled and from what dates ?

[No. L-20012/95/75/D. III. A]

आदेश

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 1975

का०आ० 5006.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स नेशनल कोल डिवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड की मोनिडिह, कोलियरी के ठेकेदार, मैसर्स सालिगराम मोदी एण्ड कम्पनी, डाकघर मोनिडिह, जिला धनबाद के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कमकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण संख्या 2, धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या मैसर्स नेशनल कोल डिवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड की मोनिडिह कोलियरी के ठेकेदार, मैसर्स सालिगराम मोदी एण्ड कम्पनी डाकघर मोनिडिह जिला धनबाद के प्रबन्धतंत्र की निम्नलिखित कर्मकारों को काम से रोकने की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं ?

क्रम संख्या	कर्मकारों के नाम	पदाभिधान
1.	श्री मथरा बोउरी	मिट्टी और पत्थर काटने वाले मजदूर
2.	श्री अजीत बोउरी	—यथोक्त—
3.	श्री पहालु बोउरी	—यथोक्त—
4.	श्री उजाला बोउरी	—यथोक्त—
5.	श्रीमती राधी बोउरी	—यथोक्त—
6.	श्रीमती बौती बोउरी	—यथोक्त—
7.	श्रीमती सोरी बोउरी	—यथोक्त—
8.	श्री दुबराज बोउरी	—यथोक्त—

क्रम सं०	कर्मकारों का नाम	पदाभिधान
9.	श्री रोहन	मिट्टी और
10.	श्रीमती जमुना बोउरी	पत्थर काटने
11.	श्रीमती मंजूरा बोउरी	वाले मजदूर
12.	श्री भेजु बोउरी	–यथोक्त–
13.	श्री अमुल्या बोउरी	–यथोक्त–
14.	श्रीमती चान बाला	–यथोक्त–
15.	श्रीमती लतिका बाला	–यथोक्त–
16.	श्रीमती महादेव बाला	–यथोक्त–
17.	श्री अनन्दु बाला	–यथोक्त–
18.	श्री गोपी बाला	–यथोक्त–
19.	श्री साहादेव बाला	–यथोक्त–
20.	श्री नन्तु बाला	–यथोक्त–
21.	श्रीमती कबिता	–यथोक्त–
22.	श्रीमती सुशीला	–यथोक्त–
23.	श्रीमती मिथिला	–यथोक्त–
24.	श्रीमती दुसी	–यथोक्त–
25.	श्री सागर मांझी	–यथोक्त–
26.	श्रीमती मानी	–यथोक्त–
27.	श्री भारत	–यथोक्त–
28.	श्री अक्लाग	–यथोक्त–
29.	श्री सुफल बोउरी	–यथोक्त–
30.	श्री गोखल	–यथोक्त–
31.	श्रीमती शंकरी	–यथोक्त–
32.	श्रीमती बालिका	–यथोक्त–
33.	श्रीमती चपला	–यथोक्त–
34.	श्री गोउर बोउरी	–यथोक्त–
35.	श्री भगत बोउरी	–यथोक्त–
36.	श्री सुदारा	–यथोक्त–
37.	श्री अलता	–यथोक्त–
38.	श्री इन्द्रा	–यथोक्त–
39.	श्री बोदी	–यथोक्त–
40.	श्रीमती चुल्वि	–यथोक्त–
41.	श्रीमती छेपी	–यथोक्त–
42.	श्री मामदास	–यथोक्त–
43.	श्री मोनु	–यथोक्त–
44.	श्री हारू	–यथोक्त–
45.	श्रीमती बीबी	–यथोक्त–
46.	श्रीमती लक्ष्मी	–यथोक्त–
47.	श्री राजेन्द्रा गन्जु	–यथोक्त–
48.	श्री खेबु गन्जु	–यथोक्त–
49.	श्रीमती मुस्तुई	–यथोक्त–
50.	श्रीमती सनिचरिया	–यथोक्त–
51.	श्री रोशनी गन्जु	–यथोक्त–
52.	श्री बासनी सीतराम	–यथोक्त–
53.	श्री हान्डु सोउरी	–यथोक्त–
54.	श्री वासु बोउरी	–यथोक्त–
55.	श्रीमती साम्नि	–यथोक्त–
56.	श्रीमती मालती	–यथोक्त–
57.	श्री कामाद	मिट्टी और
58.	श्री चैतन	पत्थर काटने
59.	श्री गुरपादा	वाले मजदूर
60.	श्री सुभान्कर	–यथोक्त–
61.	श्रीमती बातश्ला	–यथोक्त–
62.	श्रीमती अचला	–यथोक्त–
63.	श्रीमती सावित्री	–यथोक्त–
64.	श्री चेत्तु	–यथोक्त–
65.	श्री भारत	–यथोक्त–
66.	श्रीमती मुनिबाला	–यथोक्त–
67.	श्रीमती पुरिकबोउरी	–यथोक्त–
68.	श्री घोरात	–यथोक्त–
69.	श्री नागेन्द्र	–यथोक्त–
70.	श्री कार्तिक	–यथोक्त–
71.	श्री बिसुए	–यथोक्त–
72.	श्री सिताला	–यथोक्त–
73.	श्रीमती रती	–यथोक्त–
74.	श्रीमती रोबानी	–यथोक्त–
75.	श्री चोपाला	–यथोक्त–
76.	श्री धिरेन	–यथोक्त–
77.	श्री देबु	–यथोक्त–
78.	श्री जगदीश	–यथोक्त–
79.	श्री हृयला	–यथोक्त–
80.	श्रीमती बिजाला	–यथोक्त–
81.	श्रीमती बेली	–यथोक्त–
82.	श्रीमती मारू	–यथोक्त–
83.	श्रीमती मान्तु	–यथोक्त–
84.	श्री सहदेव	–यथोक्त–
85.	श्रीमती रेशमी	–यथोक्त–
86.	श्री बिजाला	–यथोक्त–
87.	श्रीमती फुलमणि	–यथोक्त–
88.	श्री खोडु मांह्रातो	–यथोक्त–
89.	श्रीमती रोसनी	–यथोक्त–
90.	श्री लोबिन दास	–यथोक्त–
91.	श्रीमती चोरी दोमिन	–यथोक्त–
92.	श्रीमती कमला	–यथोक्त–
93.	श्री कनाईलाल धोबी	–यथोक्त–
94.	श्रीमती छोबि	–यथोक्त–
95.	श्री खेतु माह्रातो	–यथोक्त–
96.	श्री दुखम बोउरी	–यथोक्त–
97.	श्रीमती बिलासी	–यथोक्त–
98.	श्री बादल बोउरी	–यथोक्त–
99.	श्री पागाल	–यथोक्त–
100.	श्री अमुल्या	–यथोक्त–
101.	श्रीमती मेमी	–यथोक्त–
102.	श्रीमती मेपुता	–यथोक्त–
103.	श्रीमती कमला	–यथोक्त–
104.	श्रीमती नेबु	–यथोक्त–

क्रम सं०	कर्मकारों का नाम	पदाभिधान
105.	श्री बोनु	मिट्टी और
106.	श्री कनाई	पत्थर काटने
107.	श्री तारापाद्	वाले मजदूर
108.	श्री फाटिक	–यथोक्त-
109.	श्री रासु	-यथोक्त-
110.	श्री सक्ति	–यथोक्त–
111.	श्री मान्तु	–यथोक्त-
112.	श्री बासु	-यथोक्त-
113.	श्री कमल	-यथोक्त-
114.	श्री अकलु	-यथोक्त-
115.	श्री सीबरण	–यथोक्त–
116.	श्री घासी राम बोउरी	–यथोक्त–
117.	श्री दिगाम्बर राय	–यथोक्त–
118.	श्री बोजोए बोउरी	–यथोक्त–
119.	श्री बाबूलाल	–यथोक्त–
120.	श्री गंगाधर सिंह चौधरी	सरदार
121.	श्रीमती पारिसोष	मिट्टी और
122.	श्री भादेरी	पत्थर काटने
123.	श्री चैता	वाले मजदूर
124.	श्री गंगा	–यथोक्त-
125.	श्रीमती ममभुला	-यथोक्त-
126.	श्री माजारी	-यथोक्त–
127.	श्री सत्या	–यथोक्त–
128.	श्री अक्लु	–यथोक्त–
129.	श्रीमती अवारी	-यथोक्त-
130.	श्रीमती लतिका	-यथोक्त-
131.	श्री पातु	-यथोक्त-
132.	श्री खाम्लु	-यथोक्त-
133.	श्री गोमु बोउरी	-यथोक्त-
134.	श्री सुलोचना	–यथोक्त–
135.	श्रीमती बिजाला	-यथोक्त-
136.	श्रीमती नेपाली	-यथोक्त-
137.	श्रीमती पंखि	–यथोक्त-
138.	श्रीमती कापुरा	-यथोक्त-
139.	श्रीमती बिदु	–यथोक्त-
140.	श्रीमती गुंगनी	–यथोक्त–
141.	श्रीमती सुखादा	–यथोक्त–
142.	श्रीमती भेली	–यथोक्त–
143.	श्रीमती नारदा	-यथोक्त–
144.	श्रीमती कौसिला	–यथोक्त–
145.	श्री बिपुलि	–यथोक्त–
146.	श्री रधु	–यथोक्त–
147.	श्री रसिम	–यथोक्त–
148.	श्री काजाला	–यथोक्त–
149.	श्रीमती चम्पा	-यथोक्त–
150.	श्रीमती चाबिला	–यथोक्त–
151.	श्रीमती बिरबल	–यथोक्त–
152.	श्री छुट्टु	–यथोक्त-
153.	श्री बाधारी	मिट्टी और
154.	श्री बासुदेव	पत्थर काटने
155.	श्री कालेपादा	वाले मजदूर
156.	श्री मानोका	-यथोक्त-
157.	श्री गुगाई	-यथोक्त–
158.	श्री संकर	–यथोक्त–
159.	श्री भादि	–यथोक्त–
160.	श्री पारी	–यथोक्त-
161.	श्रीमती लखन	-यथोक्त-
162.	श्री सामल	-यथोक्त–
163.	श्री अमुल्या	-यथोक्त-
164.	श्रीमती सकुन्तला	-यथोक्त-
165.	श्रीमती लालु	–यथोक्त–
166.	श्री बाबुर	–यथोक्त–
167.	श्री सुरी	–यथोक्त–
168.	श्रीमती बारोश्रांई	–यथोक्त–
169.	श्री लिकोमि	–यथोक्त–
170.	श्रीमती फालारी	–यथोक्त–
171.	श्री चुट्टु	-यथोक्त–
172.	श्रीमती सन्सारी बोम्मिन	-यथोक्त-
173.	श्री सामूला	-यथोक्त-
174.	श्री नेबू	-यथोक्त-
175.	श्री अनिल	-यथोक्त-
176.	श्रीमती पेमिला	-यथोक्त–
177.	श्री नेबी	–यथोक्त–
178.	श्री चन्दु	–यथोक्त-
179.	श्री जगदीश	-यथोक्त-
180.	श्रीमती मिथिला	–यथोक्त–
181.	श्रीमती ग्रोपन	–यथोक्त-
182.	श्रीमती अशोनि	-यथोक्त-
183.	श्री लालु	-यथोक्त-
184.	श्रीमति दोम	–यथोक्त–
185.	श्रीमती भालिया	-यथोक्त-
186.	श्री लालूमोचन	-यथोक्त-
187.	श्री सत्रुधन	–यथोक्त–
188.	श्रीमती बुलारी	-यथोक्त-
189.	श्री अबिलाश	-यथोक्त-
190.	श्री गोपाल	-यथोक्त-
191.	श्री सशि	-यथोक्त-
192.	श्रीमती कासानि	-यथोक्त-
193.	श्री किपून	-यथोक्त–
194.	श्रीमती चारी बोउरिन	–यथोक्त–
195.	श्री भमेश्वर सिंह चौधरी	सरदार

[सं० एल-20012/156/74-एल० आर० II डी० III ए०]

ORDER

New Delhi, the 19th Sept., 1975

S.O. 5006.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Messrs Saligram Modi and Company, Contractor, Monidih Colliery of Messrs National Coal Development Corporation Limited, Post Office Monidih, District Dhanbad and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed ;

And Whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication ;

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by Clause (d) of sub- section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal No. 2 Dhanbad Constituted under Section 7A of the said Act.

THE SCHEDULE

Whether the action of the management of Messrs Saligram Modi and Company, Contractor, Monidih Colliery of Messrs National Coal Development Corporation Limited, Post office Monidih, District Dhanbad, in stopping from work with effect from the 2nd June 1974 the undermentioned workmen, is justified ? If not, to what relief are the said workmen entitled?

Serial No.	Name of the workmen	Designation
1.	Shri Mathura Bouri	Earth & Stone cutting Mazdoor
2.	Shri Ajit Bouri	Do.
3.	Shri Pahalu Bouri	Do.
4.	Shri Ujala Bouri	Do.
5.	Smt. Badhi Bouri	Do.
6.	Smt. Boti Bouri	Do.
7.	Smt. Sori Bouri	Do.
8.	Shri Dubraj Bouri	Do.
9.	Shri Rohan	Do.
10.	Smt. Jamuna Bouri	Do.
11.	Smt. Manjura Bouri	Do.
12.	Shri Bhoju Bouri	Do.
13.	Shri Amulya Bouri	Do.
14.	Smt. Chan Chala	Do.
15.	Smt. Latika Chala	Do.
16.	Smt. Mahadeb Chala	Do.
17.	Shri Anandu Chala	Do.
18.	Shri Gopi Chala	Do.
19.	Shri Sahadeo Chala	Do.
20.	Shri Nantu Chala	Do.
21.	Smt. Kabita	Do.
22.	Smt. Sushila	Do.
23.	Smt. Mithila	Do.
24.	Smt. Dusi	Do.
25.	Shri Sagar Manjhi	Do.
26.	Smt. Mani	Do.
27.	Shri Bharat	Do.
28.	Shri Abtag	Do.
29.	Shri Sufal Bouri	Do.
30.	Shri Gokhal	Do.
31.	Smt. Shankari	Do.
32.	Smt. Balika	Do.
33.	Smt. Chapala	Do.
34.	Shri Gour Bouri	Do.
35.	Shri Bhagat Bouri	Earth & Stone cutting Mazdoor.
36.	Shri Sudara	Do.
37.	Shri Alta	Do.
38.	Shri Indra	Do.
39.	Shri Bodi	Do.
40.	Smt. Chulvi	Do.
41.	Smt. Chhepi	Do.
42.	Shri Mandas	Do.
43.	Shri Monu	Do.
44.	Shri Haru	Do
45.	Smt. Bibi	Do.
46.	Smt. Lakshmi	Do.
47.	Shri Rajendra Ganju	Do.
48.	Shri Khedu Ganju	Do.
49.	Smt. Mustul	Do.
50.	Smt. Sanichariya	Do.
51.	Shri Rosani Ganju	Do.
52.	Shri Basni Sitram	Do.
53.	Shri Handu Souri	Do.
54.	Shri Dasu Bouri	Do.
55.	Smt. Santi	Do.
56.	Smt. Malati	Do.
57.	Shri Kamadu	Do.
58.	Shri Chitan	Do.
59.	Shri Gurpada	Do.
60.	Shri Subhankar	Do.
61.	Smt. Batlla	Do.
62.	Smt. Achala	Do.
63.	Smt. Sabitri	Do.
64.	Shri Chattu	Do.
65.	Shri Bharat	Do.
66.	Smt. Munibala	Do.
67.	Smt. Putki Bouri	Do.
68.	Shri horat	Do.
69.	Shri Nagendra	Do.
70.	Shri Kartik	Do.
71.	Shri Visue	Do.
72.	Shri Sitala	Do.
73.	Smt. Rati	Do.
74.	Smt. Robani	Do.
75.	Shri Chopala	Do.
76.	Shri Dhiren	Do.
77.	Shri Debu	Do.
78.	Shri Jagdish	Do.
79.	Shri Abala	Do.
80.	Smt. Bijala	Do.
81.	Smt. Beli	Do.
82.	Smt. Maru	Do.
83.	Shri Mantu	Do.
84.	Shri Sahadev	Do.
85.	Smt. Reshmi	Do.
86.	Shri Bijala	Do.
87.	Smt. Fulmani	Do.
88.	Shri Khodu Mahato	Do.
89.	Smt. Rosni	Do.
90.	Shri Lobin Das	Do.
91.	Smt. Chori Domin	Do.
92.	Smt. Kamala	Do.

S. No.	Name of the workmen	Designation
93.	Shri Kanailal Dhobi	Earth & Stone Cutting Mazdoor
94.	Smt. Chhobi	Do.
95.	Shri Khetu Mahato	Do.
96.	Shri Dukhan Bouri	Do.
97.	Smt. Bilasi	Do.
98.	Shri Badal Bouri	Do.
99.	Shri Pagal	Do.
100.	Shri Amulya	Do.
101.	Smt. Meni	Do.
102.	Smt. Meputa	Do.
103.	Smt. Kamala	Do.
104.	Smt. Nebu	Do.
105.	Shri Donu	Do.
106.	Shri Kanai	Do.
107.	Shri Tarapadu	Do.
108.	Shri Fatik	Do.
109.	Shri Rasu	Do.
110.	Shri Sakti	Do.
111.	Shri Mantu	Do.
112.	Shri Basu	Do.
113.	Shri Kamal	Do.
114.	Shri Aklu	Do.
115.	Shri Sricharan	Do.
116.	Shri Ghasi Ram Bouri	Do.
117.	Shri Digamber Roy	Do.
118.	Shri Bojoy Bouri	Do.
119.	Shri Babulal	Do.
120.	Shri Gangdhar Singh Choudhary	Sardar
121.	Smt. Paritosh	Earth & Stone Cutting Mazdoor
122.	Shri Bhaderi	Do.
123.	Shri Chaita	Do.
124.	Shri Ganga	Do.
125.	Smt. Manbhula	Do.
126.	Shri Majari	Do.
127.	Shri Satya	Do.
128.	Shri Aklu	Do.
129.	Smt. Adari	Do.
130.	Smt. Latika	Do.
131.	Shri Patu	Do.
132.	Shri Khantu	Do.
133.	Shri Gonu Bouri	Do.
134.	Shri Sulochna	Do.
135.	Smt. Bijala	Do.
136.	Smt. Nepali	Do.
137.	Smt. Pankhi	Do.
138.	Smt. Kapura	Do.
139.	Smt. Bidu	Do.
140.	Smt. Gungni	Do.
141.	Smt. Sukhada	Do.
142.	Smt. Bheli	Do.
143.	Smt. Narada	Do.
144.	Smt. Kausyla	Do.
145.	Shri Bipuli	Do.
146.	Shri Rathu	Do.
147.	Shri Ratim	Do.
148.	Shri Kajala	Do.
149.	Smt. Champa	Do.
150.	Smt. Chadila	Do.
151.	Smt. Birbal	Do.
152.	Shri Chhutu	Earth & Stone Cutting Mazdoor
153.	Shri Badhari	Do.
154.	Shri Basudeo	Do.
155.	Shri Kalaipada	Do.
156.	Shri Manoka	Do.
157.	Shri Gugal	Do.
158.	Shri Sankar	Do.
159.	Shri Bhadi	Do.
160.	Shri Pari	Do.
161.	Smt. Lakhan	Do.
162.	Shri Samal	Do.
163.	Shri Amulya	Do.
164.	Smt. Sakuntala	Do.
165.	Smt. Lalu	Do.
166.	Shri Bhadur	Do.
167.	Shri Turi	Do.
168.	Smt. Baroai	Do.
169.	Shri Lilmoni	Do.
170.	Smt. Phalari	Do.
171.	Shri Chutu	Do.
172.	Smt. Sunsari Domin	Do.
173.	Shri Samla *	Do.
174.	Shri Nebu	Do.
175.	Shri Anil	Do.
176.	Smit. Pemila	Do.
177.	Shri Nebi	Do.
178.	Shri Chandu	Do.
179.	Shri Jagdish	Do.
180.	Smt. Mithila	Do.
181.	Smt Dropan	Do.
182.	Smt. Ashoni	Do.
183.	Shri Lalu	Do.
184.	Smt. Dom	Do.
185.	Smt. Bhalia	Do.
186.	Shri Lalmochan	Do.
187.	Shri Satrughan	Do.
188.	Smt. Dulari	Do.
189.	Shri Abilash	Do.
90.	Shri Gopal	Do.
191.	Shri Sashi	Do.
192.	Smt. Kasani	Do.
193.	Shri Kishan	Do.
194.	Smt. Charl Bourin	Do.
195.	Shri Bhuneshwar Singh Choudhary	Sardar

(No. L-20012/156/75/LR.II/D.III-A)

आदेश

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 1975

का०आ० 5007.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की फुलारितांड कोलियरी के अपर मान्द्रा अनुभाग, डाकघर खरखरी, जिला धनबाद के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है।

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन संगठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण संख्या 2, धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या मैसर्स भारत कोकिंग कोल लि० की फुलारितांड कोलियारी के अपर मान्द्रा अनुभाग, डाकघर खरखरी, जिला धनबाद के प्रबन्धतंत्र की, श्री चेत लाल हरी, झाड़ूकश को 10 जुलाई, 1974 से काम से रोकने की कार्रवाई न्यायोचित है? यदि नहीं, तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है?

[संख्या एल.-20012/25/75/डी० 3ए]

ORDER

New Delhi, the 23rd September, 1975

S.O. 5007.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Upper Mandra Section of Phularitand Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Kharkharee, District Dhanbad and their workman in respect of the matters specified in Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal No. 2 Dhanbad, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the action of the management of Upper Mandra Section of Phularitand Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Kharkharee, District Dhanbad, in stopping Shri Chet Lal Hari, Sweeper, from work with effect from the 10th July, 1974, is justified? If not, to what relief is the said workman entitled?

[No. L-20012/25/75/D. III. A]

आदेश

का०आ० 5008.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की जोयरामपुर कोलियरी, डाकघर खास जीनागोरा, जिला धनबाद के प्रबन्धतंत्र के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7 क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण संख्या 2, धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की जोयरामपुर कोलियरी, डाकघर खास जीनागोरा, जिला धनबाद के प्रबंधतंत्र की, निम्नलिखित कर्मकारों को नियमित न करने की कार्रवाई न्यायोचित है?

1. श्री डोना मुंडा	2. रंगा मुंडा	3. सुंद्री मुंडा
4. गांगी मुंडा	5. गौरी मुंडा	6. श्रीमती मुंडा
7. आदारी बोउरी	8. बहादुर बोउरी	9. अमेला बोउरी
10. भीमजी बोउरी	11. दानी बोउरी	12. साबुना मियां
13. बिसौखा राजवर	14. कपुरा बोउरी	15. हाराधान मुंडा
16. अक्का बोउरी	17. कुजाली देशवाली	18. विजय बोउरी
19. अनेदा बोउरी	20. बिनि कामिन	21. इच्छा कामिन
22. बेदनी बोउरी	23. बुधु बोउरी	24. खांडु बोउरी
25. धाकिना बोउरी	26. अर्जुन बोउरी	27. गौड़ बोउरी
28. साति बोउरी	29. साति लीलामुनी मांझिन	

यदि नहीं, तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं और किन तारीखों से?

[संख्या एल-20012/94/75-डी०-3ए]

एल० के० नारायणन, अनुभाग अधिकारी (विशेष)

ORDER

S.O. 5008.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Jayrampur Colliery, of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Khas Jeenagora, District Dhanbad and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Dhanbad, constituted under section 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the action of the management of Joyrampur Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Khas Jeenagora, District Dhanbad, in not regularising the undermentioned workers is justified?

1. Sri Dona Munda.
2. Ranga Munda.
3. Sundri Munda.
4. Gangi Munda.
5. Gauri Munda.
6. Srimati Munda.
7. Adari Bouri.
8. Bahadur Bouri.
9. Amela Bouri.
10. Bhimji Bouri.
11. Dani Bouri.
12. Sabuna Mian.
13. Bisaukha Rajwar.
14. Kapura Bouri.
15. Haradhan Munda.
16. Akka Bouri.
17. Kujali Deshwali.
18. Bijay Bouri.
19. Aneda Bouri.
20. Bini Kamin.
21. Ichha Kamin.

22. Beedni Bouri.
23. Budhu Bouri.
24. Khandu Bouri.
25. Dhakina Bouri.
26. Arjun Bouri.
27. Gaur Bouri.
28. Sati Bouri.
29. Sati Lilamuni Manjhin.

If not to what relief are the said workmen entitled and from what dates ?

[No. L-20012/94/75/DIIIA]
L. K. NARAYANAN, Section Officer (Spl.)

नई दिल्ली, 15 अक्तूबर, 1975

का०आ० 5009.—कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 13 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना सं० ए-12015(2)/72-पी०एफ० I, तारीख 10 अक्तूबर 1972 को अधिक्रांत करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री आर० के० चोपड़ा को उक्त अधिनियम, स्कीम और उसके अधीन विरचित किसी कुटुम्ब पेंशन स्कीम के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार के या उसके नियंत्रणाधीन किसी स्थापन के संबंध में या किसी रेल कंपनी, महापत्तन, खान या तेल क्षेत्र या नियंत्रित उद्योग से संबंधित किसी स्थापन के संबंध में या किसी ऐसे स्थापन के संबंध में जिसके एक से अधिक राज्य में विभाग या शाखाएं हों, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए निरीक्षक नियुक्त करती है।

[सं० ए०-12016(4)/74-पी०एफ०I]

New Delhi, the 15th October, 1975

S.O. 5009.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), and in supersession of the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. A-12015 (2)/72-PF. I, dated the 10th October, 1972, the Central Government hereby appoints Shri R. K. Chopra to be an Inspector for the whole of the Union Territory of Delhi for the purposes of the said Act, the Scheme and the Family Pension Scheme framed thereunder in relation to any establishment belonging to, or under the control of the Central Government or in relation to any establishment connected with a railway company, a major port, a mine or an oilfield or a controlled industry or in relation to an establishment having departments or branches in more than one State.

[No. A-12016(4)/74-PF. I]

का०आ० 5010.—कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 13 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार श्रीमती के० थंकामणि अम्मा और श्री सी० जे० जोसेफ को उक्त अधिनियम, स्कीम और उसके अधीन विरचित किसी कुटुम्ब पेंशन स्कीम के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार के या उसके नियंत्रणाधीन किसी स्थापन के संबंध में या किसी रेल कंपनी, महापत्तन, खान या तेल क्षेत्र या नियंत्रित उद्योग से संबंधित किसी स्थापन के संबंध में या किसी ऐसे स्थापन के संबंध में जिसके एक से अधिक राज्य में विभाग या शाखाएं हों, सम्पूर्ण केरल राज्य और पाण्डीचेरी संघ राज्य क्षेत्र के माहे क्षेत्र राज्य के लिए निरीक्षक नियुक्त करती है।

[सं० ए-12016(11)/72-पी०एफ०I]

S.O. 5010.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby appoints Shrimati K. Thankamoney Amma and Shri C. J. Joseph to be Inspectors for the whole of the State of Kerala and Mahe area of the Union territory of Pondicherry for the purposes of the said Act, the Scheme and the Family Pension Scheme framed thereunder in relation to any establishment belonging to, or under the control of the Central Government or in relation to any establishment connected with a railway company, a major port, a mine or an oil field or a controlled industry or in relation to an establishment having departments or branches in more than one State.

[No. A-12016/11/72-PF. I]

नई दिल्ली, 30 अक्तूबर, 1975

का०आ० 5011.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स रिंगलसन (इण्डिया) सेल्स कार्पोरेशन, स्टेशन रोड, गोपाल टाकीज के निकट, आनन्द जिला कैरा नामक स्थापन, जिसके अन्तर्गत वीनस एपार्टमेण्ट सी फेस, वाली, मुम्बई-18 स्थित उसकी प्रधान कार्यालय भी आती है से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करता है।

यह अधिसूचना 1974 का मई के इकत्तीसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस०-35019(13)/75-पी०एफ०21 (i)]

New Delhi, the 30th October, 1975

S.O. 5011.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Ringlson (India) Sales Corporation, Station Road, Near Gopal Talkies, Anand, District Kaira, including its Head Office at Venus Apartment Sea Face, Worli, Bombay-18, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the Thirty first day of May, 1974.

[No. S. 35019(13)/75-PF. II(i)]

का० आ० 5012.—केन्द्रीय कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि, अधिनियम 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 31 मई, 1974 से रिंगलासन (इण्डिया) सेल्स कार्पोरेशन, स्टेशन रोड, गोपाल टाकीज के निकट, आनन्द जिला कैरा नामक स्थापन को जिसके अन्तर्गत वीनस एपार्टमेण्ट, सी फेस, वाली, मुम्बई-18 स्थित उसका प्रधान कार्यालय भी आता है, उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[सं० एस०-35019(13)/75-पी०एफ० 2 (ii)]

S.O. 5012.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the 31st day of May, 1974 the establishment known as Messrs Ringlson (India) Sales Corporation, Station Road, Near Gopal Talkies, Anand District, Kaira including its Head Office at Venus Apartment Sea Face, Bombay-18 for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35019(13)/75-PF. II(ii)]

का० आ० 5013.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स शा वल्लास एण्ड कम्पनी लिमिटेड, 84 इण्डस्ट्रियल उपनगर यशवन्तपुर बंगलौर-22 नामक स्थापन से सम्बद्ध हो नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि, और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1974 के अक्तूबर के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० 35019(21)/75-पी०एफ० 2]

एस०एस० सहस्रनामम, उप सचिव

S.O. 5013.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Shaw Wallace and Company Limited, 84, Industrial Suburb, Yeshwantpur, Bangalore-22, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of October, 1974.

[No. S. 35019(21)/75-PF. II]

S. S. SAHASRANAMAN, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 17 अक्तूबर, 1975

का० आ० 5014.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स अजन्ता इण्डस्ट्रीज, मदुराई रोड, का फोर्ड, तिरुचिरापल्ली-12, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1975 की जनवरी, के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस०-35019(78)/75-पी०एफ० 2]

New Delhi, the 17th October, 1975

S.O. 5014.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Ajantha Industries Madurai Road, Crawford, Tiruchirapalli-12, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of January, 1975.

[No. S. 35019(78)/75-PF. II]

का० आ० 5015.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स आटो इन्डस्ट्रीज, अजीत इन्डस्ट्रीयल स्टेट (भाग 1) नागरवेल हनुमान रोड, राखिया, अहमदाबाद, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है।

यह अधिसूचना 1974 के सितम्बर, के तीसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस०-35019(106)/75-पी०एफ० 2]

S.O. 5015.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Auto Industries Ajit Industrial States (Part-I) Nagarvel Hanuman Road, Rakhia, Ahmedabad, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirtieth day of September, 1974.

[No. S. 35019/106/75-PF.II.]

का० आ० 5016.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स भगवती टेक्सटाइल्स सी-36, उद्योग नगर, नवसारी जिला, बलसर नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को एतद्द्वारा लागू करती है।

यह अधिसूचना 1975 की फरवरी के अट्ठाइसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस०-35019(128)/75-पी०एफ० 2]

S.O. 5016.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Bhagwati Textiles C-36, Udyognagar, Navsari District Bulsar have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the twenty-eighth day of February 1975.

[No. S. 35019/128/75-PF. II]

का० आ० 5017.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स नवीन टेक्सटाइल सी०-36, उद्योग नगर, नवसारी जिला बुलसर नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन लागू किए जाने चाहिए,

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1975 की फरवरी के अट्ठाइसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० ए०-35019(138)/75-पी०एफ० 2]

S.O. 5017.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Navin Textile C-36, Udyognagar, Navsari, District, Bulsar, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the twenty-eighth day of February, 1975.

[No. S. 35019(138)/75-PF.II]

का० आ० 5018.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स केपी टेक्सटाइल्स सी०-36 उद्योग नगर नवसारी जिला बुलसर नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1975 की फरवरी के अट्ठाइसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस०-35019(139)/75-पी०एफ० 2]

S.O. 5018.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Kepee Textiles C-36 Udyognagar, Navsari, District Bulsar, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the twenty-eight day of February, 1975.

[No. S. 35019(139)/75-PF-II]

का० आ० 5109.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स पीटीस वाइन स्टोर साउथ जंकशन, अर्नाकुलम, कोचीन-682016, जिसमें अलपेट ज्वेलरी सेन्ट्रल जंकशन, कोटायाम में स्थित उसकी शाखा सम्मिलित है, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1974 के नवम्बर, के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस०-35019(237)/74-पी०एफ० 2]

S.O. 5019.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Peettes Wine Stores, South Junction, Ernakulam, Cochin-682016, including its branch at Aloppat Jewellary, Central Junction, Kottayam, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952, (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of November, 1974.

[No. S. 35019(237)/74-PF. II]

नई दिल्ली, 30 अक्तूबर, 1975

का० आ० 5020.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स दीपक इण्टर प्राइजेज-2-बेबी चौधरी रोड, कलकत्ता-23 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1975 की जनवरी के इकतीसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस०-35017(15)/75-पी०एफ० 2]

New Delhi, the 30th October, 1975

S.O. 5020.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Deepak Enterprises. 2-Devi Chowdhury Road. Cacutta-700023, have agreed that the provisions of the Emloyees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952, (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty-first day of January, 1975.

[No. S-35017(15)/75-PF.II]

का० आ० 5021—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स फरीदाबाद प्रोडक्टिविटि कौंसिल, 32 सी, नेहरू ग्राउन्ड एन० आई० टी० फरीदाबाद, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधी अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है

यह अधिसूचना 1974 के अक्तूबर, के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस०-35019(9)/75पी०एफ०2(i)]

S.O. 5021.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Faridabad Productivity Council, 32-C, Nehru Ground, N.I.T. Faridabad, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act. the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of October, 1974.

[No. S. 35019(9)/75-PF.II(i)]

का० आ० 5022.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि, अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 1 अक्तूबर, 1974 से मैसर्स फरीदाबाद प्रोडक्टिविटी कौंसिल, 32 सी, नेहरू ग्राउन्ड एन० आई० टी० फरीदाबाद नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[सं० एस०-35019(9)/75-पी०एफ०2(ii)]

S.O. 5022.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the first day of October, 1974, the establishment known as Messrs Faridabad Productivity Council, 32-C, Nehru Ground, N.I.T., Faridabad, for the purposes of the said proviso.

[No. S-35019(9)/75-PF.II(ii)]

का० आ० 5023.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स महादेश्वर लारी ट्रांसपोर्ट सं० 126/7–2 पांचवां क्रास कलासीपल्यम, न्यू इक्सटेंशन बंगलौर-2, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1975 की जनवरी के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस०-35019(30)/75-पी०एफ०2(i)]

S.O. 5023.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Mahadeshwara Lorry Transports, No. 126/7-2, 5th Cross Kalasipalyam New Extension, Bangalore-2, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of January, 1975.

[No. S-35019(30)/75-PF.II(i)]

का० आ० 5024.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि, अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 1 जनवरी, 1975 से मैसर्स महादेश्वर लारी ट्रांसपोर्ट, 126/7–2 पांचवां क्रास कलासी पल्यम, न्यू इक्सटेंशन, बंगलौर-2, नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[सं० एस०-35019(30)[75-पी०एफ०2(ii)]

S.O. 5024.—In exercise of the powers conferred by first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the first day of January, 1975, the establishment known as Messrs Mahadeshwara Lorry Transports, 126/7-2 5th Cross, Kalasipalyam New Extension, Bangalore 22, for the purposes of the said proviso.

[No. S-35019(30)/75-PF.II(ii)]

का० आ० 5025.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स सुलतानपुर प्राइमरी को-आपरेटिव लैंड मार्गेज बैंक लिमिटेड सुलतानपुर (कपूरथला) नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1972 के नवम्बर, के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एम०-35019(51)/75-पी०एफ०2(i)]

S.O. 5025.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Sultanpur Primary Co-operative Land Mortgage Bank, Limited, Sultanpur (Kapurthala) have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made appicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of November, 1972.

[No. S. 35019(51)/75-PF.II(i)]

का० आ० 5026.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में आवश्यक जाँच के पश्चात् 1 नवम्बर, 1972 से मैसर्स सुलतानपुर प्राइमरी को-आपरेटिव लैंड मार्टज बैंक लिमिटेड, सुलतानपुर (कपूरथला), नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[सं० एस०-35019(51)/75-पी०एफ०2(ii)]

आर०पी० नरूला, अवर सचिव

S.O. 5026.—In exercise of the powers conferred by the first provise to section 6of the Employees Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the first day of November, 1972, the establishment known as Messrs Sultanpur Primary Co-operative Land Mortgage Bank Limited, Sultanpur (Kapurthala) for the purpose of the said proviso.

[No. S-35019(51)/75-PF.II (ii)]

R. P. NARULA, Under Secy.

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर, 1975

का० आ० 5027.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 2254 तारीख 17 अगस्त, 1974 के अनुक्रम में भारतीय सेल निगम लिमिटेड के गोहाटी संस्थान और पटना संस्थापन को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से, 28 जून, 1975 से 27 जून, 1976 तक, जिसमें वह दिन भी सम्मिलित है, एक और वर्ष की अवधि के लिए छूट देता है।

2. उपर्युक्त छूट निम्नलिखित शर्तों पर है, अर्थात् :—

(1) उक्त कारखाने का नियोजन, उस अवधि की बाबत जिसके दौरान यह कारखाना उक्त अधिनियम के प्रवर्तन के अधीन था, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अवधि कहा गया है), ऐसी विवरणियां ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम (साधारण) विनियम, 1950 के अधीन उक्त अवधि के संबंध में देनी थी;

(2) निगम द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक, या निगम का कोई अन्य पदधारी जो इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो—

(i) धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन उक्त अवधि की बाबत दी गई किसी विवरणी में दी गई विशिष्टियों को सत्यापित करने के प्रयोजनार्थ; या

(ii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि क्या उक्त अवधि की बाबत कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 द्वारा क्या अपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख रखे गए थे, या

(iii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि क्या कर्मचारी, नियोजक द्वारा नकदी और वस्तु के रूप में दिए जाने वाले उन फायदों को पाने का अब भी हकदार बना हुआ है जिनके प्रतिफलस्वरूप इस अधिनियम के अधीन छूट दी जा रही है; या

(iv) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि क्या उस अवधि के दौरान जब उक्त कारखाने के संबंध में अधिनियम के उपबन्ध प्रवृत्त थे, ऐसे उपबन्धों का अनुपालन किया गया था,

निम्नलिखित के लिए सशक्त होगा, अर्थात् :—

(क) प्रधान या अव्यवहित नियोजक से अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी सूचनाएं दे जो उपरोक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी द्वारा आवश्यक समझी जाएं; या

(ख) ऐसे प्रधान या अव्यवहित नियोजक के अधिभोगाधीन किसी कारखाने स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसरों में किसी युक्तियुक्त समय पर प्रवेश करना और ऐसे व्यक्ति से जो उसका भारसाधन कर रहा हो, यह अपेक्षा करना कि वह ऐसे निरीक्षक या पदधारी के समक्ष ऐसी लेखा बहियां और अन्य दस्तावेजों जो, व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के संदाय से संबंधित हों, को प्रस्तुत करे, और उसे उनकी परीक्षा करने दे या उन्हें जैसी वे आवश्यक समझें वैसे जानकारी दे; या

(ग) प्रधान या अव्यवहित नियोजक, उसके अभिकर्ता या सेवक, या किसी ऐसे व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसरों में पाया जाएगा जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करण का युक्तियुक्त कारण है कि वह व्यक्ति कर्मचारी है, परीक्षा करना या

(घ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर, लेखाबही या अन्य दस्तावेज की नकल तैयार करना या उसमें से कोई उद्धरण उतारना।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

इस मामले में छूट को पूर्वापेक्षी प्रभाव देना आवश्यक हो गया है, क्योंकि कारखाने को छूट स्वीकृत करने के संबंध में महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम की सिफारिश देर से प्राप्त हुई थी। तथापि यह प्रमाणित किया जाता है कि जिन परिस्थितियों में कारखाने को आरम्भ में छूट स्वीकृत की गई थी, वे अभी तक विद्यमान है और कारखानों

छूट का पात्र है यह भी प्रमाणित किया जाता है कि पूर्वापेक्षी प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[सं० एस० 38017/1/73-एच० 1]

New Dehli, the 21st October, 1975

S.O. 5027.—In exercise of the powers conferred by section 87 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 2254 dated the 17th August, 1974, the Central Government hereby exempts the Gauhati Installation and Patna Installation of the Indian Oil Corporation Limited from the operation of the said Act for a further period of one year with effect from the 28th June, 1975, upto and inclusive of the 27th June, 1976.

2. The above exemption is subject to the following conditions, namely :—

(1) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 ;

(2) Any inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act, or other Official of the Corporation authorised in this behalf shall for the purposes of—

(i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 of the said period ; or

(ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period; or

(iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification ; or

(iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act had been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory.

be empowered to—

(a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary ; or

(b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found incharge thereof to produce to such Inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary ; or

(c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or any persons found in such factory, establishment, office or other premises, or any person whom the said Inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee ; or

(d) make copies of or take extracts from any register, account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises.

EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case, as the recommendation of the Director General, Employees State Insurance Corporation for the grant of exemption to the factory was received late. However, it is certified that the condiions under which the factory was initially granted exemption still persist and the factory is eligible for exemption. It is also certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of anybody adversely.

[No. S. 38017(1)/73-HI]

का० आ० 5028.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 2253, तारीख 17 अगस्त, 1974 के अनुक्रम में केन्द्रीय नेशनल इन्स्ट्रूमेन्टस लिमिटेड, कलकत्ता को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से, 13 नवम्बर, 1974 से 12 नवम्बर, 1975 तक, जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, एक वर्ष की और अवधि के लिए छूट देता है।

2. पूर्वोक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन है, अर्थात् :—

(1) उक्त कारखाने का नियोजक, उस अवधि की बाबत जिसके दौरान यह कारखाना उक्त अधिनियम के प्रवर्तन के अधीन था, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अवधि कहा गया है), ऐसी विवरणियां ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो उसे कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के अधीन उक्त अवधि के संबंध में देनी थी।

(2) निगम द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक, या निगम का कोई अन्य पदधारी जो इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो :—

(i) उक्त अवधि की बाबत धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन दी गई किसी विवरणी में अन्तर्विष्ट विशिष्टियों को सत्यापित करने के प्रयोजनार्थ; या

(ii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि क्या उक्त अवधि की बाबत, कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 द्वारा यथापेक्षित रजिस्टर और अभिलेख रखे गए थे; या

(iii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि क्या कर्मचारी, नियोजक द्वारा नकदी और वस्तु के रूप में दिए जाने वाले उन फायदों को पाने के अब भी हकदार हैं जिनके प्रतिफल स्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है; या

(iv) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि क्या उस अवधि के दौरान जब उक्त कारखाने के संबंध में अधिनियम के उपबन्ध प्रवृत्त थे, ऐसे उपबन्धों का अनुपालन किया गया था, निम्नलिखित के लिए सशक्त होगा कि वह—

(क) प्रधान या अव्यवहित नियोजक से यह अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी सूचनाएं दे जो उपरोक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी द्वारा आवश्यक समझी जाए; या

(ख) ऐसे प्रधान या अव्यवहित नियोजक के अधिभोगाधीन किसी कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसरों में किसी युक्तियुक्त समय पर प्रवेश करना और ऐसे व्यक्ति से जो उसका भारसाधन कर रहा हो, यह अपेक्षा करना कि वह ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष लेखाबहियां और अन्य दस्तावेजें, जो व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के संदाय से संबंधित हों,

प्रस्तुत करें और उसकी परीक्षा करने दे या उन्हें जैसी वे आवश्यक समझें वैसी जानकारी दें; या

(ग) प्रधान या अव्यवहित नियोजक उसके अभिकर्ता या सेवक या किसी ऐसे व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसरों में पाया जाए या जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह कर्मचारी है, परीक्षा करना; या

(घ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर लेखाबही, या अन्य दस्तावेज की नकल तयार करे या उससे उद्धरण उतारना।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

इस मामले में छूट को पूर्वापेक्षी प्रभाव देना आवश्यक हो गया है क्योंकि कारखाने का छूट प्रदान करने के लिए महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम की सिफारिश देर से प्राप्त हुई थी। तथापि, यह प्रमाणित किया जाता है कि वे परिस्थितियां, जिन में कारखाने को मूल रूप में छूट प्रदान की गई थी, अभी तक भी जारी हैं और कारखाना छूट के लिए पात्र है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि पूर्वापेक्षी प्रभाव से छूट की मंजूरी किसी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

[सं० एम० 38017/61/74 एच० 1]

S.O. 5028.—In exercise of the powers conferred by section 87 of the Employees' State Insuance Act, 1948 (34 of 1948) and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 2253, dated the 17th August, 1974, the Central Government hereby exempts the National Instruments Limited, Calcutta, from the operation of the said Act for a further period of one year with effect from the 13th November, 1974 upto and inclusive of the 12th November, 1975.

2. The above exemption is subject to the following conditions, namely :—

(1) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the period under the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 ;

(2) Any inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act, or other Official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purposes of —

(i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period ; or

(ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period ; or

(iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification ; or

(iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act had been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory,

be empowered to —

(a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary ; or

(b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found incharge thereof to produce to such Inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary ; or

(c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or any person found in such factory, establishment, office or other premises, or any person whom the said Inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee ; or

(d) make copies of or take extracts from, any register, account book or other document maintained in such factory, estabishment, office or other premises.

EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case, as the recommendation of the Director General, Employees' State Insurance Corporation for the grant of exemption to the factory was received late. However, it is certified that the conditions under which the factory was initially granted exemption still persist and the factory is eligible for exemption. It is also certified that the grant of exemption with retrospective effect will not effect the interest of anybody adversely.

[No. S-38017/6/74-HI]

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 30 अक्तूबर, 1975

का० आ० 5029.—भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) तारीख 10 मई, 1975 में पृष्ठ 1784 पर प्रकाशित भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 1464 तारीख 26 अप्रैल, 1975 में पंक्ति 4 और 19 में आये हुए श्रीमति प्रतिभा डी० पटेल" के स्थान पर" श्रीमति प्रतिभा डा० पाटिल" पढ़ें।

[फा०सं०यू० 16012/15/74-एच०आई०]

जे० सी० सक्सेना, अवर सचिव

CORRIGENDUM

New Delhi, the 30th October, 1975

S.O. 5029.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 1464 dated the 26th April, 1975, published at page 1784 of the Gazette of India, Para II, section 3, sub-section (ii) dated the 10th May, 1975, —

for "Shrimati Pratibha D. Patel" and "Smt. Pratibha D. Patel", "occuring in lines" and 19 respectively, read "Shrimati Pratibha D. Patil" and "Smt. Pratibha D. Patil" respectively.

[F. No. U.16012/15/74-HI]

J. C. SAXENA, Under Secy.

(Department of Labour and Employment)

New Delhi, the 10th November, 1975

S.O. 5030.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Industrial Tribunal, No. 2 Dhanbad in the industrial dispute between the

employers in relation to the management of Jamadoba 3 & 4 Pits Colliery of M/s. Tata Iron & Steel Co., Ltd., P. O. Jamadoba, Distt Dhanbad and their workmen, which was received by the Central Government on the 30th October, 1975.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD.

PRESENT

Shri K. K. Sarkar, Judge,

Presiding Officer.

REFERENCE NO. 100 OF 1975

In the matter of an industrial dispute under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947.

(Ministry's Order No. L-20012/125/75/D.IIIA dated 7th August, 1975).

PARTIES :

Employers in relation to the management of Jamadoba 3 & 4 Pits Colliery of M/s. Tata Iron and Steel Co. Ltd., Jamadoba, P. O. Jamadoba, Dist. Dhanbad.

AND

Their workmen.

APPEARANCES :

On behalf of the employers : Shri S. S. Mukherjee, Advocate.

On behalf of workmen : Shri C. P. Rai Sharma, Vice President, R. C. M. S. Jamadoba Branch.

State : Bihar. Industry : Coal.

Dhanbad, the 25th October, 1975

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour made a reference to this Tribunal for adjudication of the industrial dispute involved with the following issues framed :—

"1. Whether the action of the management of Jamadoba Colliery of M/s. Tata Iron & Steel Co. Ltd., P. O. Jamadoba, Dist. Dhanbad in superannuating Smt. Saraswatia, Mason Kamin, Ticket No. 26440, from service w.e.f. 15th March, 1975 is justified?

2. If not, to what relief is the worker entitled ?".

Before this reference could proceed, a memorandum of settlement was filed before me by the parties jointly. I heard the parties on the memorandum of settlement and it is submitted by both sides that they have amicably arrived at a settlement and it is prayed that an award be passed in terms of the settlement. It is further submitted that passing of an early award will enable the parties to implement the terms of the settlement immediately. On the side of the employers M/s. Tata Iron & Steel Co. Ltd., the settlement is signed by their authorised advocate Shri S. S. Mukherjee and on the side of the workmen it has been signed by Shri C. P. Rai Sharma who is the Vice President of the Union on record, C.M.S. Jamadoba Branch. The left thumb impression of the concerned worker Smt. Saraswatia is also there in the memorandum of settlement. Terms of the settlement appear to be fair and beneficial to both sides and therefore I accept the same.

In the result, I pass an award in respect of the industrial dispute involved as referred to me in terms of the memorandum of settlement which do form part of my Award as Annexure-A.

K. K. SARKAR, Presiding Officer.

ANNEXURE—A

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. II, DHANBAD.

Reference No. 100 of 1975

In the matter of Notification No. L-20012/125/75/D. III-A.

Employers in relation to the Management of Jamadoba 3 & 4 pits colliery of M/s. Tata Iron & Steel Co. Ltd. Jamadoba, Post Jamadoba, District Dhanbad.

Their workmen

A dispute has been referred to the Hon'ble Tribunal for adjudication vide the above notification. In this connection both the parties abovenamed beg to submit as under :—

1. After discussion the above dispute referred for adjudication has been amicably settled between the parties on the following terms and conditions :

(a) Smt. Saraswatia, Mason Kamin, Jamadoba colliery will be referred to the Company's Medical Board to ascertain her age and the decision of the said Board will be final and binding on both the parties.

(b) In case the above Medical Board finds that Smt. Saraswatia is less than 60 years of age, she would be reinstated in her job with continuity of service.

(c) As regards the period of her idleness from the date of her superannuation to the date of her re-instatement, she will be paid 50 per cent of the wages payable to her in the said period.

(d) The above period of her idleness would be treated as if she was on leave without wages for the purpose of her eligibility of leave and other benefits, if any.

(e) That in case the Medical Board opines that the age of Smt. Saraswatia is 60 years or above she will have no claim for re-instatement or any compensation.

(f) That the above terms of settlement finally resolves the dispute between the parties and there remains no dispute for adjudication by the Hon'ble Tribunal.

It is, therefore, humbly prayed that the above terms of settlement may kindly be accepted and an Award passed in terms thereof.

For Employers,
M/s. Tata Iron & Steel Co. Ltd.,
At & P. O.—Jamadoba,
Dist.—Dhanbad,

For workman,

1. Vice-President,
R.C.M.S., Jamadoba Branch.

2. L.T.I. of
Smt. Saraswatia.

[F. No. L-20012/125/75-DIII-A]

S.O. 5031.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Industrial Tribunal, (No. 2) Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Kedla Colliery, P.O. Hazaribagh, Distt. Hazaribagh and their workmen which was received by the Central Government on the 30th October, 1975.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (No. 2), DHANBAD

PRESENT

Shri K. K. Sarkar, Judge,

Presiding Officer.

REFERENCE NO. 13 of 1974

In the matter of an industrial dispute under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947.

(Ministry's Order No. L-2012/135/73-LR. II dt. 13-2-74)

PARTIES :

Employers in relation to the management of Kedla Colliery, P.O. Hazaribagh, Dist. Hazaribagh,

AND

Their Workmen

APPEARANCES :

On behalf of the employers : Shri B. Joshi, Advocate.
On behalf of the Workmen : Shri P. K. Bose, Advocate.
State : Bihar Industry : Coal

Dhanbad, dated the 23rd October, 1975

AWARD

This is a reference which was sent by the Government of India, Ministry of Labour to this Tribunal for adjudication of the industrial disputes involved, with the following issues framed :

(1) Whether the action of the management of Kedla Colliery, Post Office Hazaribagh, District Hazaribagh in fixing the monthly basic pay of Shri S. G. Singh, Overman, employed in Block No. 41, at Rs. 265/- in the scale of pay of Rs. 245-10-305-15-440 from the 4th November, 1972 is justified ?

(2) If not, to what relief is the workman entitled ?

2. The short case of the workmen is that Shri S. G. Singh the concerned workmen should be paid @ Rs. 335/- per month basic in the scale of Rs. 305-15-395-20-575 from 4-11-1972 and for payment of difference of pay as between Rs. 335/- and Rs. 265/- in which he was placed by the management. The management who is the Receiver in respect of the Colliery opposes the claim of the workman. They deny that the concerned workman was ever placed @ Rs. 335/- basic in the scale alleged.

3. Admittedly Kedla Colliery with some other collieries belonged to Bokaro and Ramgarh Ltd. On 10-10-1969 in a civil suit the State of Bihar was appointed as Receiver in respect of the above colliery and other collieries and the services of the workmen hithertobefore working under Bokaro and Ramgarh Ltd. was transferred to the Receiver. On 1-12-1970 the concerned workman was appointed as Mining Sirdar under the Coal Wage Board Recommendations. The State of Bihar as Receiver appointed Managing Contractors to carry on the mining operations and in the month of March, 1972 the concerned workman was transferred to one Madan Sukla who was the Managing Contractor of Block No. 16 of Kedla Colliery. While working under the Managing Contractor the concerned workman passed Overmanship examination and the managing Contractor appointed him as an Overman. Subsequently the Managing Contract system was abolished and the concerned workman among others was brought within the fold of the Receiver's services. The Receiver fixed the concerned workman @ Rs. 265/- basic after giving two increments in the scale of Rs. 245-10-305-15-440. The point of dispute is what basic pay the concerned workman was getting under the Managing Contractor Madan Sukla as an Overman and what was the scale there ? Workmen contend that under the Managing Contractor, Madan Sukla the concerned workman was getting a basic pay of Rs. 335/-. This is disputed by the management of the Receiver. It remains to be seen what evidence has the workman adduced in support of his claim. The concerned workman was examined as W.W. 1 and his evidence is that he was appointed as an Overman on a basic salary of Rs. 335/- by the Managing Contractor. It appears that the management has not specifically denied the above basic pay as alleged by the workmen. Their case is that if the concerned workman was appointed as an Overman on a basic salary of Rs. 335/- by the Managing Contractor it was just a collusive affairs and the concerned workman could not have been fixed in the grade of Senior Overman. The evidence of the management's witness viz. Shri N. N. Jha who was an Agent of the Receiver (M.W. 1) and evidence of B. B. Lal who was also an Agent at the Receiver (M.W. 2) is not helpful, in that they do not deny that the basic pay of the concerned workman was Rs. 335/-. So the evidence of the concerned workman W.W. 1 remains that he was getting basic salary of Rs. 335/- under the Receiver. I am not of course wholly depending upon the uncorroborated evidence of the concerned workman alone but looking to other facts and circumstances available on record. The workmen have produced photostat copy of an application made by the concerned workman to the Superintendent of the Kedla Colliery which bears some notes of some officers of that colliery and the same is Ext. 2. According to him endorsement with signature of the manager Shri M. P. Singh and also the endorsement with signature of the Superintendent Shri D. C. Sharma appear in Ext. W. 2. He also says in his evidence that there is also an endorsement with signature of the Agent Shri K. N. Pandey and also endorsement with signature of Shri P. P. Singh, Personnel Officer. It is not satisfactorily challenged before me from the side of the management that the endorsements in Ext. W. 2 do not belong to the persons as named by the concerned workman. The first endorsement by the officers of the Company is like this : "From perusal of the records it can be seen that the applicant was working as Overman in BN 16 colliery at the basic of Rs. 335/- per month. As at the time of transfer to departmental mine he was not told that the basic will be reduced, I feel he should get Rs. 335/- basic on which he is working for last one year in the scale of Rs. 245—450". The other endorsement of Shri D. C. Sharma said to be the Superintendent is as follows : "T. K. To do the needful as per direction of Shri M. P. Singh with approval of Agent under Mines Rules". The third endorsement in Ext. W. 2 by Shri K. N. Pandey said to be Agent is as follows : P.O. to please enquire as to what is the scale of pay of 1. Shri K. P. Singh, Overman Block 3; 2. Shri Nagina Singh Block 9; 3. Shri Dwarka Prasad Singh, Overman...". The last endorsement in Ext. W. 2 which is of Shri P. P. Singh said to be Personnel Officer is as follows :". S.O.C. Sir. I inquired pay sheet and found that the basic scale of Shri K. P. Singh is Rs. 335/- only, the basic of Shri Nagina Singh is Rs. 335/- and the basic scale of Dwarka Singh, Overman is Rs. 340/- only. So it will appear from the endorsements above the Company on perusal of records that the applicant was working as an Overman in Block No. 16 colliery at basic pay of Rs. 335/- per month and it is further stated therein that as at the time of transfer to departmental management he was not told that the basic will be reduced, he concerned workman should get Rs. 335/- basic in which he is working for the last one year in the scale of Rs. 245/- — 440/-. It further appears from the endorsement that other persons viz. Shri K. P. Singh, Shri D. P. Singh and another person were also working as Overman under the Managing Contractor and they were all getting basic pay of Rs. 335/- each. It is, therefore, very much patent from Ext. W. 2 and the endorsements thereon that the concerned workman was getting a basic pay of Rs. 335/- as an Overman under the Managing Contractor. The evidence of the concerned workman together with the facts appearing from Ext. W. 2 and the unsatisfactory nature of the evidence of the management witness in this respect can only lead me to believe that the concerned workman was getting a basic pay of Rs. 335/- under the Managing Contractor where he was an Overman. The case of the management appears to be that the concerned workman could not have been given the basic pay of Rs. 335/- by the Managing Contractor which was a collusive affair. No such evidence about collusion comes before the Court nor there is sufficient material for me to hold that the Managing Contractor could not have fixed him on Rs. 335/- basic. When the Managing Contractor who was owner of the colliery for all practical purposes at the relevant time gave the concerned workman a basic pay of Rs. 335/-, there might have been some reasons behind and it will be idle now to speculate on that. So this part of the case of the workmen that the concerned workman

was getting a basic pay of Rs. 335/- under the Managing Contractor stands proved. The next question that comes up is what was the scale of pay given to the concerned workman by the Managing Contractor, Was it Rs. 245-10-305-15-440 or Rs. 305-15-395-20-575 ? It is also for the workman to prove that he was enjoying the scale of Rs. 305-15-395-20-575 as alleged by him under the Managing Contractor. It appears that apart from the written statement the workmen have not stated elsewhere that the scale which the concerned workman was enjoying under the Managing Contractor was Rs. 305-15-395-20-575. Averment of a party in the written statement is no proof unless such averment is admitted by the other side in their pleadings. As I have already stated, it is for the workmen to prove what scale he was enjoying under the Managing Contractor. I search in vain the evidence of the concerned workman to find that under the Managing Contractor he was enjoying the scale of Rs. 305-15-395-20-575. The most important document on which the workmen rely viz. Ext. W. 2 does not also disclose anywhere that the concerned workman was enjoying the scale of Rs. 305-15-395-20-575 under the Managing Contractor. Ext. M. 3 is the letter from the concerned workman dated 23-11-1973 to the Superintendent of Kedla Colliery demanding difference of wages and in this letter also the concerned workman never alleges that he was enjoying the scale of Rs. 305-15-395-20-575 under the Managing Contractor. On the other hand if Ext. W. 2 on which the workman relies most is any guide, it shows that he was enjoying the scale of Rs. 245-10-305-15-440 under the Managing Contractor. I may quote the last sentence of the first endorsement in Ext. W. 2 which is "I feel that he should get Rs. 335/- basic which he was getting for last one year in the scale of Rs. 245—440". Another fact which may appear to be of some importance is that the concerned workman was getting Rs. 335/- basic under the Managing Contractor and I have accepted it and, there is nothing to disbelieve it. The question remains that Rs. 335/- is a stage in the scale of Rs. 305-15-395-20-575 and so the question remains whether it can be said on the strength of this that the concerned workman was in the scale of Rs. 305-15-395-20-575. I think it will be only surmises and conjectures if we are to accept that the concerned workman was in the scale of Rs. 305—575 simply because he was getting the basic pay of Rs. 335/-. May it be noted here that Rs. 335/- is also a stage in the scale of Rs. 245-10-305-15-440. What will be more reasonable for me to hold which of the two scales he was actually enjoying under the Managing Contractor ? Ext. W. 2 comes to our help in this respect and I may say again that the workman places much reliance on Ext. W. 2. They rely on the endorsements of the Officers on Ext. W. 2. If the endorsements of the officers are to be accepted I think they should be accepted as a hole and not in part. Even at the cost of reiteration I may say that the last sentence of the first endorsement in Ext. W. 2 shows that the concerned workman was in the scale of Rs. 245—440. So analysing the evidence as a whole it would appear that the workmen have not been successful in establishing their case that the concerned workman was in the scale of Rs. 305-15-395-20-575 under the Managing Contractor. They have however been successful to establish that under the Managing Contractor the concerned workman was in receipt of basic pay of Rs. 335/-. There is nothing more on record to be taken into consideration for our purpose. The matter does not end there. On the facts as accepted by me, the question remains if the management is obliged to give the concerned workman a starting basic salary of Rs. 335/- and if thve are obliged to give him the scale of Rs. 305-15-395-20-575. Now, the matter revolves in the same orbit i.e. from the Receiver to his Managing Contractor and from the Managing Contractor to the Receiver. The Managing Contractor had a legal entity and they paid him basic Rs. 335/-. So long a man was getting certain pay in a particular job, his pay cannot and should not be reduced if posted in the same job. So the Receiver was not justified to reduce his pay to Rs. 265/- from Rs. 335/- which he was getting under the Managing Contractor. With regard to the alleged scale under the Managing Contractor, it has not been proved. The scale of Rs. 305-15-395-20-575 is a scale attached to Senior Overman or Head Overman. It has not been proved that the concerned workman was a Senior Overman or Head Overman under the Managing Contractor. So the workmen have not been able to prove that he should be placed in the senior Overman scale viz., 305-15-395-20-575. In view of all that has been said above, the management was justified in placing him in the scale of Rs. 245-10-305-15-440. The workman has filed a calculation about the difference of wages he is entitled to and it does not appear that the management has challenged the accuracy of the calculation. On computation by this Court the same result follows.

4. In the result, the action of the management of the Kedla Colliery, P.O. Hazaribagh, District Hazaribagh in fixing the monthly basic pay of Shri S. G. Singh, Overman employed in Block No. 41, at Rs. 265/- is not justified. The action of the management in fixing the concerned workman in the scale of pay of Rs. 245-10-305-15-440 from 4th November, 1972 is found not unjustified. The concerned workman is, therefore, entitled to receive from the opposite party management a total sum of Rs. 5,387.91 as difference of wages.

This is my award.

K. K. SARKAR, Presiding Officer.

[F. No. L-2012/135/73-LR. II]

G. C. SAXENA, Under Secy.

New Delhi, the 12th November, 1975

S.O. 5032.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal Jaipur, in the industrial dispute between the employers in relation to the Central Bank of India and their workman, which was received by the Central Government on the 1st November, 1975.

CENTRAL INDUSTRIAL TRIBUNAL
PRESENT

SHRI UPDESH NARAIN MATHUR

JUDGE

Case No. I.T. 2 of 1974.

Workmen, Central Bank of India, Ambala Cantt. ... Applicant

Vs.

The Central Bank of India, Sansar Chandra Road,

Jaipur ... Opposite party.

APPEARANCES

For the applicant—none.

For the Opposite Party—Shri D. N. Sharma.

Date of Award—25-9-1975.

AWARD

The Central Government had made the following reference vide No. L. 12011/23/73/IR. III dated 25-5-1974 for adjudication to this tribunal :—

> "Whether the demand of category 'C' Head Cashier in the Central Bank of India to be classified as category 'E' Head Cashiers with effect from the 1st March, 1969 in offices of the Bank in Rajasthan is justified on the basis of such change affected in other divisions of the same Zonal office. If not to what relief are they entitled ?"

The statement of claim was filed on behalf of All India Central Bank Staff Federation on 9-10-1974. The reply to the statement was filed on 26th April, 1975. The case was then fixed up on 2-6-1975 for the filing of documents. But on that date no body represented the federation. The case was, therefore adjourned to 10-7-1975. On that date too nobody appeared on behalf of the Federation. Again on 25-9-1975 the next date of hearing the Federation remained un-represented. It appears that the federation is not interested in getting the reference decided. In view of this a no dispute award is passed.

UPDESH NARAIN MATHUR, Judge

[No. L-12011/23/73 LR. III]

S.O. 5033.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal Jaipur in the industrial dispute between the employers in relation to the Punjab National Bank

and their workmen, which was received by the Central Government on the 1st November, 1975.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, RAJASTHAN, JAIPUR

Case No. DIT-6 of 1974

In the Matter of an Industrial Dispute

BETWEEN

The All India Punjab National Bank Employees Association, Delhi,

AND

THE PUNJAB NATIONAL BANK LIMITED, JAIPUR.

APPEARANCES :

For the Union—Shri B. L. Bhardwaj.

For the Management—Shri Ramesh Lal.

Date of Award—16-10-1975.

AWARD

The Central Government by its order No. L. 12012/6/74/LR. III, dated 27th November, 1974 have made the following reference to this Tribunal for adjudication :—

1. Whether the action of the management of Punjab National Bank in terminating the services of Shri Ram Singh, son of Shri Shyam Singh, Part-time Waterman, Branch Office, Jaipur with effect from the 24th October, 1972 is justified ? If not, to what relief is he entitled ?

2. Whether Shri Ram Singh has been paid for his services rightly in terms of the Awards and Settlements applicable to Punjab National Bank during his service from April, 1968 to October, 1972 ? If not, to what relief is he entitled ?"

The statement of claim was filed on behalf of All India Punjab National Bank Employees Association and the Association of the P.N.B.E. Rajasthan State. Before a reply on behalf of the management of the bank could be filed, the parties filed a settlement arrived at between them with the request that a no dispute award be passed. Hence a no dispute award is accordingly passed.

U. N. MATHUR, Presiding Officer,

[No. L-12012/6/74-LR. III]

S.O. 5034.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Jaipur in the industrial dispute between the employers in relation to the Punjab National Bank and their workmen, which was received by the Central Government on the 5th November, 1975.

CENTRAL INDUSTRIAL TRIBUNAL

Case No. C. I. T. 11 of 1972

IN THE MATTER OF AN INDUSTRIAL DISPUTE

All India Punjab National Bank. Employees Association, Delhi.—Applicant.

Vs.

Punjab National Bank, Central Circle, Indore, Jaipur Region—Opposite Party.

APPEARANCES :

For the Applicant—Shri Chamanlal Bhardwaj.

For the Opposite Party—Shri Ramesh Lal.

Date of Award—4-9-1975.

AWARD

The Central Government have made the following reference to this Tribunal vide No. L. 12012/44/72/I.RIII dated 2nd Nov., 1972:—

"Whether the action of the management of Punjab National Bank, Central Circle, Indore in denying officiating chances in the post of Cashier to Shri Shyamlal, Hundi Presenter (now designated as Bill Collector-cum-Cash Peon), Branch Office, Jaipur is justified? If not, to what relief is he entitled?"

The statement of claim has been filed on behalf of All India Punjab National Bank Employees Association. It has been alleged in the statement of claim that Shyamlal joined as a Peon at Jaipur Branch with effect from 21-11-44. He was promoted and posted as Hundi Presenter w.e.f. 8-8-61 and under the First Bipartite Settlement dated 19-10-66 his designation was changed to that of Bill Collector-cum-Cash Peon. It is admitted that Shyam Lal is Non-Matriculate and in terms of D. M. Central Circle, Indore, Internal Circular No. DMC/STP/21 dated 10-5-67, Shri Shyamlal was allowed to officiate as Assistant Cashier in stop-gap arrangement w.e.f. 20-8-69 onwards. The details are given in para 2(c). The above mentioned circular of 10-5-67 has been quoted as under :

"According to our existing instructions, Hundi Presenters are allowed officiating chances to work in place of cashier staff only. It has, however, been decided that Hundi Presenters who are Matriculate or Intermediate **may also** be allowed chances to officiate in the clerical vacancies also".

It is alleged that in utter violation of the decision the management abruptly denied officiating chance to Shyamlal w.e.f. October, 1971. It is further stated that from February 70 Shyamlal was officiating as a Cashier against a permanent sanctioned vacancy and was entitled to be promoted and posted as such against that vacancy. It is now prayed on behalf of the Association that the management be advised to allow officiating chance to Shri Shyamlal on the post of cashier w.e.f. the date he was denied to do so.

In reply on behalf of the management of the Punjab National Bank, Jaipur Region, it is admitted that Shyamlal was promoted as Hundi Presenter w.e.f. 1-1-62. It is submitted that as in other banks, members of subordinate staff were not allowed to officiate on any clerical cadre. It was towards the end of 1966 that the management decided to consider the cases of Matriculate Peons only for giving them promotion to the post of clerks and also to allow them officiating chances to work in clerical cadre. Accordingly instructions were issued on 3-11-66 to all the Regional Heads to consider the cases of only such peons who had at least four years service in the bank after passing matriculation examination. The position was clarified in the circular dated 10-5-57 by the management. It is stated that since Shyamlal is Non-Matriculate he was not eligible either for promotion or officiating chance as per Bank rules. It is admitted that he was allowed officiating chance to work as cashier, but this was done inadvertently and when this fact came to the notice of the higher authorities it was discontinued.

It is denied on behalf of the management that Shyamlal was officiating as a cashier from February 1970 against a permanent sanctioned vacancy. It is submitted that he was allowed officiating chance by the Branch Manager in Stop-gap-arrangement only under mis-interpretation of the instructions on the subject. It is submitted that no relief may be granted to Shyamlal.

In evidence the statement of the concerned workman Shyam lal was recorded while in rebuttal the statement of Shri Rameshlal, Manager, Punjab National Bank, Jaipur was recorded on behalf of the Management. Arguments were heard.

The facts as narrated above are admitted in so far as Shyamlal was allowed officiating chance to work as Assistant Cashier or Cashier whenever vacancy occurred.

The only point for consideration is whether the instructions issued by the management which are placed on record by both the parties may be so interpreted as to discontinue allowing officiating chance to Non-Matriculate Hundi Presenters. The two circulars have been filed on behalf of the management which are admitted by the workmen's association also. The first is circular No. 111/66 dated 9-11-66. Now according to the submission made on behalf of the management only matriculate persons who have at least 4 years service in the bank at their credit after passing the Matriculation Examination and are reported to have picked up working knowledge of clerical work are to be considered to the post of clerks. It is submitted that the position has been further clarified in the Internal Circular which is Annexure 'A' filed with the statement of claim by the association. It is submitted that since Shri Shyamlal does not fulfil the qualifications laid down in the two circulars he should not be allowed officiating chance further. On behalf of the association it is argued that the earlier circular No. 111/66 of 9-11-66 does not apply to Shyamlal. The said circular is meant for matriculate peons only. It does not refer to Hundi Presenters whether Matriculate or Non-Matriculate. It is the other circular, Annexure 'A' which gives instructions regarding Hundi Presenters. It is the submission on behalf of the association that so far, Hundi Presenters were allowed officiating chance to work in place of cashier staff only. Later on according to this Circular Hundi Presenters who were Matriculate or Intermediate were allowed to officiate in the clerical vacancies also. It is argued that according to this circular Shyamlal could not be allowed to officiate on the clerical post because of his non-matric qualification, but he could continue to officiate on cashier staff even though he was non-matric.

I have given my considerate thoughts over the arguments put forward by the Representatives of the parties and agree with the submission made by the Representatives of the workers association. The circular No. 111/66 dated 9-6-66 does not say anything about the Hundi Presenters. It relates to the Matriculate peons only who were to be given officiating chance on clerical posts. A perusal of the contents of this circular would show that it deals with the peons only and the branches of the bank are directed to consider the cases of such peons who are eligible to officiate on clerical posts. The other circular Annexure 'A' while refering to the earlier circular No. 111/66 which, as stated above, relates to matriculate peons only, has dealt with Hundi Presenters also. In the second paragraph of this circular it has been clearly stated that according to the then existing instructions Hundi Presenters are allowed officiating chance to work in place of cashier staff only. It shows that the existing instructions referred to in this paragraph did not put any restrictions on Non-Matriculate Hundi Presenters to officiate on cashier staff, and now this circular has made Hundi Presenters who are Matriculate or Intermediate, eligible to officiating in the clerical vacancies also. This clarifies that Non-Matriculate Hundi Presenters could officiate on posts of cashier staff but not on clerical posts. The circular nowhere says that Non-Matriculate Hundi Presenters could not henceforth be allowed to officiate in place of cashier. No other instructions or circular has been filed according to which a Non-Matriculate Hundi Presenter was not allowed to officiate as Assistant Cashier or Cashier.

In my opipion therefore the contention of the Representative of the management that according to Annexure 'A' Shyamlal was not eligible to officiate on the post of Assistant Cashier or Cashier, is not correct. Shymlal is eligible according to the instructions referred to in para 2 of Annexure 'A' to officiate in place of Assistant Cashier or Cashier. There was no justification in disallowing Shri Shyamlal to officiate as Assistant Cashier or Cashier with effect from February, 1970. He is entitled to officiate on this post as he did before February, 1970.

Reference is answered accordingly.

UPDESH NARAIN MATHUR, Judge

[No. L. 12012/44/72-LRII]

Central Industrial Tribunal, Rajasthan, Jaipur.

Dated New Delhi, the

S.O. 5035.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Jaipur in the industrial dispute between the employers in relation to the State Bank of Bikaner and Jaipur and their workman which received by the Central Government on the 5th November, 1975.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, RAJASTHAN, JAIPUR

Case No. CIT-4 of 1975

Ref.—Government of India, Ministry of Labour, New Delhi Order No. L. 12012/54/72-LRIII dated 28th April, 1975.

In the Matter of an Industrial Dispute

BETWEEN

Shri S. K. Gautam, Workman

AND

The State Bank of Bikaner & Jaipur, S. M. S. Highway Jaipur.

APPEARANCES :

For the workman—None.
For the management—Shri Tandon.
Date of Award—30-9-75.

AWARD

The Central Government have made the following reference to this Tribunal for adjudication :—

"Whether the action of the management of the State Bank of Bikaner and Jaipur, Jaipur in discharging Shri S. K. Gautam, Clerk-cum-Cashier-cum-Godown-Keeper from service is justified ? If not, to what relief is the said workman entitled ?"

Notice to Shri S. K. Gautam was issued to file his statement of claim, but in-spite of serving of notice on 22-8-75 he did not turn up to file his statement of claim. The case was twice adjourned to enable the workman to appear and file his statement of claim but he did not do so. It appears that he does not want to pursue the reference. The reference is, therefore, rejected and a no dispute award passed.

U. N. MATHUR, Presiding Officer.

[No. L-12012/54/72-LRIII]

S.O. 5036.—In pursuance of section 17 of the ndustrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following Award of the Central Government Industrial Tribunal, Jaipur in respect of a complaint under section 33A of the said Act filed by the All India Central Bank Staff Federation, Ambala Cantt., which was received by Central Government on 1st November 1975.

CENTRAL INDUSTRIAL TRIBUNAL

Complaint No. I. T. 1 of 1974

In the matter of an Industrial Dispute

BETWEEN

All India Central Bank Staff Federation, Ambala Cantt.—Applicant.

Vs.

The Central Bank of India.—Opposite Party. Sansar Chandra Rd., Jaipur.

APPEARANCES :

For the applicant—None.
For the Opposite Party—None.
Date of Award—25-9-75.

AWARD

This is a complaint filed under sec. 33(A) of the Industrial Disputes Act on behalf of the workman of the Central Bank of India. It is alleged that referrence is pending before this tribunal in the matter of determining the seniority of category 'C' and 'E' of Head Cashier. Pending this reference the management has held interviews of senior cashier and as such has flouted the provision of law and contravened section 33 of the Industrial Disputes Act. It is therefore prayed that the management be directed to maintain status que till the referrence is decided. A reply on behalf of the management was filed and a rejoinder to it was filed on 7-2-75 on behalf of the All India Central Bank Staff Federation. The case was then fixed on 2-6-75 for the filing of documents but on that date no body was present on behalf of the staff federation. The case was therefore adjourned to 10-7-75. Then also no body appeared on behalf of the federation. Again on 25-9-75 the federation remained unrepresented. This absence on continuous dates shows that the staff-Federation is not interested in pursuing the complaint. The complaint is rejected and a no dispute award is passed.

[No. L. 12025/1/75/II/A]

UPDESH NARAIN MATHUR, Judge.

S.O. 5037.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Govrnment hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal Chandigarh in the industrial dispute between the employers in relation to the State Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on the 5th November, 1975.

BEFORE JUSTICE H. R. SODHI, PRESIDING OFFICER,

INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL),

CHANDIGARH

Reference No. 35/C of 1975

BETWEEN

The workmen and the State Bank of India, Sundernagar.

APPEARANCES:

Shri Jai Gopal Verma for the workman.
Shri S. P. Sharma for the respondent Bank.

AWARD

The management of the Sate Bank of India, Sundernagar, terminated the services of Shri Ravi Singh, a workman, with effect from 1st July, 1974. The workman felt aggrieved and served a demand notice on the management, challenging the legality of termination of his services, and the Central Government then, being of an opinion that an industrial dispute existed, acted in exercise of the powers conferred by section 7A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, and referred as per Notification No. 12012/143/74/LRIII, dated 21st July, 1975, published in the Gazette of India, the followine matter to this Tribunal for adjudication :—

> "Whether the action of the management of the State Bank of India, Sundernagar, in terminating the services of Shri Ravi Singh with effect from the 1st July, 1974 is legal and justified? If not, to what relief is he entitled?"

2. Notices were issued to the parties and the workmen through the Sate Bank Staff Association, which is registered under the Indian Trade Unions Act, filed a claims statement. No. written statement was filed, and Shri S. P. Sharma, appearing for the management of the Bank, assured the workman at one of the hearings that the latter would be re-employed. The workman wantd actual employment instead of assurance, and Shri S. P. Sharma then made a statment on 4th October, 1975, to the effect that the workman had been ordered to be appointed to the job with effect from the date he joins. Shri Jai Gopal Verma, authorised representative of the workman, accepted the statement as made on behalf of the management, and it was agreed between the parties that the claim would not be pressed. The claim was accordingly dismissed as not pressed, with no orders as to costs.

Dated October 4, 1975.

H. R. SODHI, Presiding Officer.

[No. L. 12012/143/74-LRIII]

R. KUNJITHAPADAM, Under Secy.

S.O. 5038.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Calcutta Port Commissioners and their workmen, which was received by the Central Government on the 6th November, 1975.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT CALCUTTA

PRESENT:

Justice E. K. Moidu, Presiding Officer

Reference No. 14 of 1975

PARTIES:

Employers in relation to the management of Calcutta Port Commissioners.

AND

Their Workmen.

APPEARANCE :

On behalf of Employers—Shri S. M. Banerjee, Labour Adviser, with Shri S. P. Naha, Deputy Labour Adviser and Industrial Relation Officer.

On behalf of Workmen—Shri S. Kar, Jt. General Secretary, National Union of Waterfront Workers.

State : West Bengal Industry : Port & Dock

AWARD

The case arises out of a rference dated 7th February, 1975 made to this Tribunal by the Government of India on the basis of the Order No. L-32012/11/74-P&D/CMT/DIV(A) passed by the Ministry of Labour, by virtue of its power under Clause (d) of Sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (Act 14 of 1947). The question that arises for decision as set out in the referrence is read as follows:

> "Where the action of the management of the Calcutta Por Commissioners in confirming Shri S. K. Khalaque as Lascar from 1st January, 1966 was instified. If not, what should be his date of confirmation and what benefits should he be entitle to ?"

2. The workman concerned in the case is one Khalaque, in whose behalf the National Union of Waterfront Workers filed a written statement contending that Khalaque having been appointed as a Lascar on the Despatch Vessel, "Seva" on the 7th February, 1964 should have been confirmed in the service of Lascar with effect from 7-8-1964 on the basis of a circular which was in force allowing confirmation of all the employees of the Calcutta Port Trust within 6 months of their employment if the appointment was in a permanent vacancy. It is alleged that Khalaque was appointed on 7-2-1964 in a permanent vacancy caused by the resignation of one Nadu Meah. So the Union claims that Khalaque should have been confirmed in the service as Lascar with effect from 7-8-1964. Contrary to the rule and procedure it is alleged that the Calcutta Port Trust confirmed Khalaque

only with effect from 1-1-1966 by an order of the Port Trust dated 19-12-1969. The Union pointed out an instance, where discremination was made in the confirmation of Khalaque when he was confirmed on 1-1-1966, even though he was permanently appointed on 7-2-1962 while another lascar Santi Ranjan Mahattam who was appointed as lascar on 10-5-1964 had been confirmed as lascar on 1-3-1965. According to the Union the confirmation of Khalaque on 1-1-66 is irregular, unjust and discreminatory and therefore Union require this Tribunal to pass an order fixing the date of confirmation of Khalaque as a lascar as on 7-8-1964 with consequent relief.

3. The Port Trust, Calcutta in their written statement contended that Khalaque has no valid claim for confirmation as lascar with effect from 6-8-1964 as his confirmation depended upon the confirmation of the crews holding higher posts in the vessel "Seva" to which he was attached. The Port Trust further stated that there was large scale exodus of Pakistan nationals working in various boats and vessels within the Port during 1964 with the result vacancies of lascars as well as that of higher grade posts in "Seva" were created unexpectedly. So the Port Trust was obliged to promote lascars to higher posts and to recruit others in the vacancy of lascars. It was accordingly Khalaque was appointed on 7-2-64 in a regular vacancy. He has no right to get confirmation as alleged because lascars promoted to higher posts could not be earlier confirmed. However, after the confirmation of the persons in the higher posts, Khalaque and others were also confirmed in the permanent vacancies. According to the Port Trust the promotion was vessel-wise and as such Khalaque could not dispute the confirmation of Shanti Rajan Mahattam who was appointed in the vessel, "Nadia" as lascar on 10-5-1964 while he was confirmed on 1-3-1965 in his own vessel. The Port Trust had also denied in their rejoinder all the allegations which the Union made in the written statement stating that Khalaque has no right whatsoever to claim confirmation with effect from 7-8-1964.

4. The simple question that arises for decision in this reference is whether the confirmation of Khalaque is a lascar on 1-1-1966 is justified in the circumstances of the case or to put it in other way, whether Khalaque's claim that his confirmation shall take effect from 7-8-1964 is sustainable on the facts and circumstances of the case.

5. It is admitted on either side that Khalaque entered the service of the Port Trust as a lascar in a regular vacancy only on 7-2-1964 in the vessel, "Seva". However it is in dispute whether it was a permanent vacancy to which he was appointed on 7-2-1964. If it was a permanent vacancy to which he had been appointed certainly he would take his confirmation from the date of his appointment. But the union did not contend that the date of his cofirmation was to be on 7-2-1964, but on the other hand, they raised the contention that he shall take his confirmation with effect from 7-8-1964 on the basis of a circular of the Port Trust, which is marked in this case as Ext. M-11 dated 2-7-47. The relevant portion of Ext. M-11 reads :

> "Every employee appointed in a temporary capacity against a substantive vacancy should ordinarily be confirmed after six months' service and in any case after the lapse of one year. If for any reason it is found that an employee cannot be confirmed after one year he should be discharged from the service."

6. The above rule is applicable to Khalaque only if it was found that he had been appointed in a substantive vacancy. On this question, there is some evidence in the case. Khalaque himself did not however say that the incumbent of the post who was alleged to have resigned prior to 7-2-1964 was a permanent employee. His word of mouth however was not contraverted by any counter evidence on the opposite side to prove that he was not appointed in a substantive vacancy.

7. It is admitted case that in February 1964 a large number of Pakistan Nationals who were employed in various vessels and boats in the Calcutta Port had left this country and as a result of the exodus many posts in vessels, especially in "Seva" became vacant. The Port authorities were therefore obliged to promote lascars to higher posts like serang, seceaunny, leadsman and cassops and to make new recruitment of lascars in the vacant posts. Many lascars had also fled from this country to other places in February, 1964. The list of persons so promoted and recruited will find a place in the Muster Roll register which is produced in the case. The list maintained for February, 1964 shows that items nos. 7A to 16A were the persons promoted from the rank of lascars and items 17A to 27A were the persons appointed as lascars by direct recruitment or otherwise. They were substituted in the places of items respectively nos. 7 to 16 and nos. 17 to 27 who were the persons alleged to have left the services either in exodus or as persons whose whereabouts were not known. It was found on scrutiny of the above register as well as Ext. M-10 and Ext. M-13 that item nos. 16, 17, 18, 20 and 23 were either persons missing or alleged to have left the service as Paskistan National Items 19A, 21A, 22A, 24A, 25A and 26A were persons who were promoted to the posts higher to that of a lascar. On account of the exodus and promotion large number of vacancies occurred in the rank of lascars, with which we are concerned in the case. Khalaque was appointed on 7-2-1964 as item 23A in place of item 23 who must have left the service either as Pak National or he could have resigned the post on some other ground. Number 23 in the register was one Nadu Meah. It is relevant in this connection to point out that one Nadu Meah's name appears in a cofirmation list issued by the Department of Port Trust. That confirmation list is marked as Ext. M4. Item 23 in Ext. M4 relates to lascar Santi Rajan Mahattam. The commander of Vessel "Nadia" in which Santi Ranjan Mahattam worked as lascar reported to the Port authority to confirm Santi Ranjan Mahattam in the vacancy caused due to the resignation of Nadu Meah as per Ext. M4. Port Trust has no case that Nadu Meah mentioned in Ext. M 4 was persons different from Nadu Meah mentioned as Nadu Meah in the Muster Roll as well as in Ext. M 10 and Ext. M 13. The Muster roll which is provided in the case shows that item 23 in that register was Nadu Meah in whose place Khalaque was said to have been appointed as lascar on 7-2-1964 as item 23A. In the later month item 23 was declared vacant but Khalaque acted in the vacancy continuously. This conflict has not been explained by the Port authorities. The Muster roll shows that the personnel described in it were in the vessel "Seva". So, if Nadu Meah was in "Seva" as per the Muster roll he could not have been in "Nadia" to enable the Port authority to confirm Santi Ranjan Mahattam in the vacancy created by the alleged resignation of Nadu Meah. It is not shown that Nadu Meah had been transferred to "Nadia" giving up his lean in "Seva". Any way, the Port authorities in the written rejoinder dated 26-6-75 stated that, "The two vessels viz., 'Seva' and 'Nadia' are two separate units for the purpose of appointment, seniority and promotion in terms of the award of the Das Gupta Tribunal in Reference No. 1 of 1956. That appointment and confirmation of Shri Shanti Ranjan Mahattam on 'Nadia' are not relevant to the issue under reference". If the confirmation of Santi Ranjan Mahattam was in "Nadia", of course, it will have no relevancy to the matter concerned in the Reference. But that the Port authority did not establish fully whether Nadu Meah was attached to "Seva" or "Nadia". Any way that question will have some importance in favour of Khalaque to establish his case that he was appointed in a specific substantive vacancy.

8. The Port authority has relied upon the list of lascars as in February 1964 when Khalaque was appointed on 7-2-1964 as lascar. They point out Ext. M10 and Ext. M13 for the purpose of showing that Khalaque could not have been confirmed earlier than 1-1-1966 because of the persons holding permanent post of lascar still were awaiting confirmation in the higher posts. As per Ext. M10 list the four persons who acted as seacunny could not be confirmed due to some error on their part. They were (1) Bhim Baboo, (2) Gopal Dey, (3) Madhusudhan Barua and (4) Madhusudhan Raha. Ext. M10 shows that they could not be recommended for confirmation as they were not keeping Anchor Watch either in mooring or whilist down the river. On account of the delay caused in their confirmation it is alleged that the lascars mentioned in Ext. M10 as (1) Khalaque, (2) Oshiar Rahman, (3) Abdul Mazid and (4) Barendra Nath Mondal could not also be confirmed till the above four acting seacunnies were permanently adjusted. Ext. M.13 list shows that the four seacunnys mentioned above were confirmed only with effect from 1-8-1971. If the contention of the Port Trust is

accepted that the confirmation of the four lascars including Khalaque was held up because of the delay in the confirmation of the above 4 seacunnies there was no justification of the confirmation of Khalaque and the 3 other lascars with effect from 1-1-1966 when the four seacunnies were found to have been confirmed only on 1-8-1971. The Port Trust did not explain as to the permanent vacancies which were available on 1-1-1966 for the confirmation of Khalaque and other 3 lascars. The only ground alleged against the confirmation of Khalaque with effect from 7-8-1964 was that the four acting seacunnies blocked his way in as much as they could not be confirmed. That argument has no substance.

9. It is more or less admitted that there was no adverse remark against Khalaque and none was brought to the notice of the Tribunal during the trial of the case. So, even on 20-4-1969 which is the date of Ext. M10 list, Khalaque was liable to be confirmed in spite of the impediment caused by the acting seacunnies. If the four seacunnies were found to be unfit for confirmation the Port Trust could have acted upon Ext. M11 circular and discharged them from service. In that case Khalaque could have been confirmed in spite of the bar caused by the four acting seacunnies at an earlier date. The Port authorities did not place any material before me to ascertain as to the permanent vacancy against which Khalaque was confirmed with effect from 1-1-1966. It is for the Port authorities to prove conclusively that Khalaque had been confirmed as against a particular permanent vacancy. They were not able to do so. On the other hand, the only circumstance on which they relied upon was the report in Ext. M10 list showing that four acting seacunnies blocked the confirmation of Khalaque and 3 other lascars. If that explanation was correct and valid the four seacunnies should have also been confirmed with effect from 1-1-1966 and in these resultant vacancies Khalaque and the 3 other lascars could have also been confirmed with effect from 1-1-1966 That was not the case of the Port Trust. They admit that the four seacunnies in question were confirmed only with effect from 1-8-1971. In that case Khalaque and 3 other lascars could not have been confirmed with effect from 1-1-1966. It appears to me that the Port Trust fixed 1-1-1966 as a national date for confirmation in view of the long and satisfactory period of probation in which Khalaque and the 3 other lascars worked in Vessel "Seva". In the absence of any specific case as to why 1-1-1966 was fixed as the date of confirmation it would be difficult to accept the date of confirmation of Khalaque as valid and legal.

10. Under Ext. M11 circular Khalaque was bound to be confirmed within 6 months of his regular appointment in a substantive vacancy. That a vacancy had arisen in "Seva" on 7-2-1964 admits of no dispute. If Nadu Meah had left India as Pakistan National on 6-4-64 there was bound to be permanent vacancy. The Port Trust did not lead any evidence to show that it was not a permanent vacancy as against evidence of Khalaque. The Muster roll mentioned Nadu Meah as a lascar attached to "Seva" in February 1964. So in the month of February 1964 just at the time of the appointment of Khalaque as lascar in the place of Nadu Meah (see items 23 and 23A in the acquittance roll) they were both employees of "Seva", though Nadu Meah left the service on 6-2-64. The confirmation of Khalaque with effect from 7-8-1964 will not in any manner effect the seniority inter se among the lascars of "Seva". The Port Trust did not show that any other lascars senior to Khalaque had been confirmed prior to 1-1-1966 so that there might be conflict of interest between Khalaque and his senior lascars. The date of appointment in the fourth column in Ext. M13 is the date of original appointment in respect of items 1 to 15 in the list. So Khalaque being appointed on 7-2-1964 he is liable to be confirmed with effect from 7-8-1964. But the confirmation will not in any manner change the inter se seniority among the lascars who are mentioned in Ext M13 list. He will held the present rank among the lascars but the date of his confirmation takes effect from 7-8-1964. However, he will be entitled to all the money benefits if any to be accrued in his favour on account of the confirmation from 7-8-1964 as lascar.

11. When the rule of confirmation is based upon a valid and binding circular which is in force the employees are entitled to take advantage of its provisions. It is for the Port Trust to prove why the provisions of the circular were not applied to the case on hand. The postponement of Khalaque's confirmation on the ground of delay in the confirmation of four seacunnies as per Ext. M10 list is proved to be ineffective and in consistent with the facts in the case. The Port Trust cannot take advantage of that ground for refusing to confirm Khalaque with effect from 7-8-1964 which is the period to be reckoned with under the circular, Ext. M 11. I find accordingly that the action of the Calcutta Port Trust in confirming Khalaque as lascar with effect from 1-1-1966 is not justified.

12. In the result, the reference is answered in favour of the workman, Khalaque. He shall be deemed to have been confirmed as Lascar with effect from 7-8-1964 without any interference of the seniority inter se among the lascars working in the vessel "Seva". He shall be entitled to get the money benefits if any accrued in his favour as a result of the altered date of confirmation.

An award is made in these terms.

E. K. MOIDU, Presiding Officer.

[No. L 32012/11/74-P&D/CMT/DIVA]

NAND LAL, Section Officer (Spl.)

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 1975

बीमा

का. आ. 5039.—केन्द्रीय सरकार, आपात जोखिम (माल) बीमा अधिनियम, 1971 (1971 का 50) की धारा 5 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 5483 तारीख 10 दिसम्बर, 1971 के साथ प्रकाशित आपात जोखिम (माल) बीमा स्कीम में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :—

1. इस स्कीम का नाम आपात जोखिम (माल) बीमा (चतुर्थ संशोधन) स्कीम, 1975 है।

2. आपात जोखिम (माल) बीमा स्कीम में, पैरा 14 में, पैरा (3) के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"4 इस पैरा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति से किसी तिमाही के लिए शास्ति वसूल की जाती है, वहां ऐसी तिमाही के जिसकी बाबत इस प्रकार शास्ति वसूल की गई है, पश्चात्वर्ती किसी तिमाही के लिए प्रीमियम की दर विनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ ऐसे व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसकी पालिसी पश्चात्वर्ती तिमाही के अंत में प्रवृत्त थी।"

[फा. सं. 66 (1) बीमा 3/2/75-1]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

New Delhi, the 10th November, 1975

INSURANCE

S.O. 5039.—In exercise of the powers conferred by subsection (5) of section 5 of the Emergency Risks (Goods) Insurance Act, 1971, (50 of 1971), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Emergency Risks (Goods) Insurance Scheme, published with the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance), No. S.O. 5483 dated the 10th December, 1971, namely :—

1. This scheme may be called the Emergency Risks (Goods) Insurance (Fourth Amendment) Scheme 1975.

2. In the Emergency Risks (Goods) Insurance Scheme in paragraph 14, after sub-paragraph (3), the following sub-paragraph shall be inserted, namely :—

"4. Notwithstanding anything contained in this paragraph, where any penalty is recorvered from any person under sub-section (1) of section 8 for any quarter, such person shall, for the purpose of determining the rate of premium for any quarter subsequent to the quarter for which penalty has been so recovered, be deemed to have a policy in force at the end of the first mentioned quarter."

[F. No. 66(i) Ins. III/2/75-I]

का. आ. 5040.—केन्द्रीय सरकार, आपात जोखिम (उपक्रम) बीमा अधिनियम, 1971 (1971 का 51) की धारा 3 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 5486 तारीख 10 दिसम्बर, 1971 के साथ प्रकाशित आपात जोखिम (उपक्रम) बीमा स्कीम में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :—

1. इस स्कीम का नाम आपात जोखिम (उपक्रम) बीमा (चतुर्थ संशोधन) स्कीम, 1975 है।

2. आपात जोखिम (उपक्रम) बीमा स्कीम, में पैरा 13 में उप-पैरा 3 के पश्चात् निम्नलिखित उप पैरा अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"4 इस पैरा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां पैरा 11 के उप-पैरा (1) के अधीन किसी व्यक्ति से किसी तिमाही के लिए शास्ति वसूल की जाती है, वहां ऐसी तिमाही के, जिसकी बाबत शास्ति इस प्रकार वसूल की गई है, पश्चात्वर्ती किसी तिमाही के लिए प्रीमियम की दर विनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ ऐसे व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसकी पालिसी पश्चातवर्ती तिमाही के अंत में प्रवृत्त थी।"

[फा. सं. 66 (1) बीमा 3/2/75-2]

आर. डी. खानवलकर, अवर सचिव

S.O. 5040.—In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 3 of the Emergency Risks (Undertakings) Insurance Act, 1971, (51 of 1971), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Emergency Risks (Undertakings) Insurance Scheme, published with the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, (Department of Revenue & Insurance), No. S.O. 5486 dated the 10th December, 1971, namely :—

1. This scheme may be called the Emergency Risks (Undertakings) Insurance (Fourth Amendment) Scheme, 1975.

2. In the Emergency Risks (Undertakings) Insurance Scheme, in paragraph 13, after subparagraph (3) the following sub-paragraph shall be inserted, namely :—

"4. Notwithstanding anything contained in this paragraph, where any penalty is recovered from any person under sub-section (1) of section 11 for any quarter, such person shall, for the purpose of determining the rate of premium for any quarter subsequent to the quarter for which penalty has been so recovered, be deemed to have a policy in force at the end of the first mentioned quarter."

[F. No. 66(i) Ins. III/2/75-II]

R. D. KHANWALKAR, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110027
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-6, 1975.